



www.kahaar.in

ISSN (p) : 2394-3912

ISSN (e) : 2395-9369

त्रैमासिक 13(1) जनवरी-मार्च, 2026

Technical articles are peer reviewed

# कह्यार

जनविज्ञान की बहुभाषाई पत्रिका

# KAHAAR

A Multilingual People Science Magazine

भारतीय  
सिनेमा  
पर विशेष  
खण्ड-2



**प्रकाशक**

प्रोफेसर एच.एस. श्रीवास्तव फाउण्डेशन फॉर साइंस एण्ड सोसाइटी, लखनऊ

([www.phssfoundation.org](http://www.phssfoundation.org))

**सह-प्रकाशक**

पृथ्वीपुर अभ्युदय समिति, लखनऊ ([www.prithvipur.org](http://www.prithvipur.org))

"दिनांक 26 दिसम्बर, 2025 को बाराबंकी जिले के देवा क्षेत्र स्थित अकटहिया गांव में **प्रोफेसर एच.एस. श्रीवास्तव फाउंडेशन**, लखनऊ द्वारा एक भव्य और सार्थक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह के अंतर्गत 'ग्रामीण संवाद', कंबल वितरण और कैलेंडर वितरण जैसे सामाजिक सरोकार के कार्य संपन्न हुए, जिसका उद्देश्य भीषण ठंड में जरूरतमंदों की सहायता करना और ग्रामीणों के साथ आत्मीय जुड़ाव बढ़ाना था। कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए फाउंडेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिनमें उपाध्यक्ष **डॉ. आर.डी. त्रिपाठी**, महासचिव **प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह**, एमेरिटस वैज्ञानिक **श्री विनय त्रिपाठी** और प्रशासनिक अधिकारी **श्री कृष्णानंद सिंह** शामिल थे। इन गणमान्य अतिथियों की



उपस्थिति और फाउंडेशन के इन सेवाभावी प्रयासों ने इस आयोजन को अत्यंत सफल और स्मरणीय बना दिया।"





www.kahaar.in

# कहार

जनविज्ञान की बहुभाषाई पत्रिका

त्रैमासिक, 13(1) जनवरी-मार्च, 2026

A Multilingual People Science Magazine

## प्रधान संपादक

प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह, लखनऊ

**अतिथि संपादक (विशेष खण्ड)**

प्रोफेसर गोविन्द जी पाण्डेय, लखनऊ

**कार्यकारी सम्पादक**

श्री कृष्णानन्द सिंह, लखनऊ

**सह-सम्पादक**

डॉ. बसंत माहेश्वरी, पेनरिथ, ऑस्ट्रेलिया

डॉ. रुद्र प्रताप सिंह, आजमगढ़

डॉ. निहारिका शंकर, नोएडा

डॉ. अर्चना सिंह, ब्रैनफोर्ड (यू.एस.ए.)

श्री आकाश वर्मा, लखनऊ

श्री सुनीत कुमार यादव, मऊ

श्री शुभम अभिषेक, धनवाद

श्री पवन कुमार, लखनऊ

**सम्पादक मण्डल**

प्रोफेसर सुनीता मिश्रा, लखनऊ

प्रोफेसर राकेश सिंह सेंगर, मेरठ

श्री नरसिंह, देवरिया

श्री हरीशचन्द्र दहिया, गुडगाँव

डॉ. संजय सिंह, झांसी

श्री अनिल जैन, नई दिल्ली

श्री अनिल सिंह, लखनऊ

डॉ. मनोज गर्ग, लखनऊ

डॉ. पीयूष गोयल, नई दिल्ली

श्री मेराज उद्दीन सिद्दीकी, लखनऊ

डॉ. अनुज कुमार सक्सेना, सीतापुर

**सलाहकार मण्डल**

प्रोफेसर सरोज कान्त बारिक, लखनऊ

डॉ. प्रफुल्ल वी. साने, जलगाँव

डॉ. राम स्नेही द्विवेदी, लखनऊ

डॉ. राजेन्द्र सिंह जलपुरुष, भीखमपुरा

डॉ. वेदप्रकाश पाण्डेय, बालापार, गोरखपुर

डॉ. रुद्रदेव त्रिपाठी, लखनऊ

प्रोफेसर एन. रघुराम, दिल्ली

डॉ. योगेश शर्मा, लखनऊ

डॉ. सी. एम. नौटियाल, लखनऊ

डॉ. शक्ति के. प्रभुजी, गोरखपुर

प्रोफेसर शिल्पी वर्मा, लखनऊ

डॉ. सुमन कुमार सिन्हा, गोरखपुर

डॉ. धीरज कुमार सिंह, नोएडा

प्रोफेसर रणवीर दहिया, रोहतक

डॉ. सुधाकर तिवारी, कुशीनगर

डॉ. मनोज कुमार पटैरिया, नई दिल्ली

डॉ. सिराज वजीह, गोरखपुर

प्रोफेसर मालविका श्रीवास्तव, गोरखपुर

श्री उपेन्द्र प्रताप राव, दुदही

श्रीमती मधु, करमेल, यू.एस.ए.

ई. तरुण सेंगर, कारमेल, (यू.एस.ए.)

डॉ. मनीष सेंगर, रोहतक

डॉ. पूनम अहलावत, चण्डीगढ़

## आवरण फोटो

श्री प्रकाशवीर सिंह, लखनऊ

**प्रबंध-संपादक**

श्री अंचल जैन, लखनऊ

**सोशल मीडिया**

श्री रणजीत शर्मा, लखनऊ

श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह, लखनऊ

**टाइप सेटिंग और प्रोडक्शन**

श्री जावेद अहमद, लखनऊ

## घोषणा

लेखक के विचार से कहार टीम का सहमत होना जरूरी नहीं हैं। किसी रचना में उल्लेखित तथ्यात्मक भूल के लिए 'कहार' की टीम जिम्मेदार नहीं होगी।

**कार्यालय :** 04, पहली मंज़िल, एल्डिको एक्सप्रेस प्लाजा, शहीद पथ, उत्तरेठिया, रायबरेली रोड, लखनऊ-226 025, भारत

ईमेल: kahaarmagazine@gmail.com/

dr. ranapratap.59@gmail.com

## सदस्यता / Subscription\* (Print Copy)

एक प्रति रुपये 250/- वार्षिक (4 प्रति) रुपये 1000/-

वार्षिक (10 प्रति) रुपये 9000/- (100 प्रति) रुपये 22000/-

\*(डाक व्यय सम्मिलित)

## विज्ञापन (Advertisements)

Rs. 10,000/- Full Page (B/W) Rs. 6,000/- Half Page (B/W)

Rs. 15,000/- Full Page (Color) Back Cover

सहयोग राशि 'प्रोफेसर एच.एस. श्रीवास्तव फाउण्डेशन फॉर साइंस एण्ड

सोसायटी : लखनऊ (Prof. H.S. Srivastava Foundation for

Science and Society, Lucknow) के नाम भेजे।

खाता संख्या 2900101002506, केनरा बैंक, बी.बी.ए., विश्वविद्यालय,

लखनऊ IFSC: CNRB0002900

## लेखकों के लिए

वैचारिक रचनाओं में आवश्यक संदर्भ भी दें, एवम् इन संदर्भों का विस्तार रचना के अंत में प्रस्तुत करें। अंग्रेजी रचनाओं का हिन्दी तथा हिन्दी सहित अन्य भाषाओं की रचनाओं का अंग्रेजी या हिन्दी में सारांश दें। मौलिक रचनाओं के साथ रचना के स्वलिखित, मौलिक एवम् अप्रकाशित होने का प्रमाण पत्र दें। लेखक पासपोर्ट साइज फोटो भी भेजें। रचनाएँ English के Times New Roman (12 Point) और हिन्दी में मंगल/यूनिकोड में कन्वर्ट कर के भेजें। फोटो या रेखाचित्र अलग से और चित्र संख्या के साथ भेजे।

कहार एक पारम्परिक मनुष्य वाहक के लिए प्राचीन देशज सम्बोधन है। कहार की तरह ही यह पत्रिका जानकारियों एवं लोगो के बीच सेतु बनने की कोशिश कर रहा है।

# अनुक्रमणिका (Content)

क्र.सं. / Sl. No.	विषय / Topics	लेखक / Author	पृष्ठ / Page
1.	अरावली का पुनः नया संकट – प्रकृति और संस्कृति का विध्वंस है	जलपुरुष राजेन्द्र सिंह	1-2
2.	सृष्टि की उत्पत्ति	कृष्णानंद सिंह एवं राणा प्रताप सिंह	3-5
3.	कर्नाटक में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर महिला किरदारों के चरित्र का अध्ययन	निसर्ग सी ए' एवं अरविंद कुमार'	6-14
4.	उच्चतम न्यायालय, भारत एवं कोप30 बेलेम, ब्राजील का पर्यावरणीय ऐतिहासिक निर्णय '20 नवम्बर 2025'	जलपुरुष राजेन्द्र सिंह	15-16
5.	भू-सांस्कृतिक मानचित्रण प्रमाणीकरण संगोष्ठी	पारस प्रताप सिंह	17-19
6.	“अमृत काल में भोजपुरी भाषा का विकास एवं चुनौतियां”	नरसिंह	20-22
7.	“गधस्य गर्वः च अधिकारीस्य बोधः”	गणेश बाजपेई	23
8.	Development of Banana Plantlets through Micro propagation Techniques	Uttam Kumar, Dr. R. S. Sengar, Dr. Nidhi Singh and Garima Sharma	24-26
9.	Hydroponics: Boon for Urban Farming	Nidhi Singh, R. S. Sengar, Aditya Das, Garima Sharma and Sangam	27-29
10.	Indian Soil Health: A Mini Review	Shivam Singh, Ankit Tiwari, Jagannath Pathak, Mahendra Pratap Singh, Satendra Kumar	30-31
11.	Organic Farming and Its Role in Sustainable Agriculture: A Short Review	Devesh Kumar Shukla and Sushmitha Baskar	32-37
12.	Regulation and Censorship of OTT Platforms: Examining the Regulatory Landscape and Content Censorship Challenges Globally	Abhishek Kumar and Dr. Kaushal Tripathi	38-42
13.	Religious Portrayals in Salim-Javed's Screenplay Writing: An Examination of Implicit and Explicit Narratives	Abhishek Rajput	43-55
14.	COP30, Belém, Brazil	Jalpurush Rajendar Singh	56-58
15.	The Poles and Our Planet: A Story of Ice, Life, and Climate Change	Jaswant Singh	59-60



## फैलते शहर और जहरीली सर्दियां

उस पुरानी बोध—कथा का नायक वह लकड़हारा भी मनुष्य ही था, जो जिस डाल पर बैठा था, उसी को काट रहा था। तबसे अपने भीतरी और बाहरी विकास की यात्रा में काफी आगे निकल आने पर भी हमारी मानवीय चेतना में वह लकड़हारा कहीं छिप कर बैठा हुआ है, और हम देख नहीं पा रहे हैं। हम उसे इसलिए देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सोचना, विमर्श करना, स्थितियों और घटनाओं का विश्लेषण करना और परिणामों को बदलने के लिए विचार करना, हम अब वैचारिक बोझ मानने लगे हैं। हम चाहते हैं, कि कोई और हमारे लिए सोचे, और अपने काम की चीज हम उसी से खरीद लें। बने बनाये विचार और वस्तुएं बेचने वाले दुनिया भर में तैयार बैठे हैं, और अधिक से अधिक खरीदारों का इंतजार कर रहे हैं। तकनीकी विकास ने मशीनों को मनुष्य और मनुष्यों को मशीन बनाना शुरू कर दिया है, और हम सब हर नए वर्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उत्सव जोर-शोर से मनाने लगे हैं। विचार विहीनता और उत्सव धर्मिता आज का नया युग धर्म बनता जा रहा है।

विकास के लुभावने सपने दिखा कर समय हमें नए सिरे से मनुष्य से अमनुष्य बनाता जा रहा है, और हम इस आहट को सुन ही नहीं पा रहे हैं। दुनिया भर के अमीर लोग सस्ते श्रम और मानवीय मूल्यों के दबाव से बचने के लिए, मनुष्य के बनाये रोबोट को मनुष्य की जगह ले आना चाहते हैं। इस नए बाजार—तन्त्र और वैश्विक अर्थ शास्त्र को कुछ लोगों की आवश्यकता, कुछ विशेष प्रकार के विशेषज्ञों के रूप में तो है, पर शेष बाकी सब लोगों की आवश्यकता, उन्हें बस एक उपभोक्ता और ग्राहक के रूप में है। आज के इस समय को फिर से थोड़े से अत्यंत अमीर लोग और कथित तौर पर बुद्धिमान लोग अपनी सनक और इच्छा से चलाना चाहते हैं।

वे चाहते हैं, कि जब जिस चीज पर चाहें, कब्जा कर लें, और उसे अपने न्याय के पैमाने से न्यायोचित साबित कर दें। वे ऐसा ही कर रहे हैं। और बाकी सब अपनी सुविधाओं को बचाए रखने के लिए चुप हैं। दुनिया भर में देशों के बीच, धर्मों के बीच, वर्गों के बीच, जातियों के बीच, और लोगों के बीच संघर्ष और युद्ध बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई दूसरे पर अपना वर्चस्व चाहता है, और कोई भी दूसरे के वर्चस्व में नहीं रहना चाहता। सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं टूट रही हैं, लोगों का मन टूट रहा है और जीवन अव्यवस्थित होता जा रहा है। क्या यही विकास है? इसी लिए प्रकृति ने पशुओं में से कुछ को बदल कर मनुष्य बनाया था? यह असुविधा जनक सवाल कोई किसी से पूछना नहीं चाहता। दूसरों को कोई अनावश्यक रूप से नाराज नहीं करना चाहता। सुविधाएँ तलाशते—तलाशते हमने अपने लिए और दूसरों के लिए नैतिकता और मानवीयता के पैमाने अलग—अलग तलाशने शुरू कर दिए हैं। अपना सब कुछ भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हो चलेगा, पर दूसरों का निर्मल और नैतिक होना चाहिए। यह हमारा समकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक चरित्र बनता जा रहा है। यह मनुष्य का एक जैविक प्रजाति और सामाजिक—सांस्कृतिक व्यवस्था वाले जीव के रूप में बड़ा अवमूल्यन है।

हमें विकास तो चाहिए पर विकास सिर्फ संरचनाओं और वस्तुओं का निर्माण नहीं होता। विकास मनुष्य को भीतरी तौर पर अधिक विचारशील तथा मानवीय बनाना भी है। विकास पृथ्वी—तंत्र और सामाजिक—तंत्र के नित्य विकसित हो रही पारिस्थिकी में व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समूह निर्माण, राष्ट्र निर्माण और विश्व निर्माण के लिए एक समावेशी अनुकूलन विकसित करना भी है। विकास पशुता पूर्ण संघर्षों को सीमित करते जाने और सहजीवी, समावेशी तथा सहकारी मानव मन का निर्माण करना भी है।

जीवन में सेहत, शांति और खुशियों के लिए अच्छी हवा, शुद्ध पानी, स्वच्छ ऊर्जा और विष विहीन पोषक भोजन की आवश्यकता किसी भी अन्य चीज के पहले है, और विकास के वर्तमान स्वरूप में वही अधिक खराब होता जा रहा है। हमें इसे बचाने के लिए हरित चक्रीय विकास के संयुक्त राष्ट्र संघ के सुझाये मॉडल पर पूरी गंभीरता और विश्वसनीयता के साथ काम करना होगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें लगेगा, कि हमारे पास जनसँख्या के अनुपात में जमीन कम है। तो ऐसे में हमें नवीन नवाचारी तरीके ढूँढने होंगे। अपने वन क्षेत्रों को बढ़ा कर हम पर्यावरण की कई समस्याएं कम कर सकते हैं। हमारे पास नए वन लगाने के लिए जगह कम है, तो पुराने वनों के क्षरित हो चुके क्षेत्रों को हमें अधिक घना करना होगा। आबादी के आस—पास छोटे—छोटे सघन वन क्षेत्र विकसित करने होंगे, और जंगली जानवरों के लिए बड़े वनों के भीतर सघन और सुरक्षित वन क्षेत्र बनाने होंगे।

हमें कम जमीन में भी वनस्पतियों, फसलों, सब्जियों, फूलों और फलों को जमीन के साथ—साथ वायु में उगाने की तकनीकें और क्षमता पैदा करनी होगी। अपने शहरों, कस्बों और गाँवों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने के लिए शहरों के बाहर उपग्रह शहरों, उप नगरों और गाँवों के ढांचागत विकास की परिकल्पना को सही मायने में जमीन पर उतारना होगा। हमारे उपग्रह नगर, बड़े शहरों में बेतरतीबी से समाते जा रहे हैं। सरकारी स्तर पर वन का, उद्योग का, विकास का और व्यवस्था का विशाल बहुआयामी अधिकार प्राप्त ढांचा यह सब क्यों नहीं करता, कोई पूछना नहीं चाहता, क्योंकि विफलताओं के लिए किसी की जवाबदेही तय नहीं है। शहरों की धूल, धुंध और जहरीली हवा को घटाने और रोकने के लिए हमें समाज और शासन—तंत्र के भीतर और बाहर के जालों, धूल और धुंध की सफाई करनी होगी। सभी जो इस व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और नागरिक—तंत्र के हिस्से हैं, अपनी मानवीय चेतना और भीतरी प्रज्ञा को जगा लें, तो शायद अगले वर्ष यह धुंध थोड़ी कम हो जाए।

राणा प्रताप

(राणा प्रताप सिंह)



## Editorial

## Sprawling Cities and Toxic Winters



The protagonist of that old parable was a woodcutter, a human being, who was cutting off the very branch, he was sitting on. Even after having progressed so far in our journey of inner and outer development, that woodcutter still lurks somewhere within our human consciousness, and we are unable to see him. We cannot see him, because we have begun to consider thinking, deliberating, analysing the prevailing situations and events, and considering ways to change outcomes as a burden. We want someone else to think for us, and we want to buy ready-made solutions from them. Those who sell ready-made ideas and products are waiting all over the world, eager for more and more buyers. Technological development has begun to turn machines into humans and humans into machines, and we are celebrating artificial intelligence with great fanfare. Thoughtlessness and a celebratory attitude are becoming the new religion of our age.

By showing us the alluring dreams of development, time is once again transforming humans into something less than human, and we are unable to hear this warning. Wealthy people around the world, to escape the pressure of cheap labour and human values, want to replace humans with robots created by humans. This new market system and global economy require some people as specialists of a certain kind, but the rest of the people are needed only as consumers and customers. Today, a few extremely wealthy and supposedly intelligent people want to run the world according to their whims and desires.

They want to seize whatever they want, whenever they want, and justify it according to their own standards of justice. They are doing just that, and everyone else remains silent to protect their own comforts. Conflicts and wars are increasing between the countries, religions, classes, castes, and people all over the world because everyone wants to dominate others. Is this what we call development? Is this why nature transformed some animals into humans? This inconvenient question is one that no one wants to ask. No one wants to unnecessarily offend others. In our pursuit of convenience, we have begun to create different standards of morality and humanity for ourselves and others. Even if we are neck-deep in corruption, we don't see it in ourselves, but we expect others to be pure and moral. This is becoming our social and cultural character. This is a great devaluation of humanity as a biological species and a socio-cultural heritage.

We need development, but development is not just the construction of structures and usable products. Development also means making humans more thoughtful and humane internally. Development is also about developing inclusive adaptability for individual development, family development, group development, national development, and global development within the constantly evolving ecology of the earth system and social system. Development is also about limiting animalistic conflicts and building a symbiotic, inclusive, and cooperative human mind.

For health, peace, and happiness in life, clean air, pure water, clean energy, and toxin-free nutritious food are needed before anything else, and in the current form of development, these are becoming increasingly scarce. To prevent this, we must work with complete seriousness and credibility on the green circular development model suggested by the United Nations. From the Indian perspective, we will find that we have less land in proportion to our population. So, in such a situation, we will have to find innovative methods. By increasing forest cover, we can reduce many environmental problems. We have less space to plant new forests, so we will have to make the degraded areas of old forests denser. We will have to develop small, dense forest areas near populated areas and create dense and safe forest areas within large forests for wild animals.

We will have to develop techniques and capabilities to grow herbs, crops, vegetables, flowers, and fruits in less land, both on the ground and in the air. Our cities, towns, and villages need to be better organized, and the concept of satellite cities, suburbs, and villages must be truly implemented. Our satellite towns are being haphazardly absorbed into the larger cities. No one wants to ask why the vast, multi-faceted power structure of forestry, industry, development, and administration isn't addressing all of this, because no one is held accountable for the failures. To reduce and prevent the dust, smog, and toxic air in our cities, we need to clean up the webs of corruption and inefficiency within and outside of society and the governance system. If all those who are part of this system, economy, and civic structure awaken their human consciousness and inner wisdom, perhaps the smog will be a little less next year.

*Rana Pratap*

(Rana Pratap Singh)



## अरावली का नया संकट – प्रकृति और संस्कृति का विध्वंस है

जलपुरुष राजेन्द्र सिंह

अरावली क्षेत्र में 1980 के दशक में वैध-अवैध 28000 खदानें चालू थी। इनको बंद कराने का बीड़ा तरुण भारत संघ ने वर्ष 1988 में उठाया था। 1993 में अरावली की धरती पर सभी खदाने एक बार तो बंद करा दी थी। यह काम 1990 के दशहरे विजयदशमी पर सरिस्का का खनन रुकने से इसकी शुरुआत हुई थी।

महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1993 को हिम्मतनगर गुजरात से अरावली चेतना यात्रा द्वारा खनन बंद कराते हुए "अरावली का सिंहनाद" दिल्ली संसद तक 22 नवंबर 1993 को पहुंचा था। तब अरावली एक बार तो खनन मुक्त हो गई था। वर्ष 1994 में अरावली के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को खनन बंद करने की कार्यवाही हेतु अरावली संरक्षण समितियां गठित करके, उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट देने वाला तंत्र बनाया गया था।

उस समय लगता था कि अब अरावली बच गई है और आगे के लिए अरावली को बचाने वाली व्यवस्था भी अब बन गई है। वर्ष 1996 आते-आते मैं निश्चित हो गया था और मान लिया था कि अब मेरा संकल्प पूरा हो गया है। लेकिन 10-15 वर्ष बाद ही मुझे देखने में आया कि खनन संगठन ज्यादा दल-बल के साथ संगठित होकर खनन खुलवाने में जुट रहा है। तब बहुत से ख्याली मीणा जैसे युवा अरावली बचाने के लिए तैयार हो गए थे। पूरी अरावली

में बहुत से लोग स्वयं सामने आकर अरावली बचाने में जुट गए थे। मन को उस समय बहुत समाधान और संतोष था। मुझे मालूम नहीं था कि, मेरे सामने ही संपूर्ण अरावली में वैध और अवैध खनन शुरू होगा और इस खनन को सरकारों व खनन उद्योग पतियों के गठजोड़ को उच्चतम न्यायालय भी मोहर लगा देगा

मैंने जब तक उच्चतम न्यायालय का निर्णय आते ही पढ़ा, तब तक सरकारी एफिडेविट, सरकार की रिपोर्ट, मंत्रालय की कार्रवाई नहीं देखी थी। तब लगता था कि उच्चतम न्यायालय ने चारों राज्यों की अरावली का एक जैसी कानून व्यवस्था देने की मनसा से ऐसा किया होगा।

100 मीटर की ऊंचाई की परिभाषा को एक मानक माना होगा। जैसे हम अपनी पढ़ाई में कोई एक आधार बिंदु मानकर गणनाएं करते हैं, वैसे गणना के लिए यह रखा होगा। विस्तार से थू..प वन सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (जीएसआई) टेक्निकल सबकमेटी की रिपोर्ट (टीएससी) देखकर आंखें खुली कि यह संपूर्ण करवाई तो खनन उद्योग के सतत विकास के नाम पर हमारी प्राचीनतम विरासत अरावली के लिए नया संकट पैदा कर रही है।

अरावली का 20 मीटर तक की ऊंचाई वाला क्षेत्रफल 107494 वर्ग किमी है। 20 मीटर से ऊपर वाला क्षेत्र 12081 वर्ग किमी, 40 मीटर से ऊपर

वाला क्षेत्र 5009 वर्ग किमी, 60 मीटर वाला क्षेत्र 2656 वर्ग किमी है, 80 मीटर वाला क्षेत्र 1594 वर्ग किलोमीटर, 100 मीटर वाला क्षेत्र 1048 वर्ग किलोमीटर, 100 मीटर से ऊपर वाला क्षेत्र केवल 8.7 प्रतिशत क्षेत्रफल है।

अब भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय अपनी ईमानदारी से काम करेगा तो कुल 8.7 प्रतिशत अरावली क्षेत्र ही बचेगा। यह अरावली वासियों को स्वीकार नहीं है। अरावली क्षेत्र के आदिवासी तो ये स्वीकार नहीं करते हैं। अरावली में आदिवासियों के मुहासे, वाडे, घर, घेर तो 100 मीटर से नीचे की भूमि पर ही है। वहां से भी ये उजाड़ना नहीं चाहते। खनन की बीमारियों से भी बचकर इससे दूर रहना ही इनका स्वभाव है। उनकी अपनी संस्कृति और प्रकृति है। उनका आदिज्ञान तो प्रकृति से संस्कृति से जोड़ने वाला है।

अरावली की अपनी प्रकृति और संस्कृति तो दुनिया में सर्वोपरि है। अरावली में खनन उद्योग यहां की संस्कृति और प्रकृति के विरुद्ध है। इसी बात को समझकर 45 वर्ष पूर्व अरावली बचाने का काम जयपुर से शुरू हुआ था। अब रिपोर्ट को पढ़ने, देखने, समझने से समझ आया कि, जयपुर से ही खनन संगठन की पहल को उच्चतम न्यायालय ने मान्यता दे दी है। इन्हीं की बातें ही इस रिपोर्ट में झलकती हैं।

अरावली को बचाने वालों से आज तक कभी भी कोई रिपोर्ट तैयार करने वाला नहीं मिला। जबकि बचाने वाले

जयपुर, अलवर में ही अधिकतर रहते हैं; मुझे भी आज तक अरावली के विषय पर बात करने वाला कोई सरकारी अधिकारी नहीं मिला। मुझसे कोई बात करता तो मैं भी इस कार्रवाई में अरावली की सच्ची जानकारी देता और हम भी अरावली का सर्वमान्य सत्य बताते। 100 मीटर ऊंचाई वाली परिभाषा तो केवल खनन उद्योगों की बनाई परिभाषा है। यह परिभाषा किसी भू वैज्ञानिक, पर्यावरण, प्रकृति, संस्कृत, भू-संस्कृति को समझने वाला नहीं स्वीकारता है।

भारत सरकार व चारों राज्यों (गुजरात, राजस्थान हरियाणा, दिल्ली)की सरकार को अरावली की

परिभाषा पर पुनर्विचार करना चाहिए। अन्यथा सरकारों की बड़ी बदनामी होगी। परिभाषा का यह विवाद उच्चतम न्यायालय के सिर पर नहीं डालना चाहिए। उच्चतम न्यायालय तो हमारे लोकतंत्र का सर्वोपरि अंग माना जाता है; यह तो सरकार से भी ऊपर है। लेकिन न्यायपालिका आजकल जो भी न्याय करती है वे ज्यादातर एकतरफा समझौता जैसा दिखाई देता है। इसलिए आरवाली की परिभाषा वाला समझौता अरावली का न्याय नहीं है और अब हमें यह स्वीकार भी नहीं है क्योंकि इसमें अरावली पर्वतमाला के पक्ष को ठीक से स्थान नहीं मिला। इसलिए इस

निर्णय ने भारत की संस्कृति –प्रकृति के अनुरूप अरावली पर्वतमाला को न्याय नहीं मिला।

हम हमारी सम्मनीय न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना करते हैं। अरावली भारत की प्राचीनतम विरासत है। इसे भारतीय संस्कृति और प्रकृति योग का उच्चतम उदाहरण मानकर अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। वही से भारतीय विरासत अरावली को बचाने की पहल होगी।

अधिक जानकारी के लिए  
संपर्क करें

पारस प्रताप सिंह-9009739338



## सृष्टि की उत्पत्ति

कृष्णानंद सिंह एवं राणा प्रताप सिंह

### सार

ब्रह्मांड की अपनी एक अलौकिक सत्ता हैं। अलौकिक इस माने में भी मनुष्य उसे पूरी तरह नहीं जनता समझता। अपने कौतूहल गणनाओं और अध्ययनों से उसने अनेक परिकल्पनाएं की हैं, कुछ प्रयोग भी। पर पृथ्वी-तंत्र को एक प्रजाति के रूप में मनुष्य की यह विलक्षण तलाश जारी है। आइए एस्की कुछ बातों को समझते का प्रयास करें।

हम सब पृथ्वी के वासी मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े-मकोड़े, पेड़ और सूक्ष्मजीव एक विशाल और अंतहीन अंतरिक्ष के हिस्से हैं। आसमान के उस रिक्त स्थान को आकाश कहते हैं जिसमें ग्रह, तारे, गैलेक्सियों और अन्य सितारों का संसार होता है। ये सब मिलकर एक यानहीन और अज्ञानी संरचना बनाते हैं, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। और सबका साझा लोक ही अंतरिक्ष है।

हम सब जीव और मनुष्य भी इस पृथ्वी पर ही कहीं रहते हैं, और हम सबकी दुनिया आमतौर पर पृथ्वी तक ही सीमित रहती है, जब तक हम किसी अभियान के अंतरिक्ष यात्री न बने।

सृष्टि की उत्पत्ति आज भी एक बड़ा रहस्य है। सृष्टि के पहले इस रिक्त स्थान के भीतर क्या था? कोई निश्चय पूर्वक कह नहीं सकता। इसकी रचना किसने, कब और क्यों की? ऐसा क्या हुआ होगा, जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ? अनेकों अनसुलझे प्रश्न हैं जिनका सर्व स्वीकृत उत्तर किसी के पास नहीं है। कुछ सिद्धांत हैं, जो कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं, पर कुछ नये

प्रश्न फिर से खड़े हो जाते हैं। सब की जिज्ञासा शांत करने वाला एक सर्व स्वीकार्य सिद्धांत अभी तक सामने नहीं आया है। फिर भी, सृष्टि की उत्पत्ति का सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, महाविस्फोट सिद्धांत (The Big Bang Theory)।

1929 में एडवीन हबल ने एक आश्चर्य जनक खोज की, उन्होंने पाया की अंतरिक्ष में आप किसी भी दिशा में देखें, आकाशगंगाये और अन्य आकाशीय पिंड तेजी से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। अर्थात् ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। इसका मतलब है, कि पूर्व में ब्रह्मांड के सभी पदार्थ आज की तुलना में एक दूसरे से और भी पास रहे होंगे। और एक समय ऐसा रहा होगा जब सभी आकाशीय पिंड कहीं एक ही स्थान पर रहे होंगे, परंतु इस बात पर विश्वास करना बहुत ही कठिन है, कि ऐसा ही हुआ होगा।

ऐसा माना जाता है कि शायद 10

से 15 अरब साल पूर्व, ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे से एकदम पास- पास थे। सारा ब्रह्मांड संभवतः एक बिन्दु के आकार में था। यह बिन्दु अत्यधिक घनत्व (infinite density) का, अत्यंत छोटा बिन्दु (infinitesimally small) था। ब्रह्मांड का यह बिन्दु रूप अपने अत्यधिक घनत्व के कारण अत्यंत गर्म (infinitely hot) रहा होगा। ऐसा मानते हैं, कि किसी अज्ञात कारण से अचानक ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ। ऐसी अवधारणा है कि एक महा विस्फोट के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ और इस विस्फोट की ऊर्जा से पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे।

माना जाता है, कि महा विस्फोट के 10-43 सेकंड के बाद, अत्यधिक ऊर्जा के रूप में फोटॉन कणों का ही अस्तित्व था तत्पश्चात क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, एन्टी इलेक्ट्रॉन (पोजीट्रॉन) जैसे मूलभूत कणों का निर्माण हुआ। इसके तुरंत बाद लगभग 10-34 सेकंड



चित्र-1 सृष्टि के सृजन की एक परिकल्पना

के पश्चात, क्लार्क और एन्टी क्लार्क जैसे कणों का ज्यादा मात्रा में निर्माण हुआ। इस तरह ब्रह्मांड के बनाने में कण और उनके प्रति-कण दोनों का निर्माण हो रहा था, इसमें से कुछ एक कण और उनके प्रति-कण एक दूसरे से टकरा कर खत्म भी हो रहे थे। इस शुरुआती दौर में समय ब्रह्मांड का आकार एक संतरे के आकार अनुमानित किया जाता है।

ऐसी परिकल्पना है कि 10-10 सेकंड के पश्चात, एन्टी क्लार्क से टकरा कर पूर्ण रूप से खत्म हो चुके थे, और इस टकराव से फोटॉन का निर्माण हो रहा था। इसी समय फोटॉन के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी निर्माण हुआ। ऐसा अनुमान है कि इस विस्फोट के मात्र 1 सेकंड के पश्चात, जब तापमान 10 अरब डिग्री सेल्सियस था, ब्रह्मांड ने आकार लेना शुरू किया। उस समय ब्रह्मांड में ज्यादातर फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो (3) और उनके प्रति-कणों के साथ में कुछ मात्रा में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन भी बन रहे थे। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने एक दूसरे के साथ मिल कर तत्वों (elements) का केन्द्र (nuclei) बनाना शुरू किया जिसे आज हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और ड्यूटेरियम आदि के नाम से जानते हैं। जब महा विस्फोट के बाद तीन मिनट बीत चुके थे, तापमान गिरकर 1 अरब डिग्री सेल्सियस हो चुका था, उसी अवधि में तत्व और ब्रह्मांडीय विकिरण (cosmic radiation) का निर्माण हुआ। यह विकिरण आज भी मौजूद है और इसे महसूस किया जा सकता है।

आगे बढ़ने पर 300,000 वर्ष के पश्चात, के बाद विस्तार करता हुआ ब्रह्मांड अभी भी आज के ब्रह्मांड से मेल नहीं खाता था। तत्व और विकिरण एक दूसरे से अलग होना शुरू हो चुके थे। इसी समय इलेक्ट्रॉन, केन्द्रक के साथ में मिल कर परमाणु का निर्माण कर रहे थे। परमाणु मिलकर अणु बना रहे थे। इस के 1 अरब वर्ष पश्चात, ब्रह्मांड का

एक निश्चित सा आकार बनना शुरू हुआ था। इसी समय क्वासर, प्रोटोगैलेक्सी (आकाशगंगा का प्रारंभिक रूप), तारों का जन्म होने लगा था। तारे हाइड्रोजन जलाकर भारी तत्वों का निर्माण कर रहे थे। आज महा विस्फोट के लगभग 14 अरब साल पश्चात तारों के साथ उनका सौर मंडल बन चुका है। परमाणु मिलकर कठिन अणु बना चुके हैं। जिसमें कुछ कठिन अणु उदाहरण अमीनो अम्ल के जीवन के मूलभूत माने जाते हैं।

ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है, और विस्तार की गति बढ़ती जा रही है। विस्तार होते हुये ब्रह्मांड की तुलना आप एक गुब्बारे से कर सकते हैं, जिस तरह गुब्बारे को फुलाने पर उसकी सतह पर स्थित बिन्दु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं उसी तरह आकाशगंगाएँ एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह विस्तार कुछ इस तरह से हो रहा है जिसका कोई केन्द्र नहीं है, हर आकाश गंगा दूसरी आकाशगंगा से दूर जा रही है, ऐसा यह बिग बैंग सिद्धांत मानता है।

इसके अलावा सृष्टि के निर्माण के वैकल्पिक सिद्धांत भी मौजूद हैं। इस सिद्धांत के अनुसार काल और अंतरिक्ष एक साथ महा विस्फोट के साथ प्रारंभ नहीं हुये थे। इसकी मान्यता है, कि काल अनादि है, इसका ना तो आदि है ना अंत। आकाशगंगाओं (Galaxies) और आकाशीय पिंडों का समूह अंतरिक्ष में एक दूसरे से दूर होता ही रहता है।

महा विस्फोट के सिद्धांत के अनुसार आकाशीय पिण्डों की एक दूसरे से दूर जाने की गति महा विस्फोट के बाद से आज बहुत ही कम है। यह सिद्धांत कहता है, कि भविष्य में आकाशीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण इस विस्तार की गति पर रोक लगाने में सक्षम हो जायेगा। इसी समय विपरीत प्रक्रिया का प्रारंभ होगा अर्थात संकुचन का। सभी आकाशीय पिंड एक दूसरे के नजदीक और नजदीक आते जायेंगे

और अंत में एक बिन्दु के रूप में संकुचित हो जायेंगे। इसी पल एक और महा विस्फोट होगा और एक नया ब्रह्मांड बनेगा, विस्तार की प्रक्रिया एक बार और प्रारंभ होगी। यह प्रक्रिया अनादि काल से चल रही है। हमारा विश्व इस विस्तार और संकुचन की प्रक्रिया में बने अनेकों विश्व में से एक है। इसके पहले भी अनेकों विश्व बने हैं और भविष्य में भी बनते रहेंगे। ब्रह्मांड के संकुचित होकर एक बिन्दु में बन जाने की प्रक्रिया को महा संकुचन (The Big Crunch) के नाम से जाना जाता है। हमारा विश्व भी एक ऐसे ही महा संकुचन में नष्ट हो जायेगा, जो एक महा विस्फोट के द्वारा नये ब्रह्मांड को जन्म देगा। यदि यह सिद्धांत सही है, तब यह संकुचन की प्रक्रिया आज से 1 खरब 50 अरब वर्ष पश्चात प्रारंभ होगी।

महा विस्फोट का सिद्धांत सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है, लेकिन सभी वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं। वे मानते हैं कि ब्रह्मांड अनादि है, इसका ना तो आदि है ना अंत। उनके अनुसार ब्रह्मांड का महा विस्फोट से प्रारंभ नहीं हुआ था, ना ही इसका अंत महा संकुचन से होगा। यह सिद्धांत मानता है कि ब्रह्मांड का आज जैसा है, वैसा ये हमेशा से था और हमेशा ऐसा ही रहेगा।

इसके अतिरिक्त अनेक धार्मिक मान्यताओं में ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश के शक्तियों की परिकल्पना देवों और महादेवों के रूप में की गयी है।

यह सब इतनी पुरानी बातें हैं, कि इनका वास्तविक प्रमाण ढूँढना अत्यंत कठिन है। फिर भी ज्योतिशास्त्र और खगोल विज्ञान के अध्ययन ब्रह्मांड में ग्रहों, उपग्रहों और अन्य पिंडों की गति और गत्यात्मकता से ही की जाती है। ज्ञान विज्ञान की परिकल्पनाओं का कोई न कोई आधार होता है। हमें सत्य की तलाश जारी रखनी चाहिए। इसी से नए ज्ञान की खोज होगी और हम सत्य के और करीब पहुँचेंगे।

**अगले अंक में जारी**

कृष्णानन्द सिंह कहार पत्रिका के कार्यकारी संपादक हैं, और प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह प्रमुख संपादक हैं ? यह कालम युवाओं को ज्ञान विज्ञान की कुछ रोचक जानकारियाँ देने की संपादकीय टीम की एक कोशिश है। आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत रहेगा।

### सन्दर्भ

- Borenstein, Seth (2011-02-19). "Cosmic census finds crowd of planets in our galaxy". . . 22 फरवरी 2011 को मूल से पुरालेखित. अभिगमन तिथि: 14 जुलाई 2012.

- "Free-Floating Planets May be More Common Than Stars". Pasadena, CA: NASA's Jet Propulsion Laboratory. 2011-02-18. मूल से से 25 मई 2011 को पुरालेखित। अभिगमन तिथि: 14 जुलाई 2012. The team estimates there are about twice as many of them as stars.
- A M T Jackson, R.E. Enthoven (1989). Folk Lore Notes. Asian Educational Services. ISBN . ... According to the Puranas, the milky way or akashganga is the

celestial River Ganga which was brought down by Bhagirath...

- Hormusjee Shapoorjee Spencer (1965). The Aryan ecliptic cycle: glimpses into ancient Indo-Iranian religious history from 25628 B.C. to 292 A.D. H.P. Vaswani. ... There are two "Gangas"—one terrestrial and the other "akashic" or celestial ... bear reference only to the "Akash Ganga" which is the Milky Way ...

### हिन्दी कविता

## 2026 में फिर से

राणा प्रताप सिंह

रिश्ता-नाता  
खेत-खलिहान  
धन-साधन  
घर-मकान  
मजमा-उत्सव  
कुछ भी नहीं रहेगा

तो विचार तो रहेगा

फिर से जोड़ लेंगे  
सब कुछ  
विचार के साथ-साथ।

अपने-दूसरे  
लोग-अलोग  
जाने-अनजाने  
सच्चे-झूठे  
दोस्त-दुश्मन  
सब चले जाएँगे छोड़कर

तो मन तो रहेगा  
शरीर में  
साँस भर उसी से खेलेगा  
मन भर।

शरीर तंग करेगा  
उम्र के प्रहार से  
तो हौसले से

चला लूँगा काम  
मगर जंगल उजड़ जाएँगे जब  
युद्ध और विकास के नाम पर  
और नहीं बचेगी प्राणवायु  
साँस लेने लायक  
तो क्या करूँगा?

मर जायेंगी  
तैरती - कूदती मछलियाँ  
नदियों और तालाबों में

पानी नहीं होगा  
पीने लायक  
और नहाने लायक  
तो क्या पीऊँगा  
और कैसे नहाऊँगा?

इसी आशंका से  
खूँटे से बँधे पशु की तरह  
मन हो जाता है बेचैन  
तोड़ने के लिए रस्सी

लड़-लड़ कर थक जाएँगे  
देशों के बीच  
और देशों के भीतर लड़ते लोग

युद्ध में नष्ट हो जाएँगे  
अनगिनत जीव-जंतु और

वनस्पतियाँ  
और मरते हुए लोगों की  
कराह सुनने वाले भी  
नहीं होंगे आस-पास

तो क्या करेंगे लोग  
इन संरचनाओं  
और सामानों का ?

कुछ सनकी लोग  
खड़े हो गए हैं कमर कस कर  
बुद्ध के खिलाफ  
और लोग भयभीत से  
भाग रहे हैं इधर-उधर

ऐसे में कहीं फिर से  
फट जाए एटम बम  
तो क्या करेंगे  
विकलांग और बेहाल होते लोग  
दुनिया भर के?

थोड़े से आश्वासन हैं  
और ढेर सी चिंताएँ  
नए वर्ष की शुरुआत में  
आप की ही तरह  
मेरे पास भी।

17 जनवरी, 2026

## कर्नाटक में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर महिला किरदारों के चरित्र का अध्ययन

निसर्ग सी ए<sup>1\*</sup> एवं अरविद कुमार<sup>2\*\*</sup>

### सार

भारत में सिनेमा समाज के एक प्रतिबिम्ब के रूप में देखा जाता है भारतीय सिनेमा में मुख्य धारा के चरित्र निर्माण में पुरुषों को मुख्य भूमिका में रखा जाता था। वर्तमान समय में ओटीटी (ओवर-द-टॉप) प्लेटफॉर्म आने के बाद से मुख्यधारा सिनेमा के साथ-साथ क्षेत्रीय सिनेमा में महिला किरदारों की मुख्यधारा में भूमिका बढ़ी है।

कर्नाटक में ओटीटी (ओवर-द-टॉप) प्लेटफॉर्म पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व का बढ़ना एक परिवर्तनकारी और सकारात्मक प्रयास है जो सिनेमा में व्यापक सामाजिक बदलावों और लैंगिक असमानता के लिए बेहद जरूरी है। अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसी सेवाओं और वूट और जी-5 जैसे क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म के उभरने के साथ महिला पात्रों को चित्रित करने के तरीके में उल्लेखनीय बदलाव आया है जो पारंपरिक रूढ़ियों से हटकर अधिक जटिल और बहुआयामी भूमिकाएँ प्रस्तुत कर रहा है।

इस शोध में कर्नाटक में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर महिला किरदारों के चरित्र का अध्ययन किया गया है जिसमें शोधार्थी ने गुणात्मक सामग्री विश्लेषण दृष्टिकोण का उपयोग किया है। उद्देश्य नमूनाकरण तकनीक का इस्तेमाल करते हुये नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम और हॉटस्टार जैसे

प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लोकप्रिय कन्नड़ सीरीज और फिल्मों का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में कर्नाटक में ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में एक महिला का चरित्र बहुआयामी और विकसित होता है। जिसमें महिला किरदारों को मुख्य भूमिका में रखते हुए उन्हें एक मजबूत, नारीवादी, सशक्त और निर्णय लेने वाली पात्र के रूप में दिखाया गया है। इस शोध से कर्नाटक सिनेमा में लैंगिक असमानता के साथ-साथ महिला पात्रों के विभिन्न आयामों को समझने में मदद मिलेगी।

बीज शब्द : ओटीटी प्लेटफॉर्म, महत्वपूर्ण, महिलाएं, परिवर्तनकारी कथाएं, प्रतिबिंबित और मनोरंजन।

### मूल आलेख

कन्नड़ फिल्म उद्योग वास्तव में कन्नड़ रंगमंच का ही विस्तार है। शुरुआती फिल्मी हस्तियाँ कन्नड़ रंगमंच की दुनिया में सक्रिय रूप से शामिल थीं। कन्नड़ फिल्म उद्योग को 1929-1934 के दौरान संघर्ष करना पड़ा। कन्नड़ फिल्मों को मोटे तौर पर व्यावसायिक फिल्मों और नई लहर वाली फिल्मों में वर्गीकृत किया जा सकता है। गुब्बी वीरन्ना ने कन्नड़ फिल्म उद्योग के विकास के लिए ठोस नींव रखी। उन्होंने 1928 में "कर्नाटक फिल्म स्टूडियो" की स्थापना की थी।

पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर महिलाओं को

जिस तरह से दर्शाया जा रहा है, उसमें उल्लेखनीय बदलाव आया है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पारंपरिक रूढ़ियों से हटकर गहराई और जटिलता के साथ महिला पात्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रस्तुत करने के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल के रूप में उभरे हैं।

महिलाओं को अब बहुमुखी व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया जाता है जिनकी भूमिकाएँ विविध हैं जिनमें शक्ति, भेद्यता, महत्वाकांक्षा और लचीलापन जैसे गुण प्रदर्शित होते हैं। यह बदलाव बदलते सामाजिक मानदंडों को दर्शाता है और प्रगतिशील कहानी कहने को प्रोत्साहित करता है तथा महिलाओं की आवाज़ और अनुभवों को बढ़ाता है। नाटक कॉमेडी और थ्रिलर जैसी विभिन्न शैलियों के माध्यम से कर्नाटक का ओटीटी कंटेंट महिलाओं के चित्रण को नया रूप दे रहा है और अधिक समावेशी और निष्पक्ष मीडिया परिदृश्य में योगदान दे रहा है।

### समस्या का विवरण

पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के चित्रण को लेकर काफी चर्चा हुई है। इन प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कहानियों और भूमिकाओं के व्यापक दायरे के बावजूद रूढ़िवादिता के सुदृढ़ीकरण और प्रगतिशील और प्रतिगामी चित्रण के बीच नाजुक

<sup>1</sup>शोध छात्रा एवं <sup>2</sup>शोध छात्र

पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

ईमेल : nisarganisarga16118@gmail.com\* ; arvidbbau2@gmail.com\*\*

संतुलन एक वैध चिंता का विषय है। इन चित्रणों को समझने में यह चुनौती है कि यह कर्नाटक में महिलाओं के सामाजिक दृष्टिकोण और दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रीय ओटीटी सामग्री में महिलाओं के चित्रण की जांच करने से लैंगिक प्रतिनिधित्व में प्रगति और असफलताओं दोनों का पता चल सकता है तथा अधिक सूक्ष्म और सशक्त महिला पात्रों की आवश्यकता पर बल दिया जा सकता है जो विभिन्न प्रकार के वास्तविक जीवन के अनुभवों को प्रतिबिम्बित करते हैं।

### शोध के उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य कर्नाटक में ओटीटी प्लेटफॉर्म में महिलाओं की जिम्मेदारियों, स्टीरियोटाइप और चरित्र निर्माण के प्रतिनिधित्व का अध्ययन।

इस अध्ययन का उद्देश्य कर्नाटक में महिलाओं के मुद्दों चुनौतियों और सशक्तिकरण पर ओ टी टी प्लेटफॉर्म का प्रभाव।

कर्नाटक के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर वहां के सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का महिलाओं के चित्रण पर पड़े प्रभाव को समझना ?

ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर उन संभावनाओं की तलाश और दूरी को पता करना जो महिलाओं के विविधवादी और समतावादी चित्रण को दर्शाती है!

### शोध पद्धति

कर्नाटक में ओटीटी प्लेटफार्मों पर

महिला पात्रों के चित्रण का पता लगाने के लिए इस अध्ययन में गुणात्मक सामग्री विश्लेषण दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है। नेटपिलक्स अमेज़न प्राइम और हॉटस्टार जैसे प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लोकप्रिय कन्नड़ सीरीज़ और फ़िल्मों का चयन करने के लिए उद्देश्य नमूनाकरण तकनीक का उपयोग किया गया है। जिनमें मुख्य मानदंडों में दर्शकों की रेटिंग और सांस्कृतिक प्रासंगिकता शामिल है।

इस शोध का विश्लेषण चरित्र लक्षणों भूमिकाओं और कथात्मक आर्क पर केंद्रित है। आवर्ती पैटर्न और विचलन की पहचान करने के लिए डेटा को कोडित और विषयगत रूप से विश्लेषण किया गया है। दर्शक सामग्री विश्लेषण को पूरक बनाते हैं। कन्नड़ दर्शकों के बीच प्रतिनिधित्व और इसके स्वागत में सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

### परिणाम

ग्राफ : बार ग्राफ –कर्नाटक में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर महिला पात्रों की विशेषताएं—

**X-अक्ष : लक्षण :** (स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहानुभूति, विनम्रता, निर्भरता)

**Y-अक्ष : आवृत्ति :** (प्रत्येक विशेषता प्रदर्शित करने वाले वर्णों की संख्या)

**ग्राफ विवरण :** ग्राफ में 6 पट्टियाँ हैं जिनमें से प्रत्येक एक विशेषता को

दर्शाती है। प्रत्येक पट्टी की ऊँचाई उस विशेषता को प्रदर्शित करने वाले वर्णों की आवृत्ति को दर्शाती है।

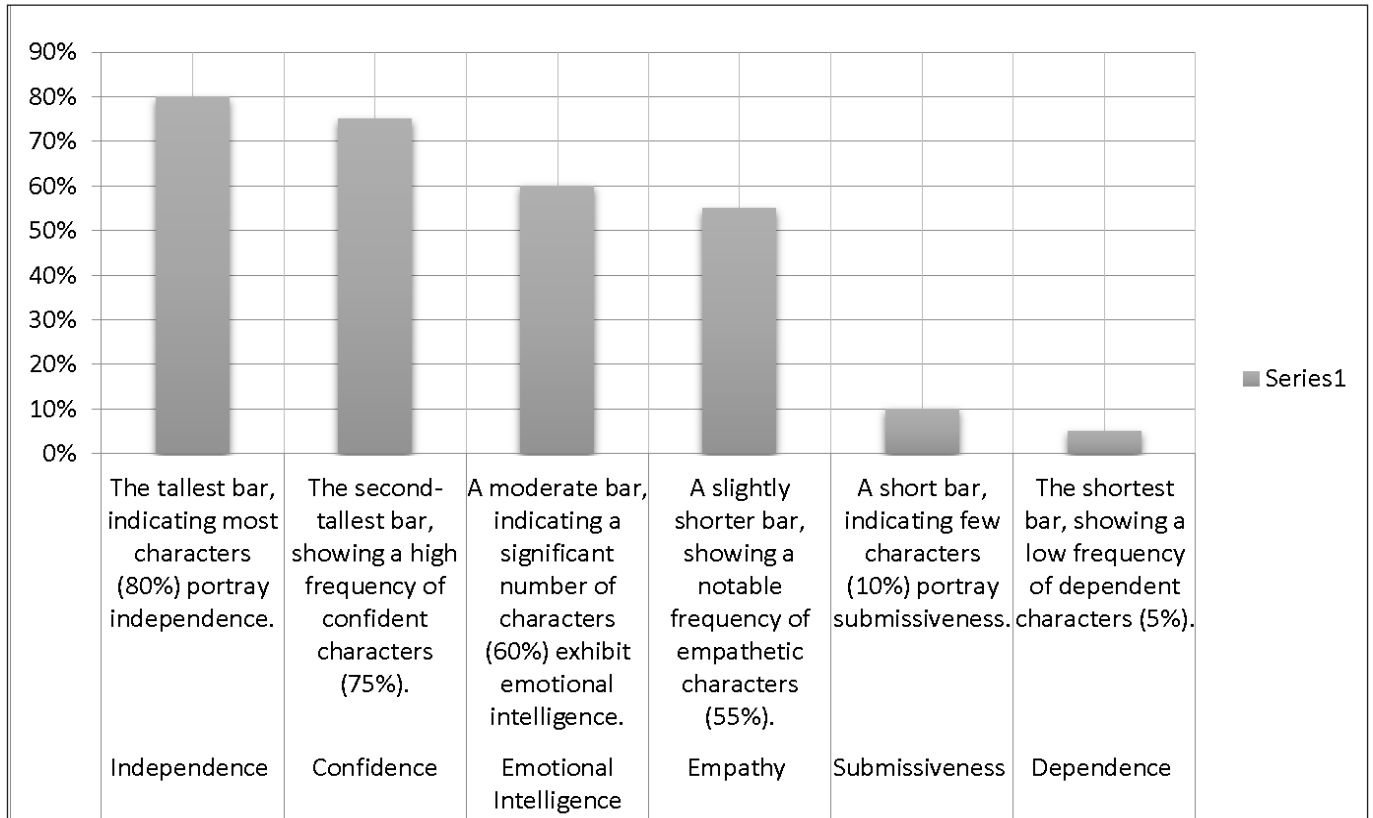
### एक परिचय कर्नाटक

कर्नाटक जो अपने समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और जीवंत मनोरंजन क्षेत्र के लिए जाना जाता है ने ओटीटी प्रवृत्ति का स्वागत किया है। इन प्लेटफॉर्म पर कन्नड़ भाषा की सामग्री लोकप्रिय हो रही है ! जिससे महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर एक अनूठा दृष्टिकोण सामने आ रहा है। राज्य के विविध दर्शकों और प्रगतिशील सोच ने रचनाकारों को ऐसे विषयों और पात्रों की खोज करने के लिए प्रेरित किया है जो आधुनिक दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं।

### प्रमुख विषय और रुझान :

- विविध भूमिकाएँ:** ओटीटी कंटेंट महिलाओं को कई तरह की भूमिकाओं में दिखाया जाता है. व्यवसायी राजनीतिज्ञ, विद्रोही और कार्यकर्ता तक। ये किरदार अक्सर पारंपरिक लैंगिक अपेक्षाओं को चुनौती देते हैं और लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं।
- यथार्थवादी चित्रण:** मुख्यधारा के सिनेमा में अक्सर अतिरंजित चित्रण के विपरीत ओटीटी प्लेटफॉर्म अधिक यथार्थवादी और भरोसेमंद महिला पात्रों की

स्वतंत्रता (Independence)	सबसे ऊंची पट्टी यह दर्शाती है कि अधिकांश पात्र 80% स्वतंत्रता दर्शाते हैं।	80%
आत्मविश्वास (Confidence)	दूसरी सबसे ऊंची पट्टी जो आत्मविश्वास से भरे पात्रों की उच्च आवृत्ति को 75% दर्शाती है।	75%
भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence)	एक मध्यम बार जो महत्वपूर्ण संख्या में पात्रों की 60 % भावनात्मक बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है।	60%
सहानुभूति (Empathy)	थोड़ी छोटी पट्टी सहानुभूतिपूर्ण पात्रों की उल्लेखनीय आवृत्ति 55% को दर्शाती है।	55%
विनम्रता (Submissiveness)	एक छोटी सी पट्टी जो कुछ पात्रों 10% की विनम्रता को दर्शाती है।	10%
निर्भरता (Dependence)	सबसे छोटी पट्टी आश्रित पात्रों की कम आवृत्ति को 5% दर्शाती है।	5%



पेशकश करते हैं, जिससे दर्शकों की सहभागिता बढ़ती है।

**3. जटिल कथाएँ:** वेब सीरीज़ का विस्तारित प्रारूप गहन चरित्र विकास और जटिल कहानी कहने की सुविधा प्रदान करता है। महिलाएँ केवल सहायक पात्र नहीं हैं बल्कि कहानी के केंद्र में हैं जो कथानक और उसके विषयों को प्रभावित करती हैं।

**4. क्षेत्रीय प्रभाव:** ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कन्नड़ कंटेंट स्थानीय संस्कृति भाषा और सामाजिक चुनौतियों को दर्शाता है जो कर्नाटक में महिलाओं के जीवन को एक अलग नज़रिए से दिखाता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म यहाँ की क्षेत्रीय कहानियों चरित्रों में महिलाओं के चित्रण को समृद्ध बनाता है।

कर्नाटक में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर महिलाओं का चित्रण पारंपरिक मीडिया चित्रण से एक उल्लेखनीय बदलाव को दर्शाता है। यह लैंगिक भूमिकाओं और

महिला सशक्तिकरण पर बदलते सामाजिक विचारों को दर्शाता है। जैसे- जैसे डिजिटल परिदृश्य विकसित होता जा रहा है महिलाओं का प्रतिनिधित्व तेजी से गतिशील और समावेशी होता जा रहा है जिससे अधिक न्यायसंगत मीडिया वातावरण को बढ़ावा मिल रहा है।

### महत्व

## सांस्कृतिक प्रतिबिंब और प्रभाव

### 1. सांस्कृतिक प्रतिबिंब

प्रामाणिक प्रतिनिधित्व ओटीटी प्लेटफॉर्म पर महिलाओं का चित्रण कर्नाटक में सांस्कृतिक मूल्यों मानदंडों और लैंगिक भूमिकाओं के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह समाज को एक आईना प्रदान करता है जो महिलाओं के अनुभवों की विविधता और जटिलता को दर्शाता है।

विविध कथाएँ कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध जनसंख्या के कारण महिला पात्रों की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है

जो राज्य में जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। प्रतिनिधित्व में यह विविधता अधिक समावेशी मीडिया परिदृश्य बनाने में मदद करती है।

### 2. सांस्कृतिक प्रभाव

दृष्टिकोण को आकार देना मीडिया का प्रतिनिधित्व महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। सकारात्मक और बहुआयामी चित्रण लैंगिक समानता को बढ़ावा दे सकते हैं और रूढ़िवादिता को चुनौती दे सकते हैं। रोल मॉडल सशक्त स्वतंत्र महिला पात्र रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं जो कर्नाटक में महिलाओं और लड़कियों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने तथा अपने अधिकारों का दावा करने के लिए प्रेरित करते हैं।

## सामाजिक प्रभाव

### 1. रूढ़िवादिता को तोड़ना

चुनौतीपूर्ण मानदंड पारंपरिक रूढ़ियों को चुनौती देने वाली विभिन्न भूमिकाओं में महिलाओं को चित्रित करके ओटीटी

प्लेटफॉर्म पुरानी धारणाओं को बदलने और अधिक प्रगतिशील विचारों को प्रोत्साहित करने में योगदान देते हैं।

सशक्तिकरण ऐसे चित्रण जो महिलाओं को सत्ता की स्थिति में निर्णय लेते हुए तथा स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीते हुए दिखाते हैं दर्शकों को समान स्वायत्तता और सम्मान के लिए प्रयास करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

## 2. जागरूकता और वकालत

मुद्दों पर प्रकाश डालना ओटीटी सामग्री महिलाओं को प्रभावित करने वाले गंभीर मुद्दों जैसे घरेलू हिंसा लैंगिक भेदभाव और कैरियर चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाती है।

परिवर्तन की वकालत करना कहानी कहने के माध्यम से ओटीटी प्लेटफॉर्म सामाजिक परिवर्तन की वकालत कर सकते हैं दर्शकों को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियों और प्रथाओं का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

## आर्थिक और रचनात्मक विकास

### 1. बाजार की मांग

दर्शकों की सहभागिता विविध और प्रासंगिक महिला पात्र व्यापक दर्शकों को आकर्षित करते हैं जिनमें महिला दर्शक भी शामिल हैं जो अपने अनुभवों के अनुरूप प्रतिनिधित्व की तलाश करती हैं।

**सामग्री विविधता :** विविध और प्रामाणिक महिला चित्रण की मांग को पूरा करने के लिए अद्वितीय और आकर्षक सामग्री का निर्माण किया जाता है जो प्रतिस्पर्धी बाजार में ओटीटी प्लेटफॉर्मों को अलग करता है।

### 2. उद्योग अवसर

प्रतिभा प्रदर्शन मजबूत महिला पात्रों को उजागर करने से महिला अभिनेत्रियों, लेखकों, निर्देशकों और निर्माताओं को

अपनी प्रतिभा दिखाने और पहचान हासिल करने के अवसर मिलते हैं।

रचनात्मक नवाचार विविध और अच्छी तरह से युक्त महिला पात्र अधिक अभिनव कहानी कहने की ओर ले जाते हैं पारंपरिक कथाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और ओटीटी उद्योग के विकास में योगदान देते हैं।

## शैक्षिक और नैतिक विचार

### 1. मीडिया साक्षरता

आलोचनात्मक अवलोकन मीडिया प्रतिनिधित्व के महत्व के बारे में दर्शकों को शिक्षित करने से विषय वस्तु का अधिक आलोचनात्मक उपभोग होता है जिससे एक विवेकशील दर्शक वर्ग का विकास होता है जो गुणवत्ता और प्रामाणिकता की मांग करता है। संवाद और चर्चा महिलाओं के विचारोत्तेजक चित्रण से लैंगिक भूमिकाओं और समानता के बारे में चर्चा को बढ़ावा मिल सकता है जिससे अधिक सूचित और जागरूक समाज को बढ़ावा मिलेगा।

### 2. नैतिक जिम्मेदारी

सामाजिक उत्तरदायित्व ओटीटी प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वे महिलाओं को नैतिक और सटीक तरीके से चित्रित करें हानिकारक रूढ़ियों से बचें और सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें।

समावेशी अभ्यास सामग्री निर्माण में समावेशी अभ्यास अपनाने से अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण मीडिया वातावरण बनता है जो समानता और सम्मान के सामाजिक मूल्यों को दर्शाता और बढ़ावा देता है। कर्नाटक में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर महिलाओं का चरित्र सांस्कृतिक मानदंडों को आकार देने सामाजिक दृष्टिकोण को प्रभावित करने और मीडिया उद्योग के रचनात्मक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में बहुत महत्व रखता है।

महिलाओं के विविध प्रामाणिक और सशक्त चित्रण को प्राथमिकता देकर ओटीटी प्लेटफॉर्म एक अधिक समावेशी और प्रगतिशील समाज में योगदान करते हैं एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ महिलाओं को उनकी सभी जटिलताओं और ताकत के साथ देखा सुना और महत्व दिया जाता है।

कर्नाटक में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के चरित्र का भविष्य का रुझान

### 1. प्रतिनिधित्व में विविधता बढ़ाना

चरित्र के आदर्शों का विस्तार भविष्य के रुझान पारंपरिक रूढ़ियों से दूर जाने का संकेत देते हैं जिसमें महिला पात्रों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम उभर कर सामने आता है। महिलाओं को पेशेवरों और उद्यमियों से लेकर एथलीटों और कलाकारों तक की विविध भूमिकाओं में चित्रित किया जाएगा जो कर्नाटक में महिलाओं की वास्तविक जीवन की जटिलताओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है !

अंतर-विषयक प्रतिनिधित्व अंतर-विषयक प्रतिनिधित्व पर अधिक ध्यान दिया जाएगा जिसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, आयु, यौन अभिविन्यास और क्षमताओं वाली महिलाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इससे महिलाओं के अनुभवों का अधिक समावेशी और व्यापक चित्रण होगा।

### 2. मजबूत महिला पात्र

मुख्य भूमिकाएँ ज़्यादातर कंटेंट में महिलाओं को मुख्य नायक के तौर पर दिखाया जाएगा जो कहानी को आगे बढ़ाएँगी और महत्वपूर्ण निर्णय लेंगी। इन किरदारों को नेता नवोन्मेष कऔर बदलाव लाने वाले के तौर पर दिखाया जाएगा।

**जटिल किरदार :** महिला मुख्य किरदारों को ज़्यादा गहराई और जटिलता के साथ लिखा जाएगा

जिसमें समय के साथ उनकी ताकत कमज़ोरियाँ और विकास को दिखाया जाएगा।

यह चलन ज़्यादा यथार्थवादी और भरोसेमंद चित्रण में योगदान देगा।

### 3. सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें

लिंग आधारित थीम ओटीटी प्लेटफॉर्म घरेलू हिंसा लैंगिक भेदभाव मानसिक स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकारों जैसे लिंग आधारित सामाजिक मुद्दों से निपटने में तेजी से आगे बढ़ेंगे। जागरूकता बढ़ाने और चर्चाओं को बढ़ावा देने के लिए इन विषयों को कहानियों में बुना जाएगा।

स्टोरीटेलिंग के माध्यम से वकालत : कंटेंट क्रिएटर लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने वकालत के लिए कहानी कहने के उपकरण के रूप में उपयोग करेंगे। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य दर्शकों को सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करने के लिए शिक्षित और प्रेरित करना होगा।

### 4. सशक्तिकरण कथाएँ

सशक्तिकरण की कहानियाँ महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित कहानियों में उछाल आएगा जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने की दिशा में उनकी यात्रा को उजागर करेंगी। ये कहानियाँ लचीलापन महत्वाकांक्षा और सशक्तिकरण का जश्न मनाएंगी।

रोल मॉडल :ओटीटी कंटेंट में काल्पनिक और वास्तविक जीवन दोनों तरह की महिला रोल मॉडल होंगी जो दर्शकों को प्रेरित करेंगी और अनुकरण करने के लिए सकारात्मक उदाहरण पेश करेंगी।

### महिला रचनाकारों के साथ सहयोग

प्रमुख भूमिकाओं में महिलाएँ : उद्योग में

महिला लेखकों, निर्देशकों और निर्माताओं की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे महिलाओं का अधिक प्रामाणिक और सूक्ष्म चित्रण होगा। ये रचनाकार अपने दृष्टिकोण और अनुभव लाएंगे जिससे सामग्री समृद्ध होगी।

**मार्गदर्शन और समर्थन :** ओटीटी उद्योग में महिला प्रतिभाओं का समर्थन और मार्गदर्शन करने की पहल गति पकड़ेगी जिससे अधिक समावेशी और न्यायसंगत रचनात्मक वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।

कर्नाटक में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर महिला किरदारों का भविष्य विविधताएँ सशक्तिकरण और प्रामाणिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण विकास के लिए तैयार हैं। इन रुझानों को अपनाकर ओटीटी उद्योग महिलाओं के अधिक समावेशी और प्रगतिशील प्रतिनिधित्व में योगदान दे सकता है, जो उनकी वास्तविक क्षमता और समाज पर प्रभाव को दर्शाता है।

### साहित्य की समीक्षा

मीडिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है जो लैंगिक भूमिकाओं और समानता के प्रति व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ओटीटी (ओवर-द-टॉप) प्लेटफॉर्म के आगमन के साथ सामग्री के उत्पादन वितरण और उपभोग के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है विशेष रूप से कर्नाटक जैसे क्षेत्रीय संदर्भों में। यह साहित्य समीक्षा कर्नाटक में ओटीटी सामग्री में महिलाओं के चित्रण पर मौजूदा शोध की पड़ताल करती है जिसमें प्रमुख विषयों रुझानों और अंतरालों की पहचान की गई है।

### मीडिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

#### 1. ऐतिहासिक संदर्भ

सिनेमा और टेलीविजन सहित

पारंपरिक मीडिया ने अक्सर महिलाओं को रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाया है। गोकुलसिंग और दिसानायक (2004) द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि कैसे भारतीय सिनेमा ने पारंपरिक रूप से महिलाओं को या तो आदर्श व्यक्ति के रूप में या सामाजिक मानदंडों के शिकार के रूप में चित्रित किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के उदय के साथ अधिक सूक्ष्म और विविध चित्रण की संभावना है। हालाँकि पारंपरिक रूढ़ियों से संक्रमण एक चुनौती बनी हुई है।

### 2. ओटीटी प्लेटफॉर्म और कंटेंट विविधता

जैन और सरिन (2020) के अनुसार ओटीटी प्लेटफॉर्म कंटेंट में विविधता लाने और मुख्यधारा के मीडिया की सीमाओं से अलग होने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। इसमें अधिक जटिल और सशक्त महिला चरित्र बनाना शामिल है। राव (2021) इस बात पर जोर देते हैं कि कर्नाटक में क्षेत्रीय ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसी कहानियों की खोज कर रहे हैं जो स्थानीय दर्शकों के साथ गूँजती हैं जिसमें महिलाओं की कहानियाँ भी शामिल हैं जो राज्य के सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ को दर्शाती हैं।

### महिलाओं के चित्रण में प्रमुख विषय

#### 1. रूढ़िवादिता और क्लिच

विविधता की संभावना के बावजूद, कई ओटीटी शो अभी भी रूढ़िवादिता को बनाए रखने के जाल में फंस जाते हैं। मेनन (2019) ने पाया कि महिला पात्रों को अक्सर पारंपरिक भूमिकाओं में दिखाया जाता है: जैसे कि गृहिणी या प्रेम रुचियाँ यहाँ तक कि डिजिटल सामग्री में भी।

गुप्ता और शर्मा (2021) द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि मजबूत महिला लीड की संख्या में वृद्धि

होने के बावजूद कई कहानियाँ अभी भी पुरुषों के साथ उनके संबंधों के इर्द-गिर्द घूमती हैं न कि उनकी व्यक्तिगत यात्राओं के इर्दगिर्द।

## 2. सशक्तिकरण और स्वायत्तता

सकारात्मक रुझान उभर रहे हैं जिसमें स्वतंत्र करियर, उन्मुख महिलाओं को दिखाने वाले ज्यादा शो शामिल हैं। नायर (2020) ओटीटी सीरीज़ के उदाहरणों पर प्रकाश डालते हैं जहाँ महिलाओं को पेशेवर उद्यमी और नेता के रूप में दिखाया जाता है। वर्मा (2022) के अनुसार, महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाली कहानियों का चलन बढ़ रहा है जो व्यक्तिगत और पेशेवर क्षेत्रों में उनके संघर्ष और जीत को प्रदर्शित करती हैं।

## 3. सांस्कृतिक विशिष्टता

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्षेत्रीय सामग्री अक्सर स्थानीय सांस्कृतिक बारीकियों को दर्शाती है। पाटिल (2021) चर्चा करते हैं कि कैसे कन्नड़ ओटीटी सामग्री सांस्कृतिक तत्वों को शामिल करती है जो कर्नाटक के लिए अद्वितीय हैं जो महिला पात्रों के चित्रण को प्रभावित करते हैं। यह सांस्कृतिक विशिष्टता रूढ़ियों को चुनौती दे सकती है और उन्हें मजबूत भी कर सकती है। उदाहरण के लिए कथाएँ पारंपरिक भूमिकाओं का जश्न मना सकती हैं जबकि आधुनिक प्रगतिशील विषयों को भी पेश कर सकती हैं।

## दर्शकों की धारणा और प्रभाव

### 1. दर्शकों की सहभागिता

अध्ययनों से पता चलता है कि दर्शक महिलाओं के विविध और प्रामाणिक चित्रण के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। राव (2020) ने पाया कि जब महिला पात्रों को गहराई और प्रामाणिकता के साथ चित्रित किया जाता है तो दर्शकों की संख्या और सहभागिता बढ़ जाती है। कर्नाटक

फिल्म जर्नल (2021) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण ने संकेत दिया कि दर्शक ऐसी सामग्री की सराहना करते हैं जो पारंपरिक लिंग मानदंडों से अलग होती है जो बदलते सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाती है!

## 2. सामाजिक प्रभाव

मीडिया में महिलाओं के चित्रण का सामाजिक धारणाओं और लैंगिक मानदंडों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शर्मा (2019) का तर्क है कि सकारात्मक प्रतिनिधित्व से समाज में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, रूढ़िवादिता का कायम रहना हानिकारक मानदंडों को मजबूत कर सकता है और लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को सीमित कर सकता है जैसा कि कुमार (2018) ने उल्लेख किया है।

## अंतराल और भविष्य की दिशाएँ

### 1. अधिक शोध की आवश्यकता

कर्नाटक के ओटीटी कंटेंट में महिलाओं के चित्रण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक व्यापक शोध की आवश्यकता है। मौजूदा अध्ययन अक्सर व्यापक होते हैं और क्षेत्रीय विशिष्टताओं में गहराई से नहीं जाते हैं। आगे के शोध में कंटेंट का मात्रात्मक विश्लेषण और रचनाकारों और दर्शकों के साथ साक्षात्कार से जुड़े गुणात्मक अध्ययन शामिल होने चाहिए।

### 2. अंतर्संबंध पर ध्यान दें

भविष्य के अध्ययनों में जाति वर्ग कामुकता और आयु जैसे कारकों पर विचार करते हुए अंतर्संबंधी प्रतिनिधित्व का पता लगाना चाहिए। इससे मीडिया चित्रण में विभिन्न पहचानों के अंतर्संबंध के बारे में अधिक समग्र समझ मिलेगी।

### 3. प्रभाव अध्ययन

कर्नाटक में महिलाओं के जीवन पर मीडिया चित्रण के वास्तविक दुनिया के

प्रभाव का आकलन करने वाले अध्ययनों की आवश्यकता है। इसमें यह देखना शामिल है कि मीडिया राज्य में महिलाओं की धारणाओं व्यवहारों और अवसरों को कैसे प्रभावित करता है।

कर्नाटक में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के चित्रण पर साहित्य प्रगति और चल रही चुनौतियों दोनों को दर्शाता है। जबकि अधिक विविधतापूर्ण और सशक्त प्रतिनिधित्व की दिशा में सकारात्मक रुझान हैं, पारंपरिक रूढ़ियाँ बनी हुई हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मीडिया अधिक समावेशिता और प्रामाणिकता की ओर विकसित होता रहे कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा आगे अनुसंधान और सचेत प्रयास आवश्यक हैं।

## दृष्टिकोण

कर्नाटक में ओटीटी (ओवर-द-टॉप) प्लेटफॉर्म पर महिलाओं को चित्रित करने के दृष्टिकोण में महिला पात्रों को विकसित करने और चित्रित करने के लिए सामग्री निर्माताओं द्वारा नियोजित विभिन्न रणनीतियों और पद्धतियों को समझना शामिल है। इसमें कथात्मक तकनीकों विषयगत फोकस और सांस्कृतिक विचारों की जाँच करना शामिल है जो इन चित्रणों को प्रभावित करते हैं।

### 1. कथात्मक तकनीक

**जटिलता और गहराई :** ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आधुनिक कथाओं का उद्देश्य एकआयामी रूढ़ियों से परे जाकर गहराई और जटिलता के साथ महिला पात्रों का निर्माण करना है। इन पात्रों में अक्सर जटिल बैकस्टोरी प्रेरणाएँ और आर्क होते हैं जो पूरी श्रृंखला या फिल्म में विकसित होते हैं।

**चरित्र विकास :** चरित्र विकास पर जोर दिया जाता है यह दिखाते हुए कि महिलाएँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक चुनौतियों का सामना कैसे करती हैं जो

उनके व्यक्तित्व में कई परतें जोड़ता है। इस विकास को अक्सर महत्वपूर्ण कथानक बिंदुओं और अन्य पात्रों के साथ बातचीत के माध्यम से दर्शाया जाता है।

## 2. सशक्त महिला पात्र

**नायक की भूमिकाएँ :** महिलाओं को केंद्रीय पात्र के रूप में स्थान दिया जा रहा है जो कथा को आगे बढ़ाती हैं। इन पात्रों को अक्सर कहानी के संदर्भ में स्वतंत्र, साधन संपन्न और प्रभावशाली के रूप में दर्शाया जाता है।

**नेतृत्व और एजेंसी :** महिला मुख्य पात्रों को प्रभार संभालते, निर्णय लेते और परिणामों को प्रभावित करते हुए दिखाया जाता है, इस प्रकार उन्हें अपने जीवन में और बड़े आख्यान में सक्रिय एजेंट के रूप में चित्रित किया जाता है।

## 3. अंतर्संबंध

**विविध प्रतिनिधित्व :** विभिन्न सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, आयु, यौन अभिविन्यास और क्षमताओं वाली महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सचेत प्रयास किया जाता है। यह दृष्टिकोण एक अधिक समावेशी चित्रण सुनिश्चित करता है जो दर्शकों की विविधता को दर्शाता है।

**सांस्कृतिक संवेदनशीलता :** कर्नाटक की सांस्कृतिक बारीकियों को समझना और चरित्र विकास में एकीकृत करना प्रामाणिक और संबंधित महिला पात्रों को बनाने में मदद करता है। इसमें स्थानीय परंपराओं बोलियों और सामाजिक मानदंडों को दर्शाना शामिल है।

## विषयगत फोकस

### 1. सशक्तिकरण और स्वायत्तता:

**करियर और महत्वाकांक्षा :** कई ओटीटी कथाएँ महिलाओं के पेशेवर जीवन पर ध्यान केंद्रित करती हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं, चुनौतियों और

सफलताओं पर प्रकाश डालती हैं। इसमें उद्यमियों, पेशेवरों और गैर-पारंपरिक भूमिकाओं में महिलाओं की कहानियाँ शामिल हैं।

**व्यक्तिगत विकास :** आत्म-खोज, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सशक्तिकरण के विषय प्रचलित हैं। ये कहानियाँ अक्सर महिलाओं को बाधाओं पर काबू पाने और अपनी पहचान और स्वायत्तता का दावा करते हुए दर्शाती हैं।

### 2. सामाजिक मुद्दे

**लिंग आधारित हिंसा :** घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना एक आम विषय है। इन कथाओं का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और इन दबावपूर्ण मुद्दों पर संवाद को बढ़ावा देना है।

**मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण :** मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के साथ महिलाओं के संघर्ष और उपचार और लचीलेपन की ओर उनकी यात्रा को दिखाया गया है।

### 3. रिश्ते और पारिवारिक गतिशीलता

भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करना कहानियाँ अक्सर रिश्तों और पारिवारिक भूमिकाओं की बदलती गतिशीलता का पता लगाती हैं। महिलाओं को रिश्तों में समान भागीदार के रूप में चित्रित करती हैं और परिवार और समाज में उनके योगदान को उजागर करती हैं।

**सहायता प्रणाली :** मजबूत महिला मित्रता और सहायक नेटवर्क का चित्रण आम है, जो महिलाओं के बीच एकजुटता और आपसी समर्थन के महत्व पर जोर देता है।

## सांस्कृतिक विचार

### 1. क्षेत्रीय संदर्भ:

**स्थानीय कहानियाँ :** सामग्री निर्माता

ऐसी कहानियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो कर्नाटक में स्थानीय दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती हैं, जिसमें क्षेत्रीय परंपराएँ और सांस्कृतिक संदर्भ शामिल होते हैं। इससे पात्रों में प्रामाणिकता और प्रासंगिकता आती है।

**भाषा और बोली :** कन्नड़ और क्षेत्रीय बोलियों का उपयोग स्थान और सांस्कृतिक विशिष्टता की भावना पैदा करने में मदद करता है जिससे पात्र स्थानीय दर्शकों के लिए अधिक प्रासंगिक बन जाते हैं !

### 2. परंपरा और आधुनिकता में संतुलन

पारंपरिक भूमिकाएँ कुछ कहानियाँ महिलाओं को पारंपरिक भूमिकाओं में दर्शाती हैं इन भूमिकाओं में उनके योगदान और चुनौतियों पर प्रकाश डालती हैं साथ ही उनकी ताकत और लचीलेपन को भी दर्शाती हैं।

**आधुनिक आकांक्षाएँ :** इसके साथ ही ऐसी कहानियाँ भी हैं जो महिलाओं की आधुनिक प्रगतिशील आकांक्षाओं को प्रदर्शित करती हैं जो लैंगिक भूमिकाओं के प्रति विकसित होते सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।

## उदाहरण और केस स्टडीज़

### 1. उदाहरण – 1: पुष्पवल्ली

इस सीरीज़ में एक मजबूत महिला मुख्य भूमिका में है जो व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियों का सामना बुद्धि और दृढ़ संकल्प के साथ करती है। यह किरदार बहुआयामी है, जो कमजोरी, महत्वाकांक्षा और लचीलेपन दिखाता है। कहानी हास्य और गंभीर विषयों के बीच संतुलन बनाती है जिससे मुख्य किरदार का सूक्ष्म चित्रण होता है।

### 2. उदाहरण 2: कंटारा

कर्नाटक के सांस्कृतिक संदर्भ में गहराई से निहित यह फिल्म महिलाओं को विभिन्न भूमिकाओं में चित्रित करती

है, जो समाज के पारंपरिक और आधुनिक दोनों पहलुओं को दर्शाती है। महिला पात्र कहानी का अभिन्न अंग हैं जो अपने सांस्कृतिक ढांचे के भीतर ताकत ज्ञान और एजेंसी का प्रदर्शन करती हैं।

### निष्कर्ष

कर्नाटक में ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में एक महिला का चरित्र बहुआयामी और विकसित होता है जो पारंपरिक रूढ़ियों को चुनौती देते हुए व्यापक सामाजिक परिवर्तनों को दर्शाता है।

पारंपरिक मीडिया के विपरीत ओटीटी प्लेटफॉर्म अक्सर महिलाओं को विविध आकांक्षाओं और पहचानों वाले जटिल व्यक्तियों के रूप में चित्रित करते हैं। वे पारंपरिक भूमिकाओं तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि महत्वाकांक्षाएँ लचीलापन और सशक्तिकरण की कहानियों का पता लगाते हैं।

कर्नाटक में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अक्सर महिलाओं को आधुनिक चुनौतियों जैसे कि करियर ग्रोथ, रिश्तों और सामाजिक अपेक्षाओं से जूझते हुए दिखाया जाता है। वे बाधाओं को तोड़ने वाले स्वतंत्र पेशेवरों से लेकर व्यक्तिगत दुविधाओं से जूझने वाले व्यक्तियों तक के व्यक्तित्वों को दिखाते हैं। ये चित्रण एजेंसी और पसंद के महत्व पर जोर देते हैं। महिलाओं को अपने जीवन में निर्णय लेने वाले के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा कर्नाटक में ओटीटी प्लेटफॉर्म विविधता और समावेशिता का जश्न मनाने वाली कहानियों के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि और समुदायों की महिलाएँ शामिल हैं। वे ऐसी कहानियाँ पेश करते हैं जो दर्शकों को पसंद आती हैं, और ताकत भेदभाव और दृढ़ता के सार्वभौमिक विषयों को उजागर करती हैं।

निष्कर्ष के तौर पर, कर्नाटक में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक महिला का

चरित्र सूक्ष्म कहानी कहने और प्रतिनिधित्व की ओर एक प्रगतिशील बदलाव को दर्शाता है। यह लैंगिक भूमिकाओं पर संवाद को प्रोत्साहित करता है और दर्शकों को विविध कथाओं के साथ सशक्त बनाता है जो रूढ़ियों को चुनौती देते हैं और व्यक्तित्व का जश्न मनाते हैं। इन चित्रणों के माध्यम से ओटीटी प्लेटफॉर्म कर्नाटक और उसके बाहर एक अधिक समावेशी और चिंतनशील मीडिया परिदृश्य को आकार देने में योगदान करते हैं।

### संदर्भ

- स्मिथ एस. एल, चौती एम, और पीपर, के (2019)। 1200 लोकप्रिय फिल्मों में असमानता: लिंग, नस्ल और एलजीबीटी स्थिति के चित्रण की जांच। यूएससी एनेनबर्ग समावेश पहल।
- मुखर्जी, डी. (2020). भारतीय सिनेमा में महिलाएँ : एक्शन में लापता, जर्नल ऑफ़ मीडिया स्टडीज़ 34(2), 125-140
- सरकार, एस. (2021) , भारतीय वेब सीरीज़ में महिलाओं का बदलता चेहरा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ कम्युनिकेशन 15, 302-317.
- कुमार, आर. (2018). कर्नाटक सिनेमा में लिंग प्रतिनिधित्व एक अध्ययन। कर्नाटक जर्नल ऑफ़ सोशल साइंसेज, 10(1), 45-60.
- भट, पी. आर (2022 ) कर्नाटक में डिजिटल मीडिया और लैंगिक धारणाएँ एक विश्लेषण। साउथ एशियन जर्नल ऑफ़ मीडिया स्टडीज़ 19(3), 215-229 दृ
- गुप्ता, आर और शर्मा पी (2021). "भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। जर्नल ऑफ़ मीडिया स्टडीज़ 15(2), 45-62.

- राव, एस. (2020). "बदलते आख्यान: कन्नड़ सिनेमा और ओटीटी में महिलाएँ।" कर्नाटक फिल्म जर्नल, 22(4), 78-90.
- स्मिथ, ए. और जोन्स, एम. (2019) । "लिंग मानदंडों पर मीडिया का प्रभाव: ओटीटी सामग्री का एक अध्ययन।" मीडिया और समाज, 10(1), 34-501
- वर्मा के (2022) भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में ओटीटी प्लेटफॉर्म की भूमिका। डिजिटल मीडिया रिव्यू 17(3), 65-80.
- गुप्ता आरण और शर्मा पी (2023) ओटीटी प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व में भविष्य की दिशाएँ। जर्नल ऑफ़ मीडिया स्टडीज़, 17(1), 25-39.
- राव एस (2022) । कन्नड़ पाठ्य पुस्तक रचना में उभरते रुझान। कर्नाटक फिल्म जर्नल, 24(2), 55-701
- स्मिथ एण और जोन्स एमण (2022). मीडिया प्रतिनिधित्व में नवाचार एक नज़र आगे। मीडिया और समाज 11(2), 48-63.
- वर्मा के (2023) द नेक्स्ट वेव जेंडर इक्विटी एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजिटल मीडिया रिव्यू, 19(1), 82-98.
- गोकुलसिंग, के. एम और दिसानायके, डब्ल्यू . (2004). भारतीय लोकप्रिय सिनेमा सांस्कृतिक परिवर्तन की कथा , ट्रेंटहम बुक्स.
- गुप्ता, आर. और शर्मा पीण. (2021) "भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एक महत्वपूर्ण विश्लेषण।" जर्नल ऑफ़ मीडिया स्टडीज़ ,15(2), 45-62.

16. जैन, आर. और सरीन, एस. (2020) "भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म में कंटेंट का विकास।" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ डिजिटल मीडिया, 9(3), 34-49.
17. कर्नाटक फिल्म जर्नल। (2021)। "कन्नड़ ओटीटी कंटेंट में लिंग प्रतिनिधित्व के बारे में दर्शकों की धारणा।" कर्नाटक फिल्म जर्नल, 22(4), 78-901
18. कुमार, ए. (2018)." भारत में मीडिया और जेंडर स्टीरियोटाइप्स "जेंडर स्टडीज क्वार्टरली, 12(1), 21-38.
19. मेनन, ए. (2019). डिजिटल मीडिया में स्टीरियोटाइप्स : ओटीटी प्लेटफॉर्म का विश्लेषण। मीडिया और समाज 10(1), 34-50.
20. नायर, पी. (2020). "भारतीय ओटीटी सीरीज़ में सशक्तिकरण कथाएँ". डिजिटल मीडिया रिव्यू ,17(3), 65-80.
21. पाटिल, एस. (2021)."कन्नड़ ओटीटी सामग्री में सांस्कृतिक बारीकियाँ "। जर्नल ऑफ़ रीजनल मीडिया स्टडीज़ 11 (2), 55-70.
22. राव, एस. (2020). "बदलते आख्यान: कन्नड़ सिनेमा और ओटीटी में महिलाएँ।" कर्नाटक फ़िल्म जर्नल, 22(4), 78-90.
23. शर्मा, ए. (2019)." मीडिया प्रतिनिधित्व का लिंग मानदंडों पर प्रभाव ". जर्नल ऑफ़ जेंडर स्टडीज़, 16(2), 99-115.
24. वर्मा, के. (2022),"भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में ओटीटी प्लेटफॉर्म की भूमिका ". डिजिटल मीडिया रिव्यू ,17(3), 65-80
25. गुप्ता, आर. और शर्मा, पी. (2021). "भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एक महत्वपूर्ण विश्लेषण". जर्नल ऑफ़ मीडिया स्टडीज़, 15(2), 45-62.
26. राव, एस. (2021)."बदलते आख्यान कन्नड़ सिनेमा और ओटीटी में महिलाएँ ". कर्नाटक फ़िल्म जर्नल , 22(4), 78-90.
26. राव, एस. (2021)."बदलते आख्यान कन्नड़ सिनेमा और ओटीटी में महिलाएँ" कर्नाटक फ़िल्म जर्नल , 22(4),78-90.

मोजपुरी रामायण से

## बैरु प्रीति नहिं दुरइं दुराएं (अयोध्याकाण्ड 192-1)

फूलचन्द्र प्रसाद गुप्त

निषादराज बुढ़ऊ कऽ बाति मानि लिहलैं अउर अपने जाति के लोगन से कहलैं कि तुहन लोग इकट्टा होके सब घाटन के रोकि लऽ। हम जाके भरत जी से मिलिके उनुकर भेद लेब कि उनकर भाव मित्र कऽ बा कि सत्रु कऽ। ई जानिके तब आके ओही के हिसाब से प्रबन्ध करब। भरतजी के सुन्नर सुभाव से हम उनुकर सनेह पहिचानि लेब,  
काहें से कि बैर अउर प्रेम छिपवले से नाही छिपेला। निषादराज कऽ ई बाति साँच हऽ कि बैर अउर प्रेम छिपवले से नाही छिपेला। ई तऽ समय पाके प्रकट हो जाला।  
अपने लोक में रहीम कऽ दोहा बहुत प्रसिद्ध हऽ-

"खैर खून खौंसी खुसी, बैर प्रीत मद पान।  
रहिमन दाबै न दबै, जानत सकल जहान।।"

एह दोहा में बैर-प्रीत कऽ बाति कहल गइल बा। सत्रुता आ प्रेम समय पर प्रकट हो जालें। इनके छुपावल नाही जा सकेला।

वृन्द जी कहलें- 'ओछे नर के पेट में, रहै न मोटी बात।' सत्रुता कऽ बाति नाही छुपेले ओइसहीं प्रेमो प्रकट हो जाला। प्रेम तऽ आचरन से प्रकट हो जाला। लोक में ई कहल जाला- 'बैरु प्रीति नहिं दुरइं दुराएँ।'

स्रोत : फूलचन्द्र प्रसाद गुप्त की पूर्व प्रकाशित पुस्तक 'लोक मानस' से साभार

## उच्चतम न्यायालय, भारत एवं कोप30 बेलेम, ब्राजील का पर्यावरणीय ऐतिहासिक निर्णय '20 नवम्बर 2025'

जलपुरुष राजेन्द्र सिंह

"We, however, direct the MoEF&CC to prepare a MPSM through ICFRE for the entire Aravalis, i.e., understood as the continuous geological ridge extending from Gujarat to Delhi on the lines of the MPSM for Saranda and the MPSM must"

उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को निर्देश दिया है। अरावली संपूर्ण रूप में गुजरात से दिल्ली तक एक पर्वत माला है। यह सम्पूर्ण संरक्षित एक ही पर्वतमाला है। इसे समग्रता में देखना है।

पूरी दुनिया और उच्चतम न्यायालय का मानना है कि पर्वतमालाएं धरती के गर्भ से निकलती हैं। इनकी सम्पूर्ण पर्वतमाला की पारिस्थितिकी एकसमान रूप में बचानी होती है। संपूर्ण भूभाग, चाहे धरती के भीतर हो या बाहर, एक जैसा संरक्षण मांगता है। इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने अरावली के हर हिस्से को उसकी सीमाओं में खनन नहीं करने के लिए व्यवस्था बनाने का 6 माह का समय दिया है। अरावली को खनन-मुक्त रखना ही भारत की विरासत बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरावली में कई अच्छे और महत्वपूर्ण खनिज हैं; जिन खनिजों की देश को राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु आवश्यकता है। ऐटमिक राष्ट्रीय सुरक्षा महत्व हेतु खनन की उनको सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है लेकिन सामान्य खनिजों के लिए अरावली को काटना, जंगल नष्ट करना और पर्वतमाला में नए घाव बनाना किसी भी रूप में उचित नहीं है। कोप30 बेलेम, ब्राजील ने भी वर्षा वन के संरक्षण एवं वनवासियों के निर्णय में भागीदार बनाने की व्यवस्था आज के ही दिन बनाई है।

20 नवंबर 2025 को ब्राजील में कोप 30 आयोजित हुआ, जिसमें दुनिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भविष्य की

चिंता में एकत्र हुए। इस बार ब्राजील के राष्ट्रपति ने स्वयं कहा कि उनके देश के अमेजोन वर्षा वन का बड़ा नुकसान खनन से हुआ है। इस नुकसान के प्रमाण दुनिया को दिखाने के लिए कोप को अमेजन फॉरेस्ट के केंद्र बेलम में आयोजित किया गया है। इस बार का कोप एक बहुत बड़ा प्रुफ है।

कोप 30 ने निर्णय लिया कि सारा पैसा सीधे आदिवासी संगठनों को दिया जाएगा, कोई सरकार बीच में नहीं रहेगी। आदिवासी स्वयं जंगल बचाने के निर्णय करेंगे। जर्मनी ने ब्राजील के नए वैश्विक वर्षावन कोष में दस वर्षों में एक अरब यूरो देने का वादा किया है। यह कोष उपग्रह निगरानी के आधार पर वनों को बचाने वालों को पुरस्कार और अधिक कटाई करने वालों पर दंड का प्रावधान करता है। जर्मनी के मंत्रियों ने इसे धरती के "फेफड़ों" उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की रक्षा का सवाल बताया है।

ब्राजील का अनुमान है कि यह कोष आगे चलकर 125 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। वर्षावन, जिन्हें धरती के "हरे फेफड़े" कहा जाता है, खेती और खनन के दबाव से संकट में हैं। नॉर्वे तीन अरब डॉलर और ब्राजील व इंडोनेशिया एक-एक अरब डॉलर देने का वादा कर चुके हैं। इस पहल में कई वर्षावन देश शामिल हैं और इसकी देखरेख एक संयुक्त समिति करेगी। लगभग सत्तर देशों को इससे लाभ मिल सकता है, बशर्ते कम से कम 20 प्रतिशत धन आदिवासी और पारंपरिक समुदायों तक पहुंचे। अब तक 53 देश

इसका समर्थन कर चुके हैं, और ब्राजील को उम्मीद है कि समृद्ध देश 25 अरब डॉलर की शुरुआती सहायता देंगे। फोजिल-फयूल शब्द विवाद को लेकर कोप का समय बढ़ गया है।

पर्यावरण और भविष्य की चिंता करने वाले मित्रों ने उच्चतम न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में अरावली को बचाने की आवाजें उठाईं। इन याचिकाओं के परिणामस्वरूप चारों राज्यों की अरावली का एक समग्र दर्शन सामने आया, जिससे हम बहुत आनंदित थे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अब आगे कोई नई खनन लीज नहीं दी जाएगी। यह बेहद सम्माननीय फैसले है। जिनसे अरावली के कुछ आंसू पोंछने की कोशिश हुई। लेकिन अब नई परिभाषा से भारत सरकार अरावली के आंसू के पोछने की शुरुआत करेगी। यह अरावली के आंसू सदैव के लिए रोकेंगे ऐसा विश्वास है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सौ मीटर ऊंची अरावली में खनन नहीं होगा और सौ मीटर से नीचे की अरावली पर भारत सरकार विचार कर सकती हैं। यह फैसला 1990 की याद दिलाता है, जब अरावली में वैध और अवैध 28 हजार से अधिक खदानें चलती थीं। इन खदानों को बंद कराने के लिए तरुण भारत संघ की पहल और उसके आधार पर जारी नोटिफिकेशन को लागू करवाने के लिए मैंने 2 अक्टूबर 1993 को हिम्मतनगर गुजरात से दिल्ली तक पदयात्रा की थी। भारत

सरकार ने इस आवाज को गंभीरता से सुना, खदानें बंद हुईं और अरावली पुनर्जीवित होने लगी। लेकिन वर्ष 2015 आते-आते बहुत सी जगहों पर अवैध खदानें फिर चालू हो गईं। जहां खदानें चलीं, वहां अरावली नष्ट होने लगी, जल संकट और जलवायु संकट गहराने लगे, भूजल भंडार खाली होते गए। फरीदाबाद, नूहं, गुरुग्राम इसके उदाहरण हैं। अलग-अलग समय पर वैध-अवैध सभी तरह की खदानें धीरे-धीरे फिर चलने लगीं और संकट खड़ा करती रहीं। राजस्थान में अनिल मेहता तथा अन्य लोगों ने याचिका दायर करके रूकवाने की लड़ाई जारी कर दी। हरियाणा-दिल्ली में नीलम अहुवालिया ने लड़ाई खड़ी करी है, जो अब भी जारी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, एटमिक मिनरल्स जैसे अत्यावश्यक खनिज अरावली में मिलेंगे तो निकाले जा सकते हैं, और यह स्वागत योग्य बात है। लेकिन सामान्य खनिजों के लिए माइनिंग करके अरावली को नंगा करना, जंगल काटना और उसमें गैप बनाना बिल्कुल उचित नहीं है। अरावली की परिभाषा अब समग्र है। कहना कि सौ मीटर ऊंची ही अरावली होती है, गलत है। पर्वतमाला एक ही होती है। मां के गर्भ से निकले पर्वत को गर्भ से लेकर चोटी तक उसके पूरे चरित्र सहित बचाना जरूरी है, उसके पेड़-पौधे, जीव-जंतु और उसके आदिवासी, जंगलवासी समुदाय। सबसे पुराने आदिवासी समुदाय अरावली की चोटियों पर ही मिलते हैं। इनको बचाने के लिए कोप 30 से सीख लेना चाहिए।

तरुण भारत संघ ने अरावली को बचाने की आवाज सबसे पहले 1988 में उठाई थी। 1991 में अरावली में हो रहे खनन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उस जमाने में उच्चतम न्यायालय में इस केस की सुनवाई पूर्व न्यायमूर्ति श्री वेंकट चलैया, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय भारत, ने बहुत ही गंभीरता से ली थी। उन्होंने सरिस्का की 478 खदानों को बंद करने का आदेश दिया था। पूरी अरावली पर्वतमाला, जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला और दुनिया की दूसरी सबसे प्राचीन

पर्वतमालाओं में मानी जाती है, जैसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए भारत सरकार ने अरावली की आवाज सुनी और उसके आंसू पोंछने की शुरुआत 7 मई 1992 को हुई।

धीरे-धीरे यह मांग अरावली के चारों राज्यों, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैल गई। 2 अक्टूबर 1993 को हिम्मतनगर, गुजरात से अरावली का सिंहनाद करते हुए यह यात्रा 22 नवम्बर को दिल्ली संसद पहुंची थी। उस समय के संसद अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल को अरावली को बचाने के लिए ज्ञापन दिया गया और बताया गया कि भारत सरकार ने अरावली के लिए नोटिफिकेशन तो किया है, लेकिन अभी भी अवैध खदानें चल रही हैं। इन अवैध खदानों को बंद कराया जाना जरूरी है। पाटिल साहब ने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सरकारें होने से कुछ सरकारें खान मालिकों को संरक्षण दे रही हैं, जिससे मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। फिर भी, खदानों को बंद कराकर दुनिया की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली को बचाने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। उस समय अरावली ने अपने सिंहनाद से अपने को बचाने की एक प्रक्रिया शुरू करवाई थी। संसद सड़क दोनों स्थानों पर यह काम माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में किया गया था।

20 नवंबर 2025 को सम्माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की संपूर्ण पीठ ने जो निर्णय दिया है, उससे अरावली के आंसू दोबारा पोछने का काम सम्माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को दे दिया है। इन आंसुओं को रोकने का काम भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को करना है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार का जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय अरावली की पुकार सुनेगा और उसके आंसू पोंछेगा।

अरावली के बारे में चारों राज्यों में अलग-अलग परिभाषाएं दी जा रही थीं। इस चिंता को देखते हुए ही उच्चतम न्यायालय ने एक समग्र पर्वतमाला की एकीकृत परिभाषा बनाने की कोशिश की है। उन्होंने प्रयास किया

कि अरावली को राज्यों की सीमाओं में बंटाकर नहीं देखे। इस प्रयास से यह अच्छी बात हुई कि अरावली को एक पर्वतमाला मानकर उसके लिए एक समान परिभाषा का विचार आगे बढ़ा।

बड़े-छोटे का अंतर 100 मीटर उंचाई में खनन नहीं, नीची पहाड़ियों में विचार किया जा सकता है। इस गली से खनन उद्योगपति माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को तोड़-मरोड़कर उपयोग नहीं कर सके इस हेतु भारत सरकार चारों राज्य सरकारें और अरावली के समाज को खड़ा होना जरूरी है। खासकर भारत का जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय अपनी भूमिका उच्चतम न्यायालय के प्रकाश में लागू करायेगा।

अरावली विखंडित नहीं है। अरावली धरती मां के गर्भ से निकली एक समग्र पर्वतमाला है। मां के गर्भ से निकली इकाई एक होती है; उसे बड़ा-छोटा कहकर अलग-अलग परिभाषित नहीं किया जा सकता। एक इकाई के सभी अंगों का समान रूप से पोषण एवं व्यवहार होता है। जैसा उच्चतम न्यायालय ने कहा वैसा ही सरकार और खनन उद्योग में लगे उद्योगपति इस समझकर दुनिया की प्राचीनतम अरावली पर्वतमाला को सभी मिलकर बचायेंगे।

नोट- अरावली को संरक्षित करने के लिए हुए आंदोलन की पुस्तकों की लिंक दी जा रही है। जिसे क्लिक करके फ्री पढ़ सकते हैं-

### 1. अरावली का सिंहनाद

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80\\_%E0%A4%95%E0%A4%BE\\_%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A6](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80_%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A6)

### 1. अरावली के आंसू

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80\\_%E0%A4%95%E0%A4%BE\\_%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A6](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80_%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A6)

## भू-सांस्कृतिक मानचित्रण प्रमाणीकरण संगोष्ठी

पारस प्रताप सिंह

तरुण भारत संघ के तत्वावधान में भू-सांस्कृतिक मानचित्रण को लेकर दो दिवसीय (15-16 नवंबर 2025) राष्ट्रीय विचार मंथन कार्यशाला का आयोजन इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। इस कार्यशाला में भारतभर के विभिन्न एग्रो क्लाइमेटिक जोन से आए प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, डिज़ाइन विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की। यह पहल भारत के विविध भौगोलिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और पारंपरिक ज्ञान तंत्रों को जोड़कर प्रकृति व संस्कृति आधारित पुनर्जनन मॉडल तैयार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।

भू-सांस्कृतिक मानचित्रण के वैज्ञानिक सत्यापन के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें प्रो. कन्हैयालाल श्रीवास्तव, भू-विज्ञानी एवं कुलपति, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर (अध्यक्ष), प्रो. राणा प्रताप सिंह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, अर्थशास्त्री विजय परांजपे, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रो. मधुलिका बनर्जी शामिल हैं।

वहीं भू-सांस्कृतिक मानचित्रण की अवधारणा संबंधी फॉलो-अप कमेटी

में अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद के प्रो. पुनीत कुमार, जल बिरादरी पूना के नरेंद्र चुग, प्रेम शर्मा, सागर मित्र / पवन मित्र अभियान पूना के विनोद बोधनकर, यूनेस्को, नई दिल्ली में कार्यरत रहे डॉ. राम बूझ में मनोनयन किया गया है, जो एनसीईआरटी, प्रो अशोक कुमार साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर आदि के साथ मिलकर प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे।

को केंद्र में रखना होगा। यही आत्मनिर्भर और सतत भारत का मूल मार्ग है। हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए हमें एक बार फिर अपनी प्रकृति और संस्कृति के योग को देखने की जरूरत है। इस योग को देखकर, समझकर जब हम भारत के पुनर्जनन की रीति-नीति और भू-सांस्कृतिक मानचित्रण पर काम करेंगे, तो देश फिर से अपनी समृद्धि की राह पकड़ लेगा। ये समृद्धि की राह ही सनातन होगी।

उन्होंने तैयार किये

गए भू-सांस्कृतिक मानचित्रण को प्रस्तुत करते हुए बताया कि देश में मूलतः 15 एग्रो-क्लाइमेटिक जोन बनाए गए थे, परंतु वास्तविक सांस्कृतिक-पर्यावरणीय विविधता इससे कहीं अधिक व्यापक है। अब तक तरुण भारत संघ द्वारा 86 भू-सांस्कृतिक क्षेत्र पहचाने जा चुके हैं, जो मिट्टी, जल, खेती, जीवन



पर्यावरणविद् एवं पानी के कामों के जानकार डॉ. राजेंद्र सिंह की पहल पर आयोजित इस कार्यशाला में विकास बनाम पुनर्जनन के परिप्रेक्ष्य में नये नजरिये को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। डॉ. राजेंद्र सिंह ने भू-सांस्कृतिक मानचित्रण का संकल्पना पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा हमें विकास की पुरानी दृष्टि से बाहर आकर प्रकृति और संस्कृति के पुनर्जनन

व्यवहार और सांस्कृतिक प्रणालियों पर आधारित हैं। राजेंद्र सिंह ने बताया कि, दस वर्षों की यात्रा के दौरान विशिष्ट भू-सांस्कृतिक क्षेत्रों की पहचान की है, जिनकी विशिष्टताएँ 7 मानदंडों के आधार पर तय की जाती हैं। अपने अनुभव रखते हुए कहा कि स्थानीय ज्ञान हमें सिखाता है कि जहां पानी दौड़ता है, उसे रेंगना सिखाओ और फिर उसे धीरे-धीरे धरती की कोख में

उतार दो। इसी ज्ञान के आधार पर तरुण भारत संघ द्वारा 23 नदियों का पुनर्जीवन किया, जिससे जल, मिट्टी, संस्कृति के पारंपरिक वैज्ञानिक आधार को समझने में मदद मिली है।

कार्यशाला में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि, बीते दो शताब्दियों में विकास की अवधारणा केवल संरचनात्मक विस्तार और आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित रही, जिसके परिणामस्वरूप प्रकृति और संस्कृति दोनों को पीछे धकेल दिया गया। आंकड़ों के अनुसार लगभग 200 वर्ष पूर्व तक प्रकृति और संस्कृति का योग भारतीय अर्थव्यवस्था में 32 प्रतिशत तक योगदान करता था, जो आज घटकर मात्र 4 प्रतिशत रह गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मधुलिका बैनर्जी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था ने पारंपरिक ज्ञान को हाशिये पर रखा, जबकि भारत का समाज प्रकृति-संस्कृति के सह-अस्तित्व पर आधारित है। एनसीईआरटी के वरिष्ठ विशेषज्ञ दिनेश कुमार और गगन गुप्ता ने कहा कि नई पीढ़ी को अपने स्थानीय भू-सांस्कृतिक परिवेश से जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम, प्रोजेक्ट आधारित कार्य और सामुदायिक अध्यापन में नवाचार की आवश्यकता है।

पर्यावरणीय अर्थशास्त्री विजय परांजपे ने कहा कि, देश के कई क्षेत्रों का भू सांस्कृतिक चरित्र लोगों के सामान्य ज्ञान से बाहर है। लद्दाख का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि क्षेत्र दो सांस्कृतिक हिस्सों इस्लामिक और बौद्ध में बंटा होने के बावजूद इकोलॉजी और कल्चर एक-दूसरे को सहारा देते हैं। उन्होंने चर्चा के दौरान महाराष्ट्र, कोकण और मराठवाड़ा की सांस्कृतिक-पर्यावरणीय पद्धतियों को भी भू-सांस्कृतिक मानचित्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।

कार्यशाला की विशेष उपलब्धि



रही कि अहमदाबाद स्थित अनंत विश्वविद्यालय के प्रो. पुनीत कुमार तथा उनके डिज़ाइन विभाग के 44 छात्रों ने अहमदाबाद के अलावा देश के अन्य हिस्सों के लिए तैयार किए गए जियो, कल्चर मैप्स कर डिज़ाइन प्रस्तुत की। इसकी समझ तरुण भारत संघ, अलवर में अध्ययन यात्रा से मिली और उन्होंने अपने-अपने चयनित क्षेत्रों के भू-सांस्कृतिक मानचित्र तैयार किए। इन प्रस्तुतियों ने कार्यशाला की विचार-मंथन प्रक्रिया को अत्यंत समृद्ध किया।

वक्ताओं ने माना कि छात्रों द्वारा तैयार किए गए ये डिज़ाइन मॉडल बताते हैं कि भू-सांस्कृतिक मानचित्रण केवल एक शोध प्रक्रिया नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए एक प्रायोगिक, रचनात्मक और परिवर्तनकारी अभ्यास बन सकता है।

देश के विभिन्न एगो-क्लाइमेटिक ज़ोन से आए प्रतिभागियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों की पर्यावरणीय स्थिति, खेती-पद्धति, सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक अनुभव को व्यापक रूप से साझा किया। आदिकवि नन्नया विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के प्रो. एल. सी. रमेश ने ईस्टर्न कोस्टल रीजन, कुमार सिद्धार्थ ने अरावली-मालवा रीजन, वेस्टर्न राजस्थान डेर्जस्ट रीजन पर प्रो. कन्हैयालाल श्रीवास्तव, पूर्व कुलपति,

जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर की प्रस्तुतियां उल्लेखनीय रही।

एनसीईआरटी, डीएसटी, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान और स्कूल ऑफ़ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति जताई कि भूसांस्कृतिक मानचित्र केवल अकादमिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि रिसोर्स मैपिंग, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण, सामुदायिक प्रयोगों के माध्यम से विद्यार्थियों की सीख को वास्तविक जीवन से जोड़ने का माध्यम बन सकता है।

प्रतिभागियों ने कहा कि, भारत का भू-सांस्कृतिक मानचित्र नीति निर्माताओं, योजनाकारों, ब्यूरोक्रेट्स, आमजन को ऐसे मॉडल प्रदान करेगा, जिनमें स्थानीय जरूरतें, विविधता का सम्मान, जल, मिट्टी, संस्कृति, अर्थव्यवस्था का संतुलन स्पष्ट रूप से समझा जा सकेगा।

कार्यशाला के अंत में राजेंद्र सिंह ने कहा कि, जब भारत अपनी प्रकृति और संस्कृति के गहरे संबंध को समझेगा, तब विकास नहीं, बल्कि पुनर्जनन की प्रक्रिया शुरू होगी। यही स्थायी, संतुलित और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग है। इसलिए हमें भू-सांस्कृतिक मानचित्र का प्रमाणक निर्माण करके, उसी के अनुरूप प्राकृतिक पुनर्जनन को तैयार करने के लिए एक जन आंदोलन बनना चाहिए।



कार्यशाला के समापन सत्र में नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार के कुलपति, अनुसंधान और सूचना प्रणाली के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि, दुनिया अभी तक केवल 12 प्रतिशत सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को ही हासिल कर पाई है। इन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में स्थानीय सांस्कृतिक क्लस्टर और इको-प्रेक्टिसेस विकास के नए वैश्विक मॉडल बनेंगे। उन्होंने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय शतप्रतिशत नेट-ज़ीरो कैंपस है, जो जल और ऊर्जा के मामले में पूर्णतया आत्मनिर्भर है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि, बिहार के 13 विश्वविद्यालयों द्वारा एग्रो-क्लाइमेटिक ज़ोन के संदर्भ में कार्य किया जाएगा और इस संबंध में वे ज़ोन का चयन कर उस पर काम कर सकेंगे।

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक औसत केवल 17 प्रतिशत ही एसडीजी की लक्ष्य प्राप्ति हुई है। यह बात जलपुरुष राजेंद्र सिंह जी ने कही।

कार्यशाला में नरेंद्र चुग, जल बिरादरी पूना, लक्काराजु सत्यनारायण, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश, पुनीत कुमार, सहायक प्रोफेसर, अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद, वी. एम. सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, दिल्ली, प्रो. अशोक कुमार, डायरेक्टर, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली, प्रो. एल. सी. रमेश, आदिकवि नन्नया विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश, डॉ. मनमोहन सिंह सिसोदिया गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, डॉ. पंकज

गुप्ता, हाइड्रो जियो लॉजिस्ट, आईआईटी दिल्ली, गगन गुप्ता, एनसीईआरटी, नई दिल्ली, डॉ. अखिलेश मिश्रा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, दिनेश कुमार, एनसीईआरटी, नई दिल्ली, प्रभात कौल, नवीन जिंदल फाउंडेशन, नीरज कुमार बिहार, डॉ. मधुलिका बैनर्जी, दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रो. पी. के. सिंह, उन्नत भारत अभियान, आईआईटी, दिल्ली, प्रो. राणा प्रताप सिंह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, विनोद बोधनकर सागर मित्र/पवन मित्र अभियान, पूना, दीपक कुमार, पूर्व मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, डॉ. वाई. आर. सत्यासी राव, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की आशुतोष शर्मा कानपुर, रमेशचंद्र शर्मा गांधी युवा बिरादरी, दिल्ली, कुमार सिद्धार्थ, सर्वोदय प्रेस सर्विस इंदौर, संजय सिंह, परमार्थ, मध्यप्रदेश, दीपक पर्वतीयार पत्रकार, सुधांशु रंजन संपादक प्रवासी इंडियन, अनिल सिंह सेंगर जल प्रहरी, बासवराज पाटिल राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन, दिल्ली, अशोक कुमार दिल्ली सरकार, मनीष राजपूत आदि ने सक्रिय भागीदारी की। तरुण भारत संघ के पारस प्रताप सिंह की कार्यशाला के संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।

श्री अशोक कुमार आईएएस, निदेशक नीति केंद्र, नई दिल्ली ने भी कार्यशाला में उपस्थित होकर कहा कि, इस मानचित्रण के अनुसार आगे पुनर्जनन की योजनाओं की नीति बनना चाहिए।

इस संगोष्ठी में यह बात भी बहुत जोरों से उठी कि भारत में अभी भी तरुण भारत संघ की तरह के बहुत से क्षेत्रों में संस्कृति और प्रकृति के योग से सफल प्रयोग हुए हैं। इन प्रयागों को मानचित्र में उभारने के लिए गांव स्तर से लेकर भू-सांस्कृतिक इकाईयों से जैसे- दिल्ली, जो दो भू-सांस्कृतिक इकाई खांडवप्रस्त और इन्द्रप्रस्त में बंटा है। इनके मानचित्रण पर कार्य करने की जिम्मेदारी भी ली गई।

अंत में सभा ने सर्वानुमति से तय किया कि, वर्तमान जल-वायु-भूमी संकट को भारतीय सर्व-समावेशक सांस्कृतिक समझ के आधार से अंतर-बाह्य सर्वांग-सिद्ध प्रतिसाद मिलेगा, जो समझना और समझाना अब हम सब के लिये एक नित्य-कर्तव्य-साधना का मार्ग बन गया है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक पुनर्जनन जल संरक्षण, सामुदायिक प्रबंधन से नदियों के पुनर्जनन की प्रक्रिया द्वारा संभव होगा। जब भारत की नदियां अविरल-निर्मल होगी तो भारत की धरती, प्रकृति और मानवता आरोग्य के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। इसी से हमारी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समृद्धि का भी रास्ता मिलेगा। और सर्व सम्मति से भू सांस्कृतिक मानचित्र से सरकार की नीतिगत मानसिकता में बदलाव लाने के लिए एक जन आंदोलन खड़ा करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

इस चिंतन-मंथन का शुभारंभ श्री रमेश शर्मा के सांस्कृतिक गीत " तेरे रंग अनेक तू एक ही है" और संपन्न 'सांस्कृतिक क्रांति' गीत से किया गया। इस विचार मंथन में सभी संभागियों का प्राकृतिक-सांस्कृतिक तरीके से साफा और लूंगडी पहनाकर सम्मान किया गया। यह विचार मंथन दो दिन तक पूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप में चला।

## ”अमृत काल में भोजपुरी भाषा का विकास एवं चुनौतियाँ”

नरसिंह

भोजपुरी एगो समृद्ध व जीवंत भाषा ह, जेके मुख्य रूप से बिहार आउर उत्तर प्रदेश के कई भाग में बोलल जाला। इ भाषा भारत के एगो विशाल भूखण्ड जवन उत्तर में बूढ़ी गण्डक नारायणी से दक्षिण में विन्ध्य पर्वत तक, पश्चिम में प्रयागराज से पूरब में सोन तक फइलल बा। ए पवित्र भूमि के भोजपुर प्रदेश(काशी राज ) के नाम से जानल जाला।

2. ए क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सत्रह जिला देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, भदोही, संतकबीरनगर, चन्दौली तथा बिहार के नौ जिला-भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, छपरा, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, पं० चम्पारण शामिल बा।

3. भोजपुर क्षेत्र के लगभग 12 करोड़ लोगन के एक मात्र भाषा भोजपुरी ह।

4. भोजपुरी, भाषा एक समृद्ध भाषा ह, आउर संवैधानिक दर्जा ला निर्धारित सब शर्त के पूरा करे ले।

इ कवनो कृत्रिम भाषा ना ह, बल्कि हिंदी व उर्दू आउर अन्य भाषा के तरह जवन भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में दर्ज कइल गईल बा, आपन सांस्कृतिक आउर सामाजिक पहचान रख ले बाड़ी, तथापि, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही एके उचित संवैधानिक

मान्यता नईखे मिलल।

निर्विवाद सत्य इ बा कि कवनो भाषा या वस्तु के महत्व ओकरे व्यापक उपयोग आउर सामाजिक स्वीकार्यता से निर्धारित होला। यदि कवनो भाषा,लोगन के शिक्षा, प्रशासन व सामाजिक जीवन में अपनावल जाला, त ओकर सांस्कृतिक आउर सामाजिक मूल्य बढ़ी जाला।

एकरे बावजूद भोजपुरी के साथ अइसन व्यवहार ना भइल। जहाँ अन्य भाषा, जेकर बोले वालन के संख्या कम रहे, उनके संविधान के आठवीं अनुसूची में स्थान मिलल, वही जा भोजपुरी के दरकिनार कर दिहल गइल।

ए संदर्भ में वैश्य युगीन मानसिकता भी स्पष्ट रूप से देखल जा सके ला। प्रत्येक युग के आपन गुणधर्म होला, विशेषता होले। वैश्य युग जवन आज चल रहल बा, के भी आपन विशेषता बा, गुणधर्म बा। जनमानस ए विशेषता से गहराई से प्रभावित रहे ला।

वैश्य युग में जनमानस शिक्षा आउर अन्य कार्य के केवल धन व लाभ के दृष्टिकोण से आंकेला। संस्कृत में कहल गइल बा:

“यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः,  
स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः।

स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे  
गुणाः कांचनमाश्रयन्ति।।”

अर्थात्, जेकरे पास धन बा,उहे कुलीन व विद्वान मानल जाला, गुण व योग्यता भी धन के आधार पर मापल जाला स ए दृष्टिकोण में यदि कवनो

वस्तु आ कार्य धन उपार्जन के माध्यम नईखे, त ओकर मूल्य आउर सम्मान कम आंकल



जाला। भोजपुरी भाषा के साथ भी इहे स्थिति बा—एके केवल सांस्कृतिक दृष्टि से देखल गइल, लेकिन व्यावहारिक लाभ व धन के अभाव में एकर महत्व कम आंकल गइल।

हालांकि कुछ विद्यालय आउर महाविद्यालय में भोजपुरी पढ़ावल जाला, व नई शिक्षा नीति 2020 में भी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा के अनुशांसा कइल गईल बा, फिर भी लोग एकर उपयोगिता मूल्य नईखे देखेत। एकरें विपरीत, मैथिली भाषा के संवैधानिक मान्यता मिलला के कारण उहां के लोगन में भाषा के प्रति सम्मान आउर ओकर व्यावहारिक मूल्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहल बा।

आज जब हम अमृत काल मना रहल बानी जा, तब भाषा के महत्व पर ध्यान देहल अउरी आवश्यक बा स भोजपुरी, जवन भारत के कई राज्य के मातृभाषा व सांस्कृतिक धरोहर ह, आज भी संविधान के आठवीं अनुसूची में शामिल नयखे। इ केवल औपचारिक उपेक्षा ना ह, बल्कि संविधान के समानता आउर न्याय के सिद्धांत दृ जइसे अनुच्छेद 14 में कहल गइल बा

“सब कुछ कानून की दृष्टि में बराबर है”  
दृ के मूलभाव के प्रतिकूल बा।

यदि एक भाषा के, जवना के लाखों लोग बोल रहल बाड़े आउर अपनवले बाड़न, संविधानिक मान्यता ना मिलला से, इ प्रश्न उठेता कि समानता आउर न्याय के मूल्य कहाँ गइल? इ केवल भाषा के प्रश्न नइखे, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकार व पहचान के भी प्रश्न बा। अमृत काल में जब हम विकास, शिक्षा व संस्कृति के जश्न मना रहल बानी, तब इ अत्यंत महत्वपूर्ण बा कि भाषा के प्रति समान व्यवहार सुनिश्चित कइल जाव। भोजपुरी के साथ भइल उपेक्षा स्पष्ट करतेता कि भाषाई उपेक्षा व संवैधानिक अधिकार में असमानता अभी भी व्याप्त बा।

भाषा केवल संवाद के माध्यम ना ह, इ संस्कृति, इतिहास आउर सामाजिक पहचान के धरोहर ह।

इहाँ भाषा से तात्पर्य मातृभाषा से बा।

मातृभाषा उ भाषा ह जेकरे माध्यम से हमनी अपना भावना के सबसे स्वतंत्र, सहज आउर स्वाभाविक ढंग से अभिव्यक्त कर सके ली कृजइसे हमनी अपना माइ से संवाद करत समय करे ली।

भाषा के सामाजिक-आर्थिक प्रगति व सांस्कृतिक विकास के बीच गहरा आउर अविभाज्य संबंध बा। जवने प्रकार भाषा मनुष्य के अंतर्निहित भाव आउर विचार क वाहक ह, वोही तरह से उ ओकरे प्राणशक्ति से भी गहराई से जुड़ल बा।

कवनो व्यक्ति के अपने मातृभाषा में जेतना स्वतंत्रता व आत्मीयता से अपना भावना के व्यक्त करे के क्षमता होला, वोतना कवनो अन्य भाषा में ना होला। यदि कवनो व्यक्ति या समुदाय पर मातृभाषा के अतिरिक्त कवनो अन्य भाषा में लगातार संवाद करे के विवशता थोपल जाए, त उनके प्राणशक्ति धीरे-धीरे क्षीण हो जाई।

इ स्थिति वो व्यक्ति आउर पूरे समुदाय के मानसिक संकट में धकेल देला। परिणामस्वरूप उनमें हीन भावना घर करे लागेला, जवन मानसिक दुर्बलता के मूल कारण ह। जेकर

भाषा दबा दीहल जाला, उनके नैतिक शक्ति, कार्य-उत्साह आउर प्रतिरोध के क्षमता नष्ट हो जाला। अंततः उनमें पराजित मानसिकता विकसित होला, जेकरा कारण थोड़े समय में उनके प्राणशक्ति लगभग मृतप्राय हो जाला।

अतः भाषा के दमन मानव-मन पर घातक प्रभाव डालेला। इ दमन केवल संस्कृति के ही हनन ना करेला, बल्कि आर्थिक विकास के भी रोक देला। जवन समुदाय के भाषा दबा दीहल जाता, उ ना कबो सिर ऊँचा क के खड़ा हो पावेला आउर ना ही शोषण के चक्र से मुक्त हो पावेला। उ सदैव आर्थिक रूप से पिछड़ल रहे ला आउर शोषण के जाल में फँसल रहेला।

दुर्भाग्यवश, संपूर्ण विश्व, भारत सहित, ये त्रासदी से ग्रस्त बा। यही से अब कवनो भी परिस्थिति में भाषा के आउर अवदमन ना होखे के चाही। मातृभाषा के संरक्षण आउर

संवर्धन ही कवनो भी समाज के सांस्कृतिक अस्मिता व आर्थिक प्रगति के प्रथम शर्त ह।

अमृत काल में भोजपुरी भाषा के विकास।

भारत के आजादी से 75 वर्ष तक के काल खण्ड के अमृत काल कहल जाता।

एह काल खण्ड में भोजपुरी भाषा के विकास पर चर्चा के क्रम बतावल आवश्यक बा कि भोजपुरी संस्कृत मातृकुल क भाषा ह. एकरे भीतर भाव-अभिव्यक्ति क अद्भुत सामर्थ्य बा. विश्व क बरियार, मधुर, सरल आ तरल भाषा क संस्कृति केतना समृद्ध बा की सात समुन्दर पार जायियो के ना मिललाईल।

भोजपुरी भाषा क अतीत गौरव

शाली. रहल बा। सातवीं शताब्दी से आजादी के दिन तक तमाम संघर्ष के बादो आपन अस्तित्व बचा के रखले बा। जबकी विश्व क सैकड़ो भाषा काल के गाल मे समा गईली सन. इहे भोजपुरी भाषा के सामर्थ्य क बडहन प्रमाण बा।

इ भोजपुरीयन क मातृभाषा के साथ- साथे संस्कृति, अस्मिता, आ पहिचान ह. इनकरे रन्ध्र- रन्ध्र मे बा।

आजदी के बाद भोजपुरिया भाई बहिन के आशा ही ना पूरा विश्वास रहे की स्वतंत्र भारत में भोजपुरी भाषा के संवैधानिक दर्जा भी मिली आ भोजपुरी राज भी. पर आशा पर पानी फेर दीहल लोग।

इतिहास एह बात क गवाह बा की स्वतंत्रता के लड़ाई मे, भारत के समृद्ध बनावला में भोजपुरी :लोगन क सबसे बडा योगदान बा।

भोजपुरी जइसन स्वतंत्र, पूर्ण आ समृद्ध भाषा के उपभाषा. बोली कहल जाता.इ भोजपुरी क्षेत्र, आ भोजपुरियन के सीधे अपमान हवे। भोजपुरी भाषा के चार गो उपभाषा बाडीसन, काशिका, डुमरावी, चम्पारणी आ बस्तिया।

सबसे बडा दुर्भाग्य बा की भोजपुरी क्षेत्र के साहित्यकार लोग अपनी महतारी भषा भूला के दोसरा के सवारे सजावे मे लागि गईल.अइसन कवनो सांस्कृतिक प्रक्षेत्र मे ना पावल जाला।

भोजपुरी प्रक्षेत्र. के लोग अपनी मातृभाषा के आदर. नईखे करत. इ बात सही बा की

भाषा बा त संस्कृति बा, भाषा गईल त. कुच्छो नाही बची।

सब किछु के. बाद भी भोजपुरी भाषा आपन अस्तित्व बचा के अन्तराष्ट्रीय पहिचान बनवले बा।

भोजपुरी के उन्नायक लोग अपनी दम खम की साथे भोजपुरी के विकास खातिर प्रयास रत आ संघर्ष कर रहल बा लोग.आशा बा की नया इतिहास रचाई।

समाज में अईसन अवधारणा बनल रहे की भोजपुरी में काव्य ही लिखल जा सकेला. ई काव्य प्रधान भाषा ह. परन्तु एह मिथक के तूरी के आगे बढ़ि चलल बा भोजपुरी. भोजपुरी भाषा मे काव्येतर गद्य साहित्य क विकाश तेजी से हो रहल बा।

भोजपुरी प्रकाशन के सौ बरिस नाव के किताब के मुताबिक 1882 से 1992 तक 500 से अधिक भोजपुरी में किताब के प्रकाशन भईल. जवना में 76 कथा साहित्य, 82 नाटक, व 50 निबंध बा. 1982 से 2001 तक लगभग दुगुना हो गईल. आज पाच हजार से भी अधिक किताबन क प्रकाशन नईखे हो पावल। आज भोजपुरी भाषा मे गद्य के सगरो विधा मे साहित्य सृजन क होड लगल बा. जईसे निबंध, नाटक, कहानी, संस्मरण, उपन्यास, कथा, आदि।

खडी बोली समानान्तर भोजपुरी भाषा खडी बा. अन्य की भाषा के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दे रहल बा.

भारत के कई विश्व विद्यालय मे भोजपुरी क अध्ययन शुरू हो गईल बा। यथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा, हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, दीनदयाल

उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय. आज सैकड़ो छात्र भोजपुरी में शोध कर रहल बाने, केतना के पी. एच. डी. क उपाधि भी मिल गईल बा।

भोजपुरी क वैश्विक पहिचान बा, मारिशस मे राष्ट्रीय भाषा क दर्जा, फीजी में आधिकारिक भाषा के रूप मे मान्यता, नेपाल के दो राज्य के राजभाषा के रूपमे सम्मान मिलल बा।

पत्रकारिता के क्षेत्र में अद्भुत विकाश भईल बा. आज भोजपुरी क्षेत्र के हर जिला भोजपुरी क पत्रिका कवनो न कवनो रूप मे प्रकाशित हो रहल बा।

मिडिया आ सनेमा जगत मे भोजपुरी आपन. ताकत क एहसास करवले बा।

भोजपुरी सिनेमा क पहिलका फिलिम

गंगा मईया तोहे पियरी चढईबे, भोजपुरी भाषा के शीर्ष पर बईठा दीहलस. भोजपुरी फिलिमन क ताता लाग गईल।

भोजपुरी भाषा क व्याकरण, शब्दकोष क प्रकाशन भईल।

एह तरह से भोजपुरी भाषा क आशावादी भविष्य बा।

मानव विकाश क विस्तार जईसे जईसे हो रहल बा भोजपुरी भाषा क भी

विकास हो रहल बा. भोजपुरी भाषा गांव से शहर की ओर आपन पाव पसार रहल बा। मजदूर किसान के स्तर बढ़ला से भोजपुरी क स्तर बढ़ रहल बा।

भोजपुरी में विश्व के भाषा क शब्द आत्मसात करे के सामर्थ्य बा. एही कारण एकर भाव प्रकाशनी क्षमता शाक्ति काफी अधिक बा. विदेशज शब्द अईसे घुल मिलि गईल बा की पते ना चलेला की इ भोजपुरी के. ना हउए सन जईसे अचार, चाभी, झरोखा।

भोजपुरी भाषा के सामने कुछ चुनौती भी खडा बा। भोजपुरी के संवैधानिक दर्जा, गांव-गांव में अंग्रेजी स्कूलन क विस्तार, जवना से भोजपुरी के प्रति शंका आ अविश्वास पनप रहल बा।

बीच मे एगो अईसन समय आईल रहे की सिनेमा वाला लोग पईसा कमाये खातिर खटिया खडा क दिहले अश्लीलता परोसि के।

आज एह सब त्रासदी से भोजपुरी उबर रहल बा। भोजपुरिया अपनी मातृभाषा, संस्कृति के संरक्षण खातिर नव चेतना के साथ आगे आ रहल बा।

अतः भोजपुरी भाषा के भविष्य उज्ज्वल बा।

## पतझड़

विशाल यादव

ये पतझड़, बे पत्तो के पेड़  
कितने अजीब से  
लगने लगते हैं अचानक से  
  
अभी कुछ दिन पहले तो  
हरे भरे से थे  
अपने परम मित्र पत्तों के साथ  
डालियां अजब झूम रही थीं

हवा के झोंके जो पेड़ों को  
कभी मस्ती के साथ झूला झूला रहे थे  
आज ये हवाएं बेरहम होकर  
पत्तियों को पेड़ों से  
बेरहमी से अलग कर रही हैं  
  
अपनों से बिछड़ने पर  
क्या हाल होता है

यह हमें ये पतझड़ के पेड़  
सिखलाते हैं  
  
बिखरा सा जीवन और  
उसके नीचे बिखरे  
मुरझाए पत्तो जैसे सम्बंध

कैथीशंकरपुर, लालगंज आजमगढ़  
ईमेल : yvishal532@gmail.com



संस्कृत

www.kahaar.in

## ”गधस्य गर्वः च अधिकारीस्य बोधः”

गणेश बाजपेई

एकः निवृत्तः सचिव-स्तरीयः अधिकारीः स्वस्य निवृत्तेः अनन्तरं प्रथमां दीपावलीं अनुभवति स्म। पूर्वं तु दीपावलि-पूर्वसप्ताहे बहवः जनाः विविधानि उपहाराणि वहन्तः आगच्छन्ति स्म। उपहाराः अपि बहवः भवन्ति स्म, यथा तेषां कक्षः उपहार-दुकानावत् दृश्यते स्म। शुष्कफलानि अपि प्रचुरतः भवन्ति स्म।

किन्तु अस्य वर्षस्य दिवसे द्वौ घटीकौ अतीतौ, न कोऽपि मनुष्यः शुभकामनां दातुं आगतः। अधिकारीः दुःखितः अभवत्। मनः परिवर्तयितुं सः समाचारपत्रे आध्यात्मिकं स्तम्भं पठितवान्। तत्र गधस्य कथाऽभवत्कृ

एकः गधः देव-मूर्तयः पृष्ठे कृत्वा ग्रामान् अतिक्रामति स्म। जनाः ताः मूर्तयः दृष्ट्वा प्रणमन्ति स्म। गधः तु

अविवेकी, मन्यते स्मकृ “मां जनाः नमन्ति।” तस्मात् गर्वितः अभवत्।

यदा तु पूजा-स्थले मूर्तयः स्थाप्य, स्वामी सब्जीः गधस्य पृष्ठे न्यधात्, तदा कोऽपि तं न पश्यति स्म। गधः निराशः जाता, ध्यानाकर्षणाय पुनः पुनः रैति स्म। जनाः क्रुद्धाः भूत्वा तम् अताडयन्। गधः न जानाति स्मकृ “किं मया दोषः कृतः?”

एतत् वाचित्वा अधिकारीः अवबोधम् अवाप्तवान्कृ “यथा गधः मूर्तीनां कृते सम्मानं मन्यते, तथा अहं पदस्य कृते लभ्यमानं मानं स्वकीयम् इति मन्ये।”

सः पत्नीं सह दीपावलीं कर्तुम् इच्छन् आसीत्, किन्तु सा अवदत्कृ “अहं दीर्घकालं वदामिकृत्वं गधवत् आसीः। अद्य तु पत्रिकायां लिखितं सत्यं त्वं

स्वीकृतवान्!”

संदेशः

जो व्यक्ति अपने पद के अहंकार में लोगों से दुर्व्यवहार करता है, वह रिटायरमेंट के बाद अपमान और अकेलेपन का शिकार होता है।

सरल स्वभाव, विनम्रता और अच्छा व्यवहार ही जीवन को सुखी और सफल बनाते हैं।

सारः

यः जनः पद-बलम् आस्रित्य अत्यधि गर्व करोति, जनान् क्लेशयति, तस्य निवृत्तौ प्रायः अनादरः, आत्मग्लानिः च भवति। सुलभ-स्वभावः एव मानव-जीवनस्य सुगमता-समृद्धयोः मूलम्। अतः कार्ये व्यवहारश्च सादु भवतु, यत् जनाः स्नेहेन स्मरेयुः।

## एकत्व भाव

गणेश बाजपेई

आत्मीय स्वजन

अभिनन्दन

कबीर की पंक्तियां याद आ रही है जल में कुंभ कुंभ में जल है भीतर बाहर पानी फटा कुंभ जल जल ही समाना यह सत कहयो ज्ञानी

आपने सही ही लिखा है कि मानव जीवन के व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्रीय पथ पर यंत्रवत् दौड़ में प्रकृति से नैसर्गिक सम्बन्ध से जाने अनजाने भूल कर रहा है व जिस शाखा पर बैठ कर सुंदर फल लेता है उसी शाखा पर निरंतर प्रहार कर रहा है।

आपको “मेरे भीतर और बाहर एक पृथ्वी” के द्वितीय संस्करण पर अनेकानेक बधाई। निश्चित ही प्रबुद्ध पाठकों को यह बहुत पसंद आएगी।

शुभ मस्तु।

आत्मीय स्वजन! अभिनन्दनाः।

कबीरस्य वाक्यानि स्मरामि कृ “जले कुंभः, कुंभे जलम्; अन्तर्बहिर्मयं वारि। भग्नः कुंभः, वारि वारि एव समायाति कृ इदं सत्यं ज्ञानी उवाच।”

यथावत् भवान् लिखतिकृ मानवीयजीवनस्य स्वार्थपरायणा

चक्राकारगतिः यन्त्रचलनवत् धावन्ती, प्रकृतेः सह नैसर्गिकसम्बन्धं जानन्नपि न जानन्न वा विस्मरति; या शाखा उपविष्टः सन् रम्यफलानि लभते, तस्याः एव शाखायाः पुनः पुनः प्रहारं करोति।

“मम अन्तः बहिश्च पृथिव्येकैव” इति ग्रन्थस्य द्वितीयसंस्करणे भवतोऽनेकान्यभिनन्दनानि।

नूनम् प्रबुद्धपाठकानां हृदयेषु एषः ग्रन्थः अतीव रोचिष्यते।

शुभम् अस्तु।

## Development of Banana Plantlets through Micro propagation Techniques

Uttam Kumar, Dr. R. S. Sengar, Dr. Nidhi Singh and Garima Sharma

### Introduction

Banana (*Musa* spp.) is not only a fruit but also a food security crop, a livelihood avenue, and an income generator for millions of producers across the globe, more especially the tropical and subtropical nations. It is a perennial crop and can be sustained for up to 7 years or more. India is the world's largest producer of banana, accounting for almost 25% of global production. In India, bananas can only rank second after the mangoes in area and production and therefore provide an agricultural lifeline for small and marginal holders. Major banana producing states are Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka and Gujarat. In Uttar Pradesh, cultivation of banana spread over more than 68,000 hectares. The leading banana producing districts in Uttar Pradesh are - Lakhimpur Khiri, Kushinagar, Maharajganj, Prayagraj and Kaushambi. However, where they are quite prominent, one of the principal problems in banana production is the procurement of healthy and uniform plant material.

Traditionally, bananas were propagated through suckers. Although it is simple, it is a slow process and produces only a few plants. Worse, suckers typically

carry pests and plant diseases from the mother plant and cause lower yields and greater losses. This is where Science stepped in to the rescue with a novel technology – micro propagation through tissue culture.

### What is Micro propagation?

Micropropagation involves the culture of vast quantities of similar plants from small plant tissue under sterile and regulated laboratory situations. In vitro clonal proliferation is another name for it. In bananas, the



*Figure 1. Working On Laminar Air Flow for Plant Inoculation*

technique benefits from the totipotency of the plant – i.e., the capacity of the single cell to regenerate into an entire plant if proper environment is presented.

No longer do they require gigantic suckers; they can start with tiny fragments of meristem tissue, culture them on nutrient media, and recover thousands of single, uniform, and virus-free banana plantlets.

### Advantages of Banana Micro propagation

- **High multiplication rate:** Thousands of plants can be derived from a single explant.
- **Disease-free plants:** Meristem culture eliminates systemic pathogens.
- **Genetic uniformity:** Clonal propagation ensures identical progeny.
- **Year-round production:** Independent of seasons.
- **Synchronized growth:** Enables uniform flowering and harvesting.
- **Economic benefits:** High benefit–cost ratio for farmers

### Timeline for Banana Tissue Culture

Banana plantlet production through tissue culture is a multi-step process the length of which for each step is predetermined:

**Culture initiation:** 3–4 weeks for the initiation of the shoot tip.

**Shoot multiplication:** subculture cycle of 4–6 weeks; 5–7 cycles.

<sup>1</sup>Division of Plant Biotechnology, College of Biotechnology, Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology, Meerut  
\*Corresponding author email : sengarbiotech7@gmail.com



Figure 2. Banana Plant

**Rooting:** 2-3 weeks.

**Hardening (shade net + greenhouse):** 6-8 weeks.

**Field-ready plantlets:** ~5-6 months from the day of explant initiation.

So, within 150-180 days, a small meristem develops into a full-fledged banana plantlet for the farm.

### Tissue culture banana plant prices

The cost per plant of tissue-cultured (TC) banana plantlets available in Indian commercial nurseries ranges from ₹12-15.

Farmers normally require 1,800-2,000 plants per acre (~5,000 plants per hectare)

Sowing one hectare would cost around ₹60,000-75,000.

Although the start-up cost is higher compared to growing with suckers, the payoff is greater because of the superior quality and harvest.

### Benefits for Farmers per Hectare

**Yield benefit:** Tissue cultured bananas produce 60-80

tonnes/ha, versus the 30-40 tonnes/ha from classical.

**Uniform maturity:** The plants flower and fruit at one time, enabling single harvest and labour-saving.

**Disease-free plants:** Losses reduced from Panama wilt, viruses, and nematodes.

**Higher incomes:** Under market prices, a representative farm can receive ₹2.5-3 lakh per ha, typically twice the net returns of the conventional system

### Plant tissue culture establishment cost of a unit

Set up of Plant Tissue Culture (PTC) unit involves special facilities:

**Small-scale laboratory (capacity: 1-2 lakh plantlets/year):** ~₹25-30 lakh.

**Medium-scale commercial unit (5-10 lakh plantlets/year):** ~₹50-60 lakh.

**Industrial scale plant (>20 lakh plantlets/a):** ₹1 crore or more, depending on automation and bioreactors.

In spite of the investment, private laboratories and cooperative undertakings make it worthwhile since the demand for tissue-cultured banana plantlets is strong and increasing.

### Life Cycle of Banana Plantlet

**Mother Plant Selection:** Healthy sword suckers from disease-free plants (50-60 days old).

### Aseptic Culture Initiation

1. Wash explants under running tap water (15-20 min).
2. Treat with detergent solution (0.1% cetrimide, 10 min).
3. In laminar hood:



Figure 3. Working in Culture Room

- Dip in 70% ethanol (30-60 sec).
- Treat with 0.1% Hg-Cl<sub>2</sub> (8-10 min) or 2% NaOCl (15-20 min).
- Rinse 3-4 times with sterile distilled water.

**Shoot Multiplication:** Meristems sterilised and sown upon MS medium. Clusters of shoots generated using cytokinin. 6-7 subculture cycles produce large clusters of shoots.

**Rooting:** Transplanting plantlets (4-5cm) into auxin-containing medium. Roots within 2-3 weeks.

### Hardening and Acclimatization

**Primary Hardening-** Plantlets washed free of agar, transferred to trays with cocopeat/sand under greenhouse (24-26 C, 90-95% humidity, diffused light).

**Secondary Hardening-** Transfer to polybags with soil:sand:FYM (1:1:1), fungicide dip (e.g., 0.1% Bavistin) prevents infections.

**Planting Field:** Transplant into



Figure 4. Banana Plantlets

the field when plantlets are ~6 months old. Survival rates exceed 90% under proper management.

### Conclusion

Banana tissue culture has transformed banana agriculture. Within six months, a tiny drop of meristem under the microscope develops into a stately plantlet. With a minimal investment of just ₹12-15 per plant, the farmers can plant healthy, uniform, pathogen-free crops yielding almost double the output as compared to the traditional system. Bananas are grown on >0.9 million ha, with continuous demand for

disease-free plants. With tissue culture plants yield increase to 60-80 tonnes/ha compared to 30-40 tonnes/ha with suckers. For the farmers, it means higher yields, balanced harvests, better quality bananas, and more stable incomes. For India, it means better food security, better export opportunities, and sustainable agriculture. Tissue culture is more than a laboratory technique—it is a tool of empowerment for rural farm communities.

“ओस की बूंदें,  
चिड़ियों की किलकारियाँ,  
आँख मलता सूरज।

धुंधली होती रात,  
गौत गाती हवा।

बाज़ार में कुछ भी नहीं मिलता,  
चलो मेरे गाँव चले।”

-तरुण सैंगर

## Hydroponics: Boon for Urban Farming

Nidhi Singh, R. S. Sengar, Aditya Das, Garima Sharma and Sangam

### Hydroponics in Urban Agriculture

Hydroponics is simultaneously a game changer in terms of agricultural practices for the 21st century as well. Hydroponics a soil-less cultivation that allows plants to grow in nutrient-rich water solutions is seen as an attractive solution for the many challenges global agriculture faces, due mainly to issues like water scarcity, climate change, land degradation and stronger worldwide food demand. Hydroponics is a cultivation practice done without soil, but also with full supply of nutrients for plants.

### What is Hydroponics

It is a plant growing technique without using soil and here mineral nutrient solutions are added in an aqueous solvent. Plants get immediate access to water, minerals and oxygen by using nutrients solutions read to perfection so that plant growth is far superior in comparison with plant development via traditional soil farming. The roots are held up by inert growing mediums, such as perlite/vermiculite (to create space for the roots) and/or rockwool/coco coir to provide support while not adding any nutrients.

### Types of Hydroponic Systems

**1. Nutrient Film Technique (NFT)** – A shallow stream of

nutrient-rich water continuously flows along sloped channels, which work best for lightweight leafy vegetables such as lettuce and strawberries, etc.

**2. Deep Water Culture (DWC)** – plants are positioned on floating rafts with their roots hanging in the oxygen-rich nutrient solution, useful for large plants with long root systems, such as tomatoes, peppers or cucumbers.

**3. Drip Systems:** It will deliver the nutrient straight to plant roots by passing it through a controlled drip suddenly, and this system is compatible with most of the vegetables, fruits, herbs, lowers.

**4. Ebb & Flow** – Periodically floods growing areas with nutrient solution, then drains back to reservoirs; capable of supporting a wide variety of crops (from strawberries to radishes)

**Aeroponics:** A technique that suspends the plant roots in air & misting them with nutrient solutions to achieve a super-charging growth.

**How this innovative approach is affecting urban people**

### More Fresh, Healthy Food

The hydroponic farms in urban locations can be made on roof-

tops, balconies, basements and open fields which allows the local supply of products. The ability to grow produce near where it is consumed – usually closer than a mile, making this the agricultural analog of farm-to-fork – is an opportunity for city residents to eat more fresh, local food throughout the year that can walk out storefronts potentially within hours or even minutes of harvest in case traditional transport methods fail due to interruptions if or when delivered in normal scope.

**Nutritional Quality:** As compared to the traditional farming of crops, those that are grown with hydroponic systems have higher nutritional value and are not exposed to dangerous pesticides.

### More Space and Water Efficient

Advances in hydroponics could lead to high-density, vertical farming in the heart of cities producing healthier food for urban dwellers. 5 to 10 times more food per sq meter compared to traditional. Recirculating 90% of the water, these systems use of a fraction of the water that our cities are becoming increasingly stressed to supply and reduce demand on the urban system from food production.

<sup>1</sup>Division of Plant Biotechnology. College of Biotechnology, SVPUAT, Meerut-250110

\*Corresponding author email : sengarbiotech7@gmail.com

## Environmental Benefits for Cities

**Shorter food miles:** Food travels a shorter distance, reducing the carbon footprint and ensuring fresher produce with less spoilage from transit.

### Greening Urban Spaces:

Through this, white areas are being turned into green hydroponic farms using the old buildings, roof tops or vacant lots as the air is also going to be clean and look nice in cities. Soil-less farming with hydroponics can reduce the use of resource also it saves land that might have been you used if not made to use, doesn't allow soil to break down which reduces factors like those related to desertification and may also need less of synthetic fertilizers and chemicals. so in total, it is a better practice for sustainable living in dense urban areas.

## How it can be popularized among rural and urban area

### Strategies for Rural Areas

- **High government initiatives & financial support** in the form of Schemes like PM-KUSUM, Agri-Infra Fund (to reduce equipment costs), and solarized hydroponic farms.
- **Demonstration Projects** - Create pilot units in villages and agricultural colleges to demonstrate benefits on fodder production for livestock or higher crop yields with minimal water.
- **Local Partnerships:** NGOs, farmer groups, and agricultural extension services may establish model units and provide training to local farmers as well as ongoing technical support.

- **Education:** Initiate practical workshops, and mentoring programs for farmers. Another way to engage the youth locally is for rural schools and colleges by adopting hydroponics into their curriculum.
- **Community Gardens:** Create a community-owned hydroponic projects for farmers to pool resources and knowledge, deploying adoption in a cost-effective and cooperative manner.
- **Demonstrate success stories:** focus on farmers in the communities who have experiences of increased earnings or being able to manage climate problems by the means of irrigation and use radio, local newspapers for sending out a message.

### Strategies for Urban Areas

**Awareness Campaigns:** conduct workshops, food festivals and tastings to make the general public educated about hydro produce and its health & sustainability benefits.

**Overreach and Linkages:** Work with urban schools, colleges & community centers to demonstrate hydroponics through hands-on training & rooftop gardens.

**Digital Media Usage** - To capitalize on broader audience outreach, pair with social and social influencers as well as virtual walkthroughs bringing the hydroponics kits to city-based dwellers.

**Policy & Incentives:** Help promote pro-agriculture municipal policy, like supporting urban agriculture with exemptions of zoning law and subsidies for the rooftop farming programs

integrated within city plans.

**Corporate, Institutional Engagement:** Develop hydroponic farms in hotels, restaurants and office buildings for fresh, hyper-local produce as part of green building initiatives.

## Scope and Prospects of Hydroponics in Agriculture

### Scope of Hydroponics

The hydroponics scope of application is rapidly expanding, defining this technology as core in diverse agricultural environments, predominantly urban and rural. Some of the factors that define the scope of hydroponics include:

- **Leadership Resource Efficiency:** if the current trends continue, trillion hydroponics uses up to 90% less water and does not necessitate land. This is due to established knowledge about global water scarcity incidences and the continuously reducing land; Limited experience and resource allocation knowledge about hydroponics production processes.
- **Yield Enhancement:** Hydroponics can lead to an additional yield of up to 50% in one year. This is mainly as a result of several yield annual cycles overtime. Urban Integration: cutting across all urban and urban components, hydroponics can be incorporated in the rooftop, basement, everyday container, and indoor vertical gardening. As such, there is reduced post-harvest food loss since food components are grown in the city.

- **Quality and Consistency:** regardless of setting or preference, hydroponically grown crops guarantee quality. Most consumers demand pure products. Leading factors in enhanced Qualitative yield include uniformity, disease and chemical contaminations free products.
- **Technological Revolution:** conversely, large-scale production is accomplished through automation, and through the installation of AI, IoT, and weather intelligent installation, production became more efficient and cost-effective. Systems require less space set-up and operational cost has been within comfortable market prices. Government and Policy support: sustainable government, expertise, and farmer incentives and subsidies demand and support education of this technology. Climate Resilience: a conducive climate

has always attracted farming opportunities, but hydroponics has several mechanisms to withstand climate threat factors. These factors include minimum vulnerability caused by soil degradation, excessive humidity and decrease monsoon leading to droughts.

### Prospects for Hydroponics

**Growing Market:** As per study, Hydroponics market is expected to grow at a CAGR of 13.11-20% globally by 2033 and expected to move up at USD \$32.10 Billion.

**Urban and Rural Adoption** -Due to the flow of community gardens and demonstration projects, use of hydroponic methods are increasingly being adopted for fresh produce, fodder and specialty crops in both cities as well villages.

**Workplace Integration:** In 2025, more than 30% of global tech office will become a demonstration site for the new workspace and wellness solution hydroponic systems.

**Development Support:** Hydroponics is a great tool for many of the U.N. Sustainable Development Goals, particularly water management and zero hunger; as such, it should form part of any strong sustainable agriculture policy.

**Supply Chain Resilience:** Local container farms and vertical hydroponics protect against global supply chain instability by guaranteeing a constant source of fresh, safe food.

**Technology Innovations:** Automation, Smart Systems & Modular Vertical Farming Towers for Commercial Producers and Backyard Gardeners respectively

**Battle Mitigation:** Hydroponics will continue to come better equipped to fight; not that it is necessarily a war- hydroponic costs of entry are dropping while knowledge and partnerships spread, opening up use cases for hydro growing small scale land-based crops.



Hydroponics Crops



## Indian Soil Health: A Mini Review

Shivam Singh<sup>1</sup>, Ankit Tiwari<sup>2</sup>, Jagannath Pathak<sup>3</sup>,  
Mahendra Pratap Singh<sup>4</sup>, Satendra Kumar<sup>5</sup>

### Abstract

*Soil health underpins India's food security, rural livelihoods, and climate resilience. This review synthesizes the status of Indian soils across agro-ecologies, key biophysical and socio-economic drivers of degradation, and evidence-based interventions spanning on-farm practices, policy instruments, and emerging technologies. It highlights lessons from the Soil Health Card (SHC) program, integrated nutrient and residue management, and biologically driven approaches that enhance productivity while curbing input intensity and disease pressure. The review closes with research and policy priorities to accelerate scalable, context-specific soil stewardship in India's diverse landscapes.*

### 1. Introduction

India's soils carry an outsized burden: feeding over a billion people, buffering climate volatility, and sustaining biodiversity in some of the world's most intensively farmed landscapes. Yet decades of input-heavy cultivation, fragmented landholdings, and climate stress have strained physical structure, nutrient balances, and soil biology. A soil health lens—integrating chemical, physical, and biological indicators with farmer realities—offers a coherent pathway

to more resilient, profitable agriculture.

### State of Indian soils

Indian soils vary from alluvial Indo-Gangetic plains to black cotton Vertisols, red lateritic uplands, and coastal saline/sodic tracts. Across this diversity, recurrent issues include low soil organic carbon (SOC), multi-nutrient deficiencies (notably N, P, K with emerging S, Zn, B), compaction in intensively irrigated systems, and salinity/sodicity pockets in canal commands and arid/semi-arid zones.

- **Core indicators:** SOC, pH, electrical conductivity, bulk density/aggregate stability, available N–P–K, secondary and micronutrients (S, Zn, B, Fe, Mn), cation exchange capacity, microbial biomass/activity, and enzyme assays.
- **Major drivers:** Cropping intensity and residue removal/burning, imbalanced fertilization, limited organic returns (manure/compost), suboptimal irrigation quality and drainage, mechanization-induced compaction, and climate variability altering mois-

ture-temperature regimes.

- **Regional note (Indo-Gangetic plains/UP):** Rice-wheat systems face SOC decline, surface compaction from puddling, periodic Zn deficiency, and residue management challenges—making conservation tillage, residue retention, and balanced nutrients especially consequential.

### Interventions and policy

India's policy and practice landscape spans advisory tools, incentives, and agronomy that collectively shape soil outcomes.

- **Soil Health Card (SHC) program:** Periodic soil testing with site-specific fertilizer recommendations has shown promise, with reported gains of about 5–6% in yields and reductions of 8–10% in chemical fertilizer use, contributing to lower input costs and environmental benefits.
- **Balancing nutrient paradigms:** Evidence and farmer experience caution against a narrow chemical-fertilizer focus; enabling the use of locally available organic inputs alongside fertilizers

<sup>1</sup>Krishi Vigyan Kendra Sultanpur, Acharya Narendra Dev University of Agriculture and Technology, Ayodhya;

<sup>2</sup>Birsa Agriculture University, Ranchi; <sup>3</sup>Banda University of Agriculture and Technology, Banda;

<sup>4</sup>Krishi Vigyan Kendra Sonbhadra, Acharya Narendra Dev University of Agriculture and Technology, Ayodhya;

<sup>5</sup>Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology, Meerut

Corresponding author email : shivambuat@gmail.com

strengthens fertility, buffers shocks, and aligns with livelihoods in drylands.

- **Disease-suppressive management:** Crop rotations, cover crops, organic amendments, quality compost, mulching, good aeration, biological control agents (PGPR, arbuscular mycorrhizae), and fostering suppressive soils can reduce soil-borne diseases by competition, antibiosis, parasitism, ISR, and physical barriers—improving soil function and yields sustainably.

### Management strategies and case insights

A resilient soil strategy layers practices to rebuild carbon, balance nutrients, and activate biology while fitting local constraints.

- **Organic matter pathways:** Incorporate crop residues (retain/mulch), farmyard manure, compost, green manures (dhaincha, sun hemp), and biochar where viable to raise SOC and aggregate stability.
- **Integrated nutrient management:** Blend soil test-based NPK with organics, secondary/micronutrients, and site-appropriate biofertilizers; time applications to crop demand and split N doses to boost efficiency.
- **Conservation agriculture:** Reduce tillage intensity, maintain soil cover, and diversify rotations/intercropping (e.g., legumes)

to protect structure, moisture, and biota.

- **Water and salinity management:** Improve drainage, adopt laser land leveling, use gypsum in sodic soils, and prioritize efficient irrigation (drip/sprinkler) with water quality monitoring.
- **Biological protection:** Deploy PGPR and mycorrhizal inoculants, compost teas of verified quality, and rotation breaks to manage pathogens while enhancing nutrient uptake.
- **Local adaptation (Uttar Pradesh):** In rice-wheat belts, pair zero-till wheat with rice residue retention, include short-duration legumes, address Zn/S hotspots via soil test-guided supplements, and explore direct-seeded rice to reduce puddling-induced compaction.

### Emerging tools and research priorities

Digital, diagnostic, and institutional innovations can accelerate impact if grounded in farmer contexts.

- **Diagnostics and data:** Densify soil testing with robust QA/QC, spectral soil libraries, and decision tools that translate lab values into simple, field-ready advisories.
- **Carbon and biology:** Standardize rapid measures for microbial biomass, enzymes, and particulate organic matter as leading indicators; quantify carbon sequestration co-benefits in major systems.

- **Input efficiency:** Advance enhanced-efficiency fertilizers, nanofertilizers, and precision placement; rigorously evaluate cost-benefit and risk.
- **Landscape approaches:** Integrate sodic/saline reclamation, groundwater governance, and residue supply chains (e.g., bioenergy, composting) with village-level planning.
- **Policy and incentives:** Align subsidies and credit with soil-building practices; strengthen last-mile extension, custom hiring centers for CA equipment, and market pull for sustainable produce.
- **Evidence gaps:** Long-term, agroecology-specific trials on stacked practices; disease-suppressive soil development timelines; scalable models for organic resource logistics; and distributional impacts on smallholders and tenants

### Conclusion

Indian soil health will be rebuilt by combining rigorous diagnostics, farmer-proven organic and conservation practices, balanced nutrient strategies, and policies that reward stewardship. Programs like SHC provide a scaffold for site-specific action, while biologically informed disease management closes the loop between soil function and plant health. The task now is to scale context-sensitive bundles—with strong extension and incentives—so soils can carry India's food, climate, and livelihood ambitions.



# Organic Farming and Its Role in Sustainable Agriculture: A Short Review

Devesh Kumar Shukla and Sushmitha Baskar\*

## Abstract

*Organic farming is an approach to agricultural production and processing that combines responsibility, creativity and innovation in protecting our environment. It seeks to address the chemical-based farming practices and employ excellent farm management practices with more natural processing techniques. We are directly dependent on agriculture for our existence, and food health is directly related to human health. Organic farming hosts more living organisms such as plant diversity, birds, insects of various kinds and pollinators. These organisms restore the ecological balance by increasing soil fertility and possess natural pest regulatory mechanisms. Chemical-based farming practices have irreversible environmental and human health impacts. Therefore, we must adapt our agricultural practices to eco-friendly farming to prevent environmental pollution and biodiversity loss. This short review discusses the role of organic farming practices in sustainable agriculture and addressing the sustainable development goals (SDGs).*

**Keywords:** Organic farming, Sustainable agriculture.

## Introduction: Organic farming and sustainability of agricultural systems

Organic farming or green farming is an agricultural system that solely depends upon natural ecological processes, bio-

diversity, and various biological cycles to maintain productivity by avoiding synthetic fertilizers, pesticides, and genetically modified organisms (GMO). According to Gamage et al. (2023), organic farming leads to agricultural sustainability by improving soil health, enhancing nutrient cycles, and reducing environmental pollution caused by chemicals used for fertilizer and pest management. Research suggests that for long-term soil fertility, it is important to maintain the organic systems by allowing organic matter addition and reducing soil degradation (Gamage et al., 2023).

Research has proven and given more clarity about organic farming, which promotes sustainability by lowering the dependency on non-renewable resources and minimizing the negative consequences such as groundwater contamination and greenhouse gas emissions (Reganold & Wachter, 2016; Ikerd, 1993). Many practices, such as adopting crop rotation, green manuring, and biological methods of pest control, organic systems that strengthen ecosystem resilience and reducing vulnerability to climate variability have been reported (Reganold & Wachter, 2016). Conventional agricultural practices contribute to greenhouse gas emissions, soil

and groundwater pollution causing environmental and human health risks. Green farming on the other hand enriches the soil and replenishes the ecosystem health.

However, sustainability assessments also detail us about their limitations. Whole on one hand organic farming improves environmental sustainability, on the other hand, there is economic and productivity challenges, particularly during the initial conversion phase. Gamage et al. (2023) reported that yield instability and labour intensiveness are the main constraints, indicating that organic farming sustainability depends on supportive policies and improved management practices. Francis (1990) reported some misconceptions related to sustainable agriculture and emphasized that collaborative and practical applications are necessary within systems for successful sustainable practices.

## Does organic farming benefit biodiversity?

Biological conservation research has widely studied the relationship between organic farming and biodiversity. Hole et al. (2005), one of the most cited reviews, inferred that green farming generally supports higher species richness and

abundance as compared to traditional farming. Plants, insects, birds and soil organism's diversities were more in organic fields in the absence of synthetic pesticides and fertilizers (Hole et al., 2005). Later, the studies published in biological conservation by Sidemo-Holm et al. (2024) confirmed that lands under organic farming often provide favorable habitats for wild flora and fauna, especially in intensively managed agricultural landscapes. The authors claimed that organic farming increases landscape heterogeneity, which supports pollinators and natural enemies of pests (Sidemo-Holm et al., 2024). Despite all these benefits, biodiversity gains are not universal. Hole et al. (2005) also reported that biodiversity outcomes depend on the crop type, farm management intensity, and surrounding land use. Thus, organic farming alone may not guarantee biodiversity conservation unless combined with broader landscape-level ecological strategies.

### How sustainable is organic farming?

The concept of sustainability in agriculture comprises environmental integrity, economic viability, and social well-being. Organic farming is considered as environmentally sustainable due to its avoidance of chemical use and improved soil biological activity. Reganold and Wachter (2016) reported that organic farming system enhances ecosystem services such as soil carbon sequestration, water regulation, and less energy use compared to conventional farming. From a resource-use perspective, Gamage et al. (2023) reported that

organic farming reduces dependency on synthetic fertilizers, which are energy-intensive to produce specially for nitrogen-based fertilizers and contribute significantly to greenhouse gas emissions. Nevertheless, sustainability assessments also highlighted trade-offs. Borghino et al. (2024) observed that organic farming typically gives lower yields per unit area, which is concerning its capacity to feed a global increasing population. Their research argued that organic farming becomes more sustainable when done with changes in consumption patterns, reduction in food waste, and technological innovation (Borghino et al., 2024).

### Organic farming with Ancient Indian Knowledge

Another important ancient Indian tradition is to be cited in this context. Panchagavya which is an Indian nutrient power mix containing cow-based ingredients such as milk, ghee, curd, cow urine and cow dung has proved useful in organic farming. Panchagavya and 'Cowpathy' is employed in agricultural, medicinal and ritualistic procedures. A recent report emphasized the indigenous properties of panchagavya on disease and pest control, its biostimulant activity and soil structure improvements (Srinivasan and Aithal, 2025). The authors also suggest that the mixture helps in the natural growth of plants and in the production of healthy food products. Further experimental field research suggests that the addition of panchagavya increases the yield of turmeric by 22% and of cucumber by 18% (TNAU, Coimbatore). Also,

flowering is there throughout the year, the fruits are plumpy and tastier and the shelf life is extended by ten days (TNAU, Coimbatore).

### Sustainable farming without organic products

Organic farming practices can be applied even when agri-products are not marketed or certified as organic. Many farmers adopt organic practices to improve soil health and its environmental quality rather than to access organic markets. The farmers follow ecological farming methods without going for certification due to high costs or market limitations. According to Reganold and Wachter (2016), non-certified organic practices still contribute to sustainability by reducing chemical dependency and improving farm resilience as the organic supplements are used together. Such systems allow more flexibility but with a slow and continuous transition towards sustainability while maintaining farmer's autonomy. Although the approach may not provide high revenue as compared to organically labelled, but it plays a significant role in promoting environmentally friendly agriculture, specifically to those regions where certification infrastructure is poor or consumer demand for organic products is limited.

### Organic farming and small-scale farmers: Main opportunities and challenges

Organic farming has both opportunities and challenges for small-scale farmers. According to studies published by researchers, organic package of practices can reduce the cost of production by

minimizing external inputs, which is profitable for resource-poor farmers (Pretty et al., 2018). Smallholders often use locally available organic inputs, making farming attractive both in terms of economy and sustainability for longer terms. A study by Pretty et al. (2018) explains that organic farming increases employment opportunities and strengthens the local knowledge systems through farmer-to-farmer learning. Proper certification and market access to organic products can further improve household income. However, during the initial transition phase, small-scale farmers face significant challenges in terms of yield reductions, increased labor demands, and limited access to technical knowledge. Certification costs and compliance requirements are the major barriers, especially in developing countries like India (Pretty et al., 2018). Table 1 gives a comparative account of traditional and organic farming practices.

### Risk and opportunities of increasing yield in organic farming

In organic farming yield performance always remains as one of the most debatable topics.

Borghino et al. (2024) reported that crop yields under organic farming systems are lower than those achieved in farms that uses synthetic fertilizers and chemical inputs, especially in the case of cereal production. Limited nutrient availability, increased pest incidence, and strong weed competition were highlighted as the main factors restricting yields in organic agriculture. Despite these identified challenges, several opportunities are available to enhance productivity. Practices such as scientifically planned crop rotations, including the incorporation of legumes, along with improved compost management, can considerably improve nutrient availability (Gamage et al., 2023). Advancement in biological pest management techniques and ongoing research on soil microbiomes are offer encouraging approaches for improving yields. Nevertheless, increasing organic production without maintaining ecological balance may reduce its environmental advantages. Additionally, the benefit of integrating microbiome-based techniques into existing farming methods is emphasized to guarantee agricultural yield with fewer negative environmental

effects. The microbial-based technique can be utilized to increase crop yield under organic farming without significant land-use changes and agricultural expansion, especially considering climate change (Azarbad, 2022). Natural hazards, and other climate-related disasters have had a significant impact on agricultural productivity in recent years. Globally, to meet the demand for more food production, agricultural intensification is anticipated to rise. Crop stress tolerance is greatly enhanced by a variety of bioactive natural compounds produced by soil-plant microorganisms. Therefore, optimizing the effort to engineer a plant microbiome that can better support productivity in agroecosystems requires a thorough understanding of the effects of both conventional and organic farming practices and climate conditions on soil-plant microbiome interactions (Azarbad, 2022). Consequently, strategies aimed at improving yields should be consistent with organic farming principles to ensure that sustainability is not compromised (Borghino et al., 2024).

**Table 1. Traditional Vs Organic farming practices**

S. No.	Techniques employed/Risks involved	Traditional farming	Organic farming
1.	Farming technique	Synthetic/ chemical based	Organically sourced substances
2.	Fertilizers	Chemical-based, urea	Organic fertilizers, manure, compost
3.	Eco-friendly/Sustainable	Non-sustainable	Totally sustainable, eco-friendly
4.	Disease resistance	Highly adapted for disease resistance	Vulnerable to pest attacks and diseases
5.	Human Health risks	Extensive health risks due to an array of chemicals used	Zero health risks

### Package of practices

Organic farming may look like a new concept, but it is a much older concept than the chemical-based agriculture. After the industrial revolution the use of chemical supplements in the form of fertilizer and chemicals to protect crop with pest has increased, which increases the crop yield up to manifolds. But continuous use of these chemicals leads to disturbances in soil ecology thus disturbing the natural fertility. To overcome this, natural occurring organic substances can be used for every aspect of farming such as well decomposed Farmyard manure (FYM), various composts along with green manure used as nutrient supplements and ashes and Gomutra used in crop protection. For more sustainable practices, proper crop rotation which includes legumes and green manuring crop in between like Sunhemp, Dhaincha, Mesta,

and Glyricidia promotes sustainable practices and reduces soil fungal diversity (Bainard et al. 2017). When it comes to land utilization, organic agricultural methods differ from conventional agriculture. Green farming is often viewed as an ecological friendly farming practice (Bengtsson et al., 2005; Gattinger et al., 2012; Tuck et al., 2014). But in the present world scenario organically produced crop yields are 25% lower compared to synthetic farming methods (De Ponti et al., 2012; Ponisio et al., 2015; Seufert et al., 2012). Studies have also reported nitrogen deficiency in organic farming. Barbieri et al. (2017; 2023) reported that crop rotations and intercropping pattern leads to greater diversity and more evenly distributed crop species. The increased complexity of organic crop rotations is likely to improve ecosystem service provisioning to agroecosystems, and these improvements are

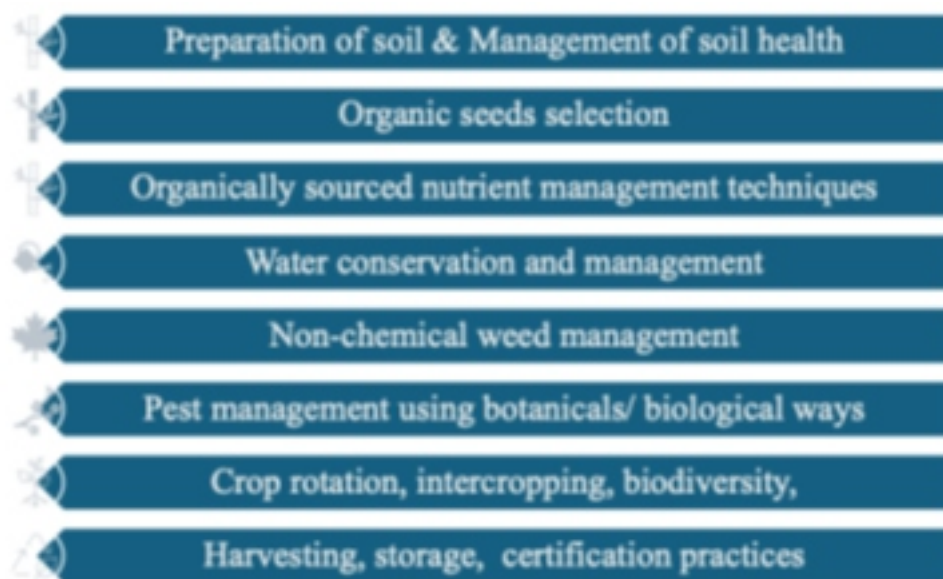
driven by a greater abundance of catch, cover crops, and temporary fodders Barbieri et al. (2017). Table 2 and Figure 1, 2 details some farming techniques and benefits of organic farming for sustainability.

### Conclusion

Green farming addresses mitigation of climate change by totally excluding the fossil fuel intensive chemical fertilizers. Natural techniques help preserve biodiversity and the planet's natural resources. Green farming technology is vital for achieving the sustainable development goals (SDGs). This agricultural farming rightly balances and stabilizes environmental sustainability, and socio-economic development. Organic farming creates an array of job opportunities world over and supports several rural livelihoods. Further in addition to preserving the soil fertility and soil structure it also helps to

**Table 2. Some farming techniques and benefits of organic farming**

S. No.	Farming Technique	Ingredients/ Nutrients/Type of technique used	Benefits
1.	Panchagavya	Cow milk, curd, ghee, cow urine, dung	Increases soil health, flowering, fruit health and yield
2.	Gomutra	Nitrogen, potassium, phosphorus	Enhances soil productivity
3.	Cow dung	Nitrogen, potassium, phosphorus	Soil fertility, plant growth
4.	Crop rotation	Alternating crop types	Improves soil fertility and health
5.	Green Manure	Specific crops grown such as legumes	Improves soil structure
6.	Zero till farming	Reducing disturbances to soil	Enhanced soil structure, no soil erosion
7.	Mulching	Covering soil with straw, leaves – organic based	Reduction in weeds, Soil temperature maintained
8.	Sustainable Water Management	Rainwater harvesting, drip irrigation	Water conservation
9.	Bio-pest control	Natural predators – Ladybug, Neem based products	Sustainable pest management
10.	Composting	Applying compost – decomposed organics	Enhances soil microbiome
11.	Agroforestry	Various tree species - intercropping	Enhances biodiversity

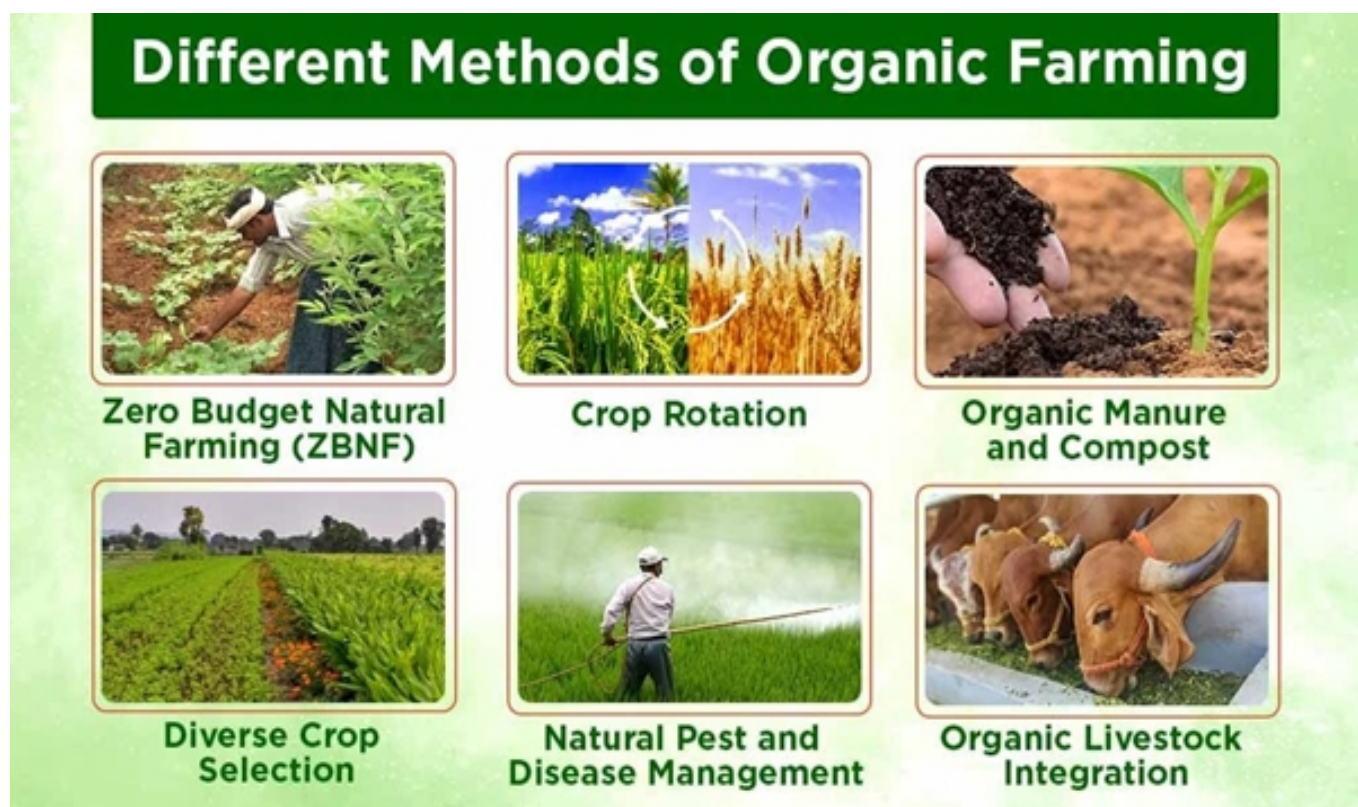


**Figure 1. Organic farming Package of Practices (ICAR-FAO Guidelines, 2016)**

maintain indigenous traditional knowledge for agricultural sustainability. This short review summarizes the benefits and limitations of organic farming in relation to sustainable agricul-

tural practices. We can infer that initially organic farming may appear as a loss because of less output and commercial returns. But after prolonged and continuous efforts it gives approximately

the same output along with one extra core benefit which is, its sustainability towards climate and ecology.



**Figure 2. Organic farming practices**

Source: <https://tractorkarvan.com/blog/what-is-organic-farming>

## References

- Azarbad, H. (2022). Conventional vs. organic agriculture: Which one promotes better yields and microbial resilience in rapidly changing climates? *Frontiers in Microbiology*, 13, Article 903500. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.903500>
- Bainard, L. D., Klironomos, J. N., & Hamel, C. (2017). Increasing the frequency of pulses in crop rotations reduces soil fungal diversity and increases the proportion of fungal pathotrophs in a semiarid agroecosystem. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 247, 156-164.
- Barbieri, P., Mancinelli, R., & Pellerin, S. (2017). Comparing crop rotations between organic and conventional farming. *Scientific Reports*, 7, Article 11015.
- Barbieri, P., Verzeaux, J., & Daryanto, S. (2023). Biological nitrogen fixation of legume crops under organic farming as driven by cropping management: A review. *Agricultural Systems*, 206, Article 103694.
- Bengtsson, J., Ahnström, J., & Weibull, A.-C. (2005). The effects of organic agriculture on biodiversity and abundance: A meta-analysis. *Journal of Applied Ecology*, 42, 261-269. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2005.01005.x>
- Borghino, N., Wissinger, L., Erb, K.-H., Mouël, C., & Nesme, T. (2024). Organic farming expansion and food security: A review of foresight modeling studies. *Global Food Security*, 41, Article 100765. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2024.100765>
- De Ponti, T., Rijk, B., & van Ittersum, M. K. (2012). The crop yield gap between organic and conventional agriculture. *Agricultural Systems*, 108, 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2011.12.004>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). *Organic agriculture: What is organic agriculture?* FAO.
- Francis, C. (1990). Sustainable agriculture: Myths and realities. *Journal of Sustainable Agriculture*, 1(1), 97-99.
- Gamage, A., Gangahagedara, R., Gamage, J., Jayasinghe, N., Kodikara, N., Suraweera, P., & Merah, O. (2023). Role of organic farming for achieving sustainability in agriculture. *Farming Systems*, 1, Article 100005. <https://doi.org/10.1016/j.farsys.2023.100005>
- Gattinger, A., Müller, A., Häni, M., Skinner, C., Fließbach, A., Buchmann, N., Mäder, P., Stolze, M., Smith, P., Scialabba, N. E.-H., & Niggli, U. (2012). Enhanced top soil carbon stocks under organic farming. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109, 18226-18231. <https://doi.org/10.1073/pnas.1209429109>
- Hole, D. G., Perkins, A. J., Wilson, J. D., Alexander, I. H., Grice, P. V., & Evans, A. D. (2005). Does organic farming benefit biodiversity? *Biological Conservation*, 122(1), 113-130.
- Ikerd, J. (1993). Two related but distinctly different concepts: Organic farming and sustainable agriculture. *Small Farm Today*, 10(1), 30-31.
- Indian Council of Agricultural Research. (2016). *Package of practices for organic farming*. ICAR.
- Ponisio, L. C., M'Gonigle, L. K., Mace, K. C., Palomino, J., de Valpine, P., & Kremen, C. (2015). Diversification practices reduce the organic to conventional yield gap. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 282, Article 20141396. <https://doi.org/10.1098/rspb.2014.1396>
- Pretty, J., Benton, T. G., Bharucha, Z. P., Dicks, L. V., Flora, C. B., Godfray, H. C. J., Goulson, D., Hartley, S., Lampkin, N., Morris, C., Pierzynski, G., Prasad, P. V. V., Reganold, J., Rockström, J., Smith, P., Thorne, P., & Wratten, S. (2018). Global assessment of agricultural system redesign for sustainable intensification. *Nature Sustainability*, 1, 441-446.
- Reganold, J. P., & Wachter, J. M. (2016). Organic agriculture in the twenty-first century. *Nature Plants*, 2, Article 15221. <https://doi.org/10.1038/nplants.2015.221>
- Seufert, V., Ramankutty, N., & Foley, J. A. (2012). Comparing the yields of organic and conventional agriculture. *Nature*, 485, 229-232. <https://doi.org/10.1038/nature11069>
- Sidemo-Holm, W., Brady, M. V., Carrié, R., Ekroos, J., & Smith, H. G. (2024). Cost-effective biodiversity conservation with organic farming: Spatial allocation is key. *Biological Conservation*, 294, Article 111062. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2024.110624>
- Srinivasan, R., & Aithal, P. S. (2025). Organic alchemy: Panchagavya's role in green agriculture transformation. *Poornaprajna International Journal of Basic & Applied Sciences*.
- Tuck, S. L., Winqvist, C., Mota, F., Ahnström, J., Turnbull, L. A., & Bengtsson, J. (2014). Land-use intensity and the effects of organic farming on biodiversity: A hierarchical meta-analysis. *Journal of Applied Ecology*, 51, 746-755. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.12219>
- Tamil Nadu Agricultural University. (n.d.). *Panchagavya: Beneficial effects on commercial crops*. TNAU AgriTech Portal. Retrieved January 24, 2026, from [https://agritech.tnau.ac.in/org\\_farm/orgfarm\\_panchakavya.html#BeneficialEffects](https://agritech.tnau.ac.in/org_farm/orgfarm_panchakavya.html#BeneficialEffects)

# Regulation and Censorship of OTT Platforms: Examining the Regulatory Landscape and Content Censorship Challenges Globally

Abhishek Kumar and Kaushal Tripathi

## Abstract

*The rapid expansion of Over-The-Top (OTT) platforms has revolutionized global content consumption, providing unprecedented access to diverse media. This growth, however, has introduced significant regulatory and censorship challenges. This study examines the regulatory landscape governing OTT platforms across different regions, identifying key regulatory bodies, specific regulations, and regional legal contexts in the United States, European Union, India, China, and Brazil. Additionally, it explores content censorship issues through case studies, highlighting common challenges and region-specific concerns. The study also conducts a thorough literature review to identify research gaps and emerging trends in OTT regulation and censorship. By integrating these methodologies, the study provides a comprehensive overview of the global regulatory environment, detailed insights into censorship challenges, and contributes to ongoing academic and industry discussions. The findings aim to inform policymakers, guide content creators and platform providers, and enhance consumer awareness, ultimately promoting a balanced and effective regulatory framework for OTT platforms.*

**Keywords:** OTT platforms, content censorship, regulatory landscape, comparative analysis, case study, United States, European Union, India, China, Brazil, digital media regulation, literature review, policy development.

## 1. Introduction

The rise of Over-The-Top (OTT) platforms, such as Netflix, Amazon Prime Video, and Disney+, has dramatically altered the media landscape by providing users with immediate access to a wide variety of content beyond traditional broadcast channels. This surge in popularity and accessibility has led to significant regulatory and censorship challenges globally. Regulatory bodies are now tasked with creating frameworks that balance the benefits of these innovations with cultural sensitivities and content standards.

Different regions have approached the regulation of OTT platforms in varied ways, reflecting their unique legal, cultural, and economic contexts. In the United States, the Federal Communications Commission (FCC) adopts a relatively hands-off approach, emphasizing competition and consumer protection while grappling with issues like net neutrality and data privacy. In contrast, the European Union's Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) requires content quotas for European works and safeguards for minors, highlighting the difficulty of harmonizing regulations across diverse member states.

India's regulatory landscape is shaped by the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021, which enforce content regulation and self-classification to balance censorship and creative freedom. China's stringent content censorship laws, overseen by the National Radio and Television Administration (NRTA), impose significant compliance burdens on OTT platforms, limiting the diversity of available content. Meanwhile, Brazil's Agência Nacional do Cinema (ANCINE) enforces national content quotas and advertising regulations, promoting local culture while presenting challenges for global providers.

Content censorship presents a host of challenges, with regions like the U.S. facing potential inequalities in content accessibility due to net neutrality issues, and the European Union balancing cultural diversity with content variety. India's self-classification rules strive to balance censorship and freedom of expression, though they risk overreach. China's ideological constraints on content restrict diversity, and Brazil's enforcement of national quotas, while encouraging local production, poses hurdles for global OTT platforms.

## Historical Perspective of OTT Platforms

The history of Over-The-Top (OTT) platforms began in the 1990s with RealNetworks' RealPlayer, which enabled online video streaming. The mid-2000s marked a significant shift with the launch of Netflix's streaming service in 2007, initially available to DVD rental subscribers and later as a standalone service. This success led to the rise of other OTT platforms like Hulu in 2008 and Amazon Prime Video in 2011.

The early 2010s saw a surge in OTT platforms, including Disney's Disney Movies Anywhere in 2013 (which evolved into Disney+), HBO Now in 2015, YouTube TV in 2016, and Facebook Watch in 2017. The growing popularity of these services prompted traditional TV networks and cable providers to launch their own streaming platforms, such as CBS All Access, NBC's Peacock, and Warner Media's HBO Max.

Technological advancements and changes in consumer behavior, including the demand for on-demand content and high-speed internet access, have driven the popularity of OTT services. In India, the COVID-19 pandemic accelerated the adoption of OTT platforms, with major players like Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar, and regional services like Zee5 and Voot seeing significant growth. These platforms offer viewers flexibility and a wide range of content, transforming the entertainment landscape.

## Need for Censorship

Censorship of Over-The-Top (OTT) platforms is essential to

address several critical concerns as these platforms expand globally. Protecting vulnerable audiences, particularly children and adolescents, is a primary reason for censorship, ensuring that harmful or inappropriate content is not easily accessible. This allows parents to make informed decisions about their children's viewing habits. Additionally, censorship helps uphold cultural sensitivities by respecting the unique cultural, moral, and social values of different regions, preventing the spread of content that could be offensive or harmful to societal norms.

The rapid spread of misinformation in the digital age is another significant concern. OTT platforms, with their vast reach, can inadvertently become conduits for false or misleading information. Censorship ensures that content is vetted for accuracy, maintaining public trust and providing viewers with credible information. Moreover, censorship is crucial for protecting national security by preventing the dissemination of content that promotes terrorism, incites violence, or spreads harmful propaganda, particularly in politically unstable regions.

While creative freedom is vital, it must be balanced with the responsibility to avoid causing harm or offense. Censorship helps strike this balance, fostering a healthy media environment where creativity can thrive without compromising ethical standards. In summary, censorship on OTT platforms is crucial for protecting audiences, respecting cultural values, ensuring accurate information, safeguarding national security, and balancing creative freedom with

responsibility.

## Review of Literature

The growth and regulation of Over-The-Top (OTT) platforms have been extensively studied, revealing diverse perspectives on regulatory frameworks, content censorship, and the sociocultural impacts of OTT platforms. This section presents ten significant reviews of literature that provide insights into these areas.

1. **Baldwin, T. F., McVoy, D. S., & Steinfield, C. W. (1996).** This foundational study explores the convergence of media, information, and communication technologies, emphasizing the need for regulatory frameworks to evolve in response to these changes. The authors argue that traditional regulatory approaches must adapt to address the unique challenges posed by digital media, including OTT platforms.
2. **Alexander, A., Owers, J. E., Carveth, R., Hollifield, C. A., & Greco, A. N. (Eds.). (2003).** This comprehensive work on media economics provides a theoretical and practical framework for understanding the economic implications of media industries, including OTT platforms. The authors discuss regulatory challenges and the balance between promoting competition and protecting consumer interests.
3. **Alleman, J., Fontaine, G., Katz, R., & Le Champion, R. (2013).** This study examines the phenomenon of video cord-cutting and its impact on traditional cable TV markets. The authors

highlight the regulatory challenges that arise from the shift to OTT platforms and the need for policies that address issues of accessibility, net neutrality, and consumer protection.

4. **Dhiman, D. (2021).** This study examines the psychosocial impact of streaming content on Indian youth, highlighting the role of regulatory frameworks in addressing harmful content. It emphasizes the need for responsible content distribution while balancing creative freedom and consumer protection.
5. **Baccarne, B., Evens, T., & Schuurman, D. (2013).** This assessment focuses on the challenges OTT platforms face in cable-dominant markets, discussing regulatory and market dynamics. The authors argue for a balanced approach that fosters innovation while ensuring fair competition and consumer protection.
6. **Dhiman, B. (2022).** This critical analysis explores the effects of online news applications on media consumption patterns, drawing parallels to OTT platforms. The study highlights the regulatory challenges and the need for frameworks that address content accuracy, consumer protection, and the balance between innovation and regulation.

## SIGNIFICANCE OF STUDY

This study examines the regulation and censorship of OTT platforms, highlighting the

complexities of diverse regulatory frameworks across different regions. It provides valuable insights for policymakers, helping them develop balanced regulations that protect consumers while fostering innovation. The study also explores content censorship challenges, offering case studies that illustrate the need to protect audiences without stifling creative freedom.

For content creators and platform providers, it offers guidance on navigating regulatory environments and making strategic decisions. By raising consumer awareness, it empowers them to make informed choices and advocate for their rights. The study contributes to academic and industry discourse and emphasizes the importance of global collaboration to harmonize regulations and promote best practices, aiming for a cohesive and effective regulatory framework worldwide.

## OBJECTIVES OF THE STUDY

1. To analyze regulatory frameworks governing OTT platforms globally.
2. To identify specific content censorship challenges faced by OTT platforms.

## RESEARCH METHODOLOGY

The research methodology combines comparative analysis, case study method, and literature review to achieve the study's objectives. Data has been collected from government publications, regulatory reports, legal documents, news articles, and academic literature. Comparative analysis has been done to identify differences and similarities in OTT regulations across regions

like the United States, European Union, India, China, and Brazil. Case studies has been done to explore specific content censorship challenges. The outcomes include a comprehensive overview of the global regulatory landscape, detailed insights into censorship challenges, and contributions to academic and industry discussions through publications and conference presentations.

## DATA ANALYSIS

### Current Global Overview of Regulatory Landscape Governing OTT Platforms

The regulatory environment for OTT platforms varies significantly across different regions, reflecting diverse legal, cultural, and economic contexts.

#### 1. United States

- **Regulating Body:** Federal Communications Commission (FCC)
- **Key Regulations:** The U.S. maintains a relatively laissez-faire approach, focusing on competition and consumer protection rather than content regulation.
- **Challenges:** Issues around net neutrality and data privacy are prominent.

#### 2. European Union

- **Regulating Body:** European Commission
- **Key Regulations:** The Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) governs OTT services, mandating content quotas for European works and protecting minors.
- **Challenges:** Harmonizing regulations across member states with different cultural sensitivities.

### 3. India

- **Regulating Body:** Ministry of Information and Broadcasting (MIB)
- **Key Regulations:** The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, which impose content regulation and self-classification.
- **Challenges:** Balancing censorship with freedom of expression in a diverse cultural context.

### 4. China

- **Regulating Body:** National Radio and Television Administration (NRTA)
- **Key Regulations:** Strict content censorship laws, with state control over media and tight regulations on foreign content.
- **Challenges:** Maintaining stringent control while adapting to digital media trends.

### 5. Brazil

- **Regulating Body:** Agência Nacional do Cinema (ANCINE)
- **Key Regulations:** Quotas for national content and regulations on advertising.
- **Challenges:** Enforcing content quotas and addressing piracy.

## Content Censorship Challenges

### Case Studies

#### 1. The U.S. and Net Neutrality

- **Issue:** The rollback of net neutrality regulations has raised concerns about the potential for ISPs to prioritize certain content, affecting OTT platform accessibility.
- **Impact:** Potential unequal access to content, impacting

consumer choice and competition.

#### 2. Europe's AVMSD Implementation

- **Issue:** The directive mandates that at least 30% of content on OTT platforms must be European, which can be challenging for platforms.
- **Impact:** Ensures cultural diversity but may limit content variety and increase costs for OTT providers.

#### 3. India's IT Rules 2021

- **Issue:** The rules require OTT platforms to self-classify content and adhere to a code of ethics, with provisions for content takedown.
- **Impact:** Strikes a balance between censorship and creative freedom but faces criticism for potential overreach.

#### 4. China's Content Restrictions

- **Issue:** Strict censorship laws limit foreign content and impose ideological constraints on domestic productions.
- **Impact:** Limits diversity of content and imposes significant compliance burdens on OTT platforms.

#### 5. Brazil's Content Quotas

- **Issue:** Enforcement of national content quotas on OTT platforms to promote local culture.
- **Impact:** Encourages local production but can be challenging for global OTT providers to meet quota requirements.

## Discussion

1. The regulatory landscape for OTT platforms varies widely across regions due to differing legal, cultural, and

economic contexts.

In the United States, the FCC adopts a hands-off approach, focusing on competition and consumer protection rather than strict content regulation, which fosters innovation but raises net neutrality and data privacy concerns.

The European Union's Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) mandates content quotas for European works and the protection of minors, challenging the European Commission to harmonize regulations across culturally diverse member states.

India's Ministry of Information and Broadcasting (MIB) regulates OTT platforms under the Information Technology Rules, 2021, balancing censorship with freedom of expression. The challenge lies in maintaining this balance without stifling creativity.

China's National Radio and Television Administration (NRTA) enforces strict content censorship and state control over media, preserving ideological control but limiting content diversity and imposing heavy compliance burdens on providers.

Brazil's Agência Nacional do Cinema (ANCINE) mandates national content quotas and regulates advertising, promoting local culture but challenging global OTT providers to meet these requirements while addressing piracy issues.

2. OTT platforms face various content censorship challenges globally. In the United States, the rollback of net neutrality raises concerns about unequal access to content, impacting consumer choice and competition.

The European Union's AVMSD directive requires 30% European content on OTT platforms, promoting cultural diversity but potentially limiting content variety and increasing costs.

India's IT Rules 2021 mandate self-classification and ethical guidelines, aiming to balance censorship with creative freedom but risking overreach and stifling innovation.

China's strict censorship laws limit foreign content and impose ideological constraints, reducing diversity and imposing heavy compliance burdens on OTT providers.

Brazil's content quotas promote local culture but challenge global OTT providers to comply with regulations and address piracy, potentially limiting international content variety.

In summary, OTT platforms must navigate a complex regulatory landscape, balancing the need for regulation with preserving creative freedom and content diversity.

## Conclusion

The regulatory landscape for OTT platforms is highly diverse and region-specific, shaped by varying legal, cultural, and economic contexts. In the United States, a hands-off approach by the FCC fosters innovation but brings challenges related to net neutrality and data privacy. The European Union's AVMSD aims to protect minors and ensure cultural diversity through content quotas, yet harmonizing these regulations across diverse member states remains a challenge.

India's regulatory framework seeks to balance censorship

with freedom of expression under the IT Rules 2021, striving to maintain this equilibrium without stifling creativity. China's strict censorship laws and state control preserve ideological control but limit content diversity and impose significant compliance burdens. Brazil's content quotas promote local culture but present challenges for global OTT providers in meeting these requirements while addressing piracy.

Globally, OTT platforms face various censorship challenges. The rollback of net neutrality in the U.S. raises concerns about unequal content access, while the EU's content quotas potentially limit variety and increase costs. India's self-classification and ethical guidelines aim to balance censorship and creative freedom, risking overreach. China's ideological constraints limit diversity, and Brazil's content quotas challenge global compliance and limit international content.

Overall, navigating the complex regulatory landscape while balancing the need for regulation, creative freedom, and content diversity remains a significant and ongoing challenge for OTT providers and regulators worldwide.

## References

- Baldwin, T. F., McVoy, D. S., & Steinfield, C. W. (1996). *Convergence: Integrating media, information & communication*. SAGE Publications.
- Alexander, A., Owers, J. E., Carveth, R., Hollifield, C. A., & Greco, A. N. (Eds.). (2003). *Media economics: Theory and practice*. Routledge.
- Alleman, J., Fontaine, G., Katz, R., & Le Champion, R.

(2013). Video cord-cutting and the regulatory challenges. *Journal of Media Economics*, 26(3), 127-145.

- Baccarne, B., Evens, T., & Schuurman, D. (2013). *Challenges for OTT platforms in cable-dominant markets*. *Telecommunications Policy*, 37(10), 972-981.
- Dhiman, D. (2021). *The psychosocial impact of streaming content on Indian youth: The role of regulatory frameworks*. *Media Psychology*, 24(2), 253-273.
- Dhiman, B. (2022). *Online news applications and media consumption patterns: Regulatory challenges and implications*. *Journal of Digital Media*, 12(1), 45-67.
- European Commission. (2018). *Audiovisual Media Services Directive*. Retrieved from <https://ec.europa.eu/digital-strategy/our-policies/audiovisual-media-services-directive-avmsd>
- Federal Communications Commission (FCC). (2020). *Net Neutrality*. Retrieved from <https://www.fcc.gov/net-neutrality>
- Ministry of Information and Broadcasting (MIB), India. (2021). *Information Technology Rules 2021*. Retrieved from <https://mib.gov.in/>
- National Radio and Television Administration (NRTA), China. (2020). *Content Censorship Laws*. Retrieved from <http://www.nrta.gov.cn/>
- Agência Nacional do Cinema (ANCINE), Brazil. (2020). *National Content Quotas*. Retrieved from <https://www.ancine.gov.br/>

## Religious Portrayals in Salim-Javed's Screenplay Writing: An Examination of Implicit and Explicit Narratives

Abhishek Rajput

### 1. Introduction

Salim-Javed, the acclaimed screenwriting duo comprising Salim Khan and Javed Akhtar, are widely recognized for their profound impact on Hindi cinema during the 1970s. Their prolific partnership, active from 1971 to 1982, was exceptionally successful, yielding 24 films, with a remarkable 22 achieving blockbuster status, which fundamentally reshaped Bollywood's narrative landscape.[3, 5] A cornerstone of their contribution was the popularization of the "Angry Young Man" archetype, most famously embodied by Amitabh Bachchan in iconic films such as *Zanjeer*, *Deewaar*, and *Kaala Patthar*. [2, 5, 6, 7] This character resonated deeply with the audience, serving as a powerful reflection of the widespread disillusionment and anger stemming from socio-economic and political challenges in 1970s India, including economic crises, political unrest, and the Emergency period.[4, 7, 8, 9] Their scripts were celebrated for their robust narratives, impactful dialogues, and the creation of multi-dimensional characters that often explored morally ambiguous territories, marking a significant departure from the more conventional and "cocooned gentility" of earlier cinematic narratives.[3, 4, 10]

This research paper aims to

critically examine the portrayal of Muslim religious identity and characters within the filmography of Salim-Javed. It specifically addresses the proposition that these narratives implicitly or explicitly promoted Muslim religion. Furthermore, it will conduct a comparative analysis of these portrayals alongside those of Hindu religious figures and themes present in their films.

The 1970s in India were a period of considerable socio-political turbulence, marked by events such as the 1971 war, the declaration of the Emergency (1975-77), rampant inflation, and widespread student protests.[7] Hindi cinema of this era frequently mirrored this societal disenchantment, with protagonists often challenging state authority and blurring traditional moral boundaries between good and evil.[8] Despite these internal pressures, mainstream Bollywood in the 1970s largely upheld a secular, democratic, and pluralistic ethos. Films from this period, such as *Amar Akbar Anthony* (though not a Salim-Javed script), explicitly celebrated pluralism by depicting characters from different religious backgrounds uniting. [11] While Salim-Javed's films generally aligned with this secular narrative, some contemporary analyses suggest a subtler, even "insidious," promotion of

Islamism disguised as secularism, particularly highlighted in the context of *Deewaar*. [12] This report will meticulously scrutinize these claims. The representation of religious minorities, especially Muslims, in Bollywood has been an extensive academic inquiry, demonstrating an evolution from exotic or benign depictions in earlier decades to more complex, and at times, negative portrayals in later periods. Salim-Javed's work falls squarely within the "benign depictions" era, where Muslim characters frequently served as trusted friends and confidants to the Hindu protagonists, [11, 13, 14]

The "Angry Young Man" (AYM) archetype, a hallmark of Salim-Javed's cinema, is consistently linked to the socio-political climate of the 1970s. [7, 8, 9] This character, often from marginalized backgrounds or facing systemic injustice, operates outside the law to seek justice. Salim Khan, being Muslim, and Javed Akhtar, the son of a Communist poet, were themselves part of a minority within a Hindu-dominated industry, where Muslim elements played a significant role, [4, 6] This suggests that the AYM, while seemingly universal in his anger, could also serve as a subtle vehicle for expressing the concerns and experiences of

marginalized groups, including religious minorities. The inquiry into the promotion of Muslim identity fits into this broader understanding of the AYM's role as a representative of the "diverse minorities and marginalized groups in Indian society"[6] The immense popularity of Salim-Javed's films and the profound resonance of the AYM character provided a powerful platform for narratives that might have otherwise faced resistance. This allowed for the integration of specific religious or cultural elements, such as the '786' symbolism or positive Muslim characters, under the guise of broader social commentary or anti-establishment themes. Consequently, any potential emphasis on Muslim identity was less overt and more deeply embedded within the protagonist's struggle against a "rigged system" [4], making it a nuanced and complex form of cinematic representation.

## 2. Literature Review

The portrayal of religion in Indian cinema has been a subject of scholarly inquiry across various disciplines, including film studies, cultural studies, and religious studies. The following review outlines the key academic contributions relevant to religious representation in Hindi cinema and how these perspectives relate to the screenwriting work of Salim-Javed.

### 2.1 Religion in Indian Cinema: A Historical and Thematic Overview

**Rachel Dwyer (2006)**, in her seminal work *Filming the Gods: Religion and Indian Cinema*, explores how religion has shaped the narrative and visual grammar of Indian films. She argues that

Indian cinema does not simply represent religion as a subject but often performs it through melodrama, spectacle, and music. Dwyer notes that filmmakers often reinforce religious iconography in secular contexts – a concept visible in Salim-Javed's works, especially *Amar Akbar Anthony*.

**Tejaswini Ganti (2012)** provides a broader sociological framework in *Producing Bollywood*, where she contextualizes religion in cinema as a reflection of middle-class sensibilities and the Indian state's secular ideals. Ganti's exploration of censorship, production decisions, and narrative conventions helps us understand how Salim-Javed navigated political sensitivities around religious identity during the Emergency era.

### 2.2 Secularism and Pluralism in Hindi Cinema

**Ashis Nandy (1998)**, in *The Secret Politics of Our Desires*, presents a psychoanalytic and political reading of Indian cinema, suggesting that popular films serve as unconscious expressions of social tensions, including those related to religion. Salim-Javed's characters, such as the morally ambiguous Vijay (*Deewaar*), reflect internal dilemmas shaped by the erosion of traditional religious authority.

**Rajadhyaksha and Willemen (1999)** argue in *Encyclopaedia of Indian Cinema* that the Bollywood formula often incorporates a secular-nationalist ethos. The "secular family" trope – most explicitly portrayed in *Amar Akbar Anthony* – is emblematic of the industry's efforts to imagine a harmonious, multi-faith India.

### 2.3 The Use of Religious

Symbolism and Character Typology

**Sumita S. Chakravarty (1993)**, in *National Identity in Indian Popular Cinema*, asserts that Hindi films encode religious identity into character archetypes. She categorizes the Muslim character as typically noble or villainous, depending on political context. In Salim-Javed's films, characters like Sher Khan (in *Zanjeer*) subvert these binaries by being heroic, secular, and deeply moral.

### 2.4 Religious Pluralism and Nation-Building in Cinema

**Ravi Vasudevan (2011)**, in *The Melodramatic Public*, discusses how melodrama in Indian cinema becomes a vehicle for moral and political discourse. He emphasizes that films use religious rituals and symbols to express universal justice – a technique employed in *Deewaar's* temple scene and *Sholay's* sacrificial overtones.

**Priya Joshi (2001)** in *In Another Country: Colonialism, Culture, and the English Novel in India*, examines the appeal of cinema in post-colonial societies, including its role in crafting a shared moral-religious vocabulary. Salim-Javed's writing, she argues, reflects this sensibility by creating emotionally resonant moral universes through religion-inflected melodrama.

### 2.5 Studies on Salim-Javed and the Masala Genre

**Yasser Usman (2018)** in *The Legend of Salim-Javed: The Mavericks of Hindi Cinema* provides a biographical and analytical overview of the duo's influence on Indian screenwriting. While not academically rigorous, the book offers insights into how they consciously employed religious

themes to evoke a secular but culturally rooted Indian identity.

**Anustup Basu (2011)**, in *Bollywood in the Age of New Media*, observes that Salim-Javed's films marked the transition from a romantic-nationalist mode to an urban-industrial critique, where religion became a site of moral reckoning rather than divine submission. This is evident in *Deewaar* and *Zanjeer*, where temples, mothers, and fate intertwine.

### 2.6 Representation of Islam and Christianity in Hindi Films

**Shahnaz Khan (2002)**, writing on Muslim representation, observes that while Bollywood generally marginalizes Muslim characters, some narratives humanize them through complex backstories and moral integrity. Salim-Javed's characters – Akbar and Sher Khan – challenge stereotypes by being protectors and reformers.

**Christophe Jaffrelot (2007)** notes that Christians in Bollywood are often caricatured, but *Amar Akbar Anthony* presents Anthony Gonsalves as flamboyant yet heroic, thus expanding the scope of Christian identity in popular narratives.

### Contributions of Salim-Javed

**Usman (2018)** offers a popular account of Salim-Javed's rise, discussing their intentional use of religion as a means of reaching diverse audiences without alienating any. While the work lacks academic rigor, it contains valuable interviews and context that highlight the duo's conscious secular ethos.

**Basu (2011)** notes that their films mark a shift toward urban realism, where religion is both a source of identity and conflict. He underscores how Salim-Javed

blend religious motifs with modern anxieties, especially around justice, family, and fate.

### 3. Research Gap

While scholars have explored religion in Hindi cinema broadly, focused academic inquiry into Salim-Javed's religious portrayals – distinguishing between implicit and explicit – remains limited. This study fills that gap by providing a comparative analysis of religious narrative functions in their key films, within the framework of post-independence secularism and popular cultural politics.

### 4. Research Questions

1. How are Muslim identities explicitly and implicitly portrayed in Salim-Javed films?
2. How do Hindu religious elements interact with other portrayals in their cinema?
3. Do Salim-Javed's narratives subtly promote specific religious values (Muslim) as secular?
4. How do inter-religious interactions challenge or uphold secularism in their films?
5. What are the socio-political implications of religious portrayals in Salim-Javed's cinema?

### 5. Research Objectives

1. To analyze the explicit and implicit portrayals of Muslim religious identity and their narrative functions in selected Salim-Javed films.
2. To compare the representation of Muslim religious figures and themes with those of Hindu religious elements in Salim-Javed's

cinema.

3. To critically assess claims of subtle religious (specifically Muslim) promotion within the narratives of Salim-Javed's films, particularly via the "Angry Young Man."
4. To examine how inter-religious character interactions in their films contribute to or challenge the secular-pluralistic ethos of the era.
5. To explore the socio-political implications of Salim-Javed's religious portrayals in the context of 1970s popular Hindi cinema.

### 6. Methodology

This research paper employs a qualitative content analysis approach to examine the religious portrayals in selected films written by Salim-Javed. The methodology is structured as follows:

#### 6.1. Film Selection

A purposive sampling method will be used to select key films from Salim-Javed's filmography that are widely recognized for their influential narratives and prominent character portrayals. These include, but are not limited to:

- *Deewaar* (1975)
- *Zanjeer* (1973)
- *Sholay* (1975)
- *Haath Ki Safai* (1974)
- *Andaaz* (1971)

These films are chosen for their iconic status, critical acclaim, commercial success, and their well-documented impact on Hindi cinema, ensuring a representative sample of Salim-Javed's thematic approaches.

#### 6.2. Data Collection

The primary data for this study

will be collected through:

- **Detailed Film Viewing:** Multiple viewings of the selected films will be conducted to meticulously observe character interactions, dialogues, visual cues, and narrative developments related to religious themes and characters.
- **Script Analysis (where available):** Analysis of film scripts will be undertaken to understand the original intent and textual representation of religious elements.
- **Secondary Source Review:** Extensive review of academic articles, books, and reliable critical analyses focusing on Salim-Javed's work, Bollywood's history, socio-political contexts of the 1970s, and the portrayal of religious minorities in Indian cinema.

### 6.3. Data Analysis

The collected data will be analysed using a multi-faceted approach:

- **Thematic Analysis:** Identification and categorization of recurring themes, motifs, and narrative patterns related to religious portrayals. This involves: Identification of Muslim Characters and Symbols: Cataloguing all significant Muslim characters and explicit religious symbols (e.g., '786' badge, specific attire, customs) present in the films.
- **Character Trait Analysis:** Examining the personality traits, moral compass, and narrative functions of these characters (e.g., integrity of

Sher Khan, piety of Rahim Chacha/Imam, altruism of Usman bhai).

- **Dialogue Analysis:** Scrutinizing dialogues that convey religious sentiments, inter-faith interactions, or discussions about faith.
- **Symbolic Interpretation:** Analysing the deeper meanings and implications of religious symbols within the narrative context.
- **Comparative Analysis:** A direct comparison between the portrayal of Muslim religious figures and themes versus Hindu religious figures and themes. This includes: Examining the roles, moral standing, and narrative arcs of characters associated with both religions. Assessing any perceived biases or differential treatment in their depiction (e.g., the user's perception of negative Hindu priest portrayals versus positive Muslim religious figures).
- **Contextualization:** Placing the film narratives within the broader socio-political and cultural landscape of 1970s India. This involves: Analysing how prevailing secular ideals, political dynamics (e.g., the Emergency), and communal harmony initiatives of the time might have influenced the screenwriters' choices. Considering how the "Angry Young Man" archetype might have served as a vehicle for integrating diverse religious identities into mainstream narratives.

This comprehensive methodology ensures a robust investigation into the nuanced and often

debated aspects of religious portrayals in Salim-Javed's cinematic legacy.

## 7. Analysis and Discussion

This section reviews existing literature and analyses thematic portrayals of religious elements in Salim-Javed's filmography, considering their socio-political context and the academic discourse surrounding their work.

### 7.1. Thematic Analysis of Muslim Character Portrayals

#### 7.1.1. The Symbolic Power of '786' in *Deewaar*

In *Deewaar* (1975), Amitabh Bachchan's character, Vijay Verma, an atheist dockworker who rises to become an underworld figure, prominently carries a badge with the number '786'. [12, 15, 16] This number holds profound reverence in Islamic culture, signifying "Bismillah al-Rahman al-Rahim" (In the name of Allah, the compassionate, the merciful), and is considered highly auspicious. [12, 17] The film explicitly establishes '786' as a symbol of divine protection for Vijay. Throughout the narrative, the badge repeatedly saves him from perilous situations, imbuing him with an aura of invincibility as long as he possesses it. [12, 16] Crucially, the loss of this badge directly precedes his fatal shooting, symbolizing the cessation of Allah's protection and marking a turning point in his destiny. [12, 16] The profound significance of '786' is elucidated to Vijay by Rahim Chacha, a character depicted as a benevolent, aged, poor, hard-working, and pious Muslim. [12] Rahim Chacha explicitly draws a parallel between '786' and 'Om' for Hindus, framing it as a

universally auspicious and protective symbol, thereby attempting to bridge religious understanding.[12]

Vijay's character is initially portrayed as an atheist, particularly expressing anger towards Hindu deities (specifically Shiva) due to the profound injustices suffered by his mother. [12, 16] He actively avoids visiting temples, and a temple priest even remarks that he will only enter when he develops 'Shraddha' (faith). [12] However, a significant narrative contrast is established as Vijay instantly develops faith in the power of '786' after Rahim Chacha's explanation. This highlights a distinct divergence: his rejection of traditional Hindu worship stands in stark opposition to his reliance on a Muslim-associated sacred symbol for protection and fortune. [12] Paradoxically, Vijay's life culminates in his death within the very Shiva temple he once scorned, collapsing in his mother's arms. This final scene can be interpreted as a symbolic return to innocence or a reluctant, perhaps fated, embrace of a more traditional spiritual path, creating a complex interplay of religious symbolism. [12, 16]

The narrative strategy in *Deewaar* regarding '786' can be understood as a form of strategic secularism.



**Image 1: Deewaar. Directed by Yash Chopra, Trimurti Films Pvt, 1975.**

The film explicitly states that its secularism "lies in subtly promoting Islam as a peaceful, benevolent and protective religion, Muslims as poor, hardworking, honest, devout and Allah-fearing people, and monkey-balancing it with enough positive stuff about Hinduism".[12] The comparison of '786' to 'Om' is a crucial element of this strategy, as it attempts to universalize a Muslim religious symbol, making it palatable and acceptable across religious lines, thereby subtly integrating it into the mainstream narrative without overt religious proselytization. This approach effectively allows for the normalization and positive association of Muslim religious symbols within a predominantly Hindu cultural landscape. It frames Muslim identity not as 'other' but as a source of universal protection and benevolence, aligning with the broader secular ethos of the 1970s. The protagonist's death in the Hindu temple, after losing the Muslim symbol, could be seen as a final narrative balancing act to reinforce broader secularism or a return to the "national" fold [2], but the journey is undeniably marked by the Muslim symbol's power.

Furthermore, the '786' symbolism creates a thematic link with the "Angry Young Man's" moral ambiguity. Vijay is the quintessential "angry young man" operating outside the law, a criminal figure, [8,16] Yet, he is consistently protected by a divine, auspicious number. [12, 16] This creates a fascinating moral paradox within the narrative. The "God in the Details" chapter discusses how Salim-Javed's scripts often explored complex themes of "morality and

justice," including the idea that "even thieves have principles" and the concept of "proportional justice"[2] Vijay's reliance on '786' suggests that even a morally ambiguous character, driven by anger and revenge against a corrupt system, can be touched by divine grace. It implies that his journey, though criminal, is somehow sanctioned or protected by a higher power, at least until he loses that sacred symbol. This adds a layer of fatalism ("It is all written!") [2] to his character arc. The '786' symbolism elevates Vijay's struggle beyond mere criminality, imbuing it with a quasi-spiritual dimension. It suggests that his fight against injustice, even though illicit means, might be divinely guided or at least divinely tolerated, making his character more complex and sympathetic to a wider audience. This aligns with the idea of the "angry young man" as a "site of reform" who can be "recuperated" [8], suggesting a deeper moral framework at play.

### 7.1.2. The 'Honest' Muslim Criminal Archetype: Sher Khan (*Zanjeer*) and Usman bhai (*Haath Ki Safai*)

In *Zanjeer* (1973), Sher Khan is initially introduced as an illegal car dealer and a local goon who challenges Inspector Vijay.[18, 19] Following a physical confrontation, Sher Khan develops a profound respect for Vijay's unwavering honesty and determination.[18, 19] This newfound respect triggers a significant transformation in his character: he voluntarily closes his gambling dens, reforms his illicit ways, and becomes a loyal, lifelong friend and indispensable accomplice to Vijay, even demonstrating a willingness to risk his own life for their friendship.[14,

**Table 1: Instances of '786' Symbolism and its Impact in *Deewaar***

Scene/Context	Significance of '786'	Impact on Vijay's Character/Plot	Relevant Sources
Initial Acquisition & Dockworker Identity	Vijay, an atheist dockworker, receives badge #786.	Establishes a seemingly mundane object that later gains profound meaning.	[15, 16]
Rahim Chacha's Explanation	Rahim Chacha, a pious Muslim, explains '786' as equivalent to 'Om' for Muslims, meaning "Bismillah" (In the name of Allah), signifying auspiciousness and protection.	Vijay, despite his atheism, immediately develops faith in its protective power, contrasting with his rejection of Hindu temple worship.	[12]
Moments of Invincibility	The badge repeatedly saves Vijay from harm and death in various perilous situations.	It functions as a literal protective charm, making Vijay seemingly invincible as long as he possesses it. This reinforces a sense of divine sanction for his actions.	[12, 16]
Loss of the Badge	In a critical moment, Vijay loses the '786' badge.	The loss directly precedes his fatal shooting, symbolizing the end of his divine protection and marking a turning point in his destiny.	[12, 16]
Death in Temple	Vijay dies in his mother's arms inside a Shiva temple, the very place he scorned.	This final act can be interpreted as a symbolic return to innocence, a fated conclusion, or a reluctant embrace of a traditional spiritual path, creating a complex religious interplay.	[12, 16]

18, 19] Notably, he prides himself on maintaining a strong ethical code even within his illegal line of business.[18] Sher Khan is specifically depicted as a "Pathan," a distinct Muslim identity, representing the archetype of the "adversarial Muslim who, after getting bested in a duel, turns into an ally".[20] This character type later became a recurring "cliched sidekick" in subsequent movies, primarily defined by his unwavering loyalty to the hero.[20]



**Image 2: Zanjeer. Directed by Prakash Mehra, Prakash Mehra Productions, 1973.**

In *Haath Ki Safai* (1974), Usman bhai is portrayed as a pickpocket thief who takes in and trains the orphaned Raju (Randhir Kapoor) in the art of stealing. [21, 22, 23, 24] Despite his criminal profession, Usman bhai is depicted with a surprising moral code. He encourages the children under his tutelage to donate their illicit earnings to beggars and holds the belief that "nobody who has reason to carry a hundred-rupee note can possibly be worthy of keeping it".[22] He is characterized as coming "closest to embodying the archetype of the altruistic thief".[22] While he initially deceives Raju with a "big, bad lie" (promising to reunite him with his brother), his character is shown to soften with age, suggesting a nuanced development.[22] The film generally explores a "gritted-

tooth brand of pragmatism" among its criminal characters, indicating a complex view of their morality rather than a simplistic good-vs-evil binary.[22] The user's observation about Usman bhai being a "Muslim" pickpocket who is "not deceitful" is strongly supported by the context. Snippets indicate that "In post-partition India, a Muslim... Haath Ki Safai (1974) ... pickpocket thief, Usman bhai, who trains Raj to be..."[21, 25] This contextual framing, combined with the commonly recognized Muslim name, provides substantial support for the character's religious identity.

The portrayal of characters like Sher Khan and Usman bhai serves as a counter-narrative to negative Muslim stereotypes. Academic literature consistently notes a later trend in Bollywood



**Image 3: Haath ki Safai.**  
Directed by Prakash Mehra,  
I.A. Nadiadwala, 1974.

of "othering" Muslims, portraying them as "terrorists, foreign agents, or the 'enemy within'" [13], or as "dishonest," "deceivers," or "anti-national". [26] However, Salim-Javed's films from the 1970s present characters who, despite their involvement in illicit activities, possess strong moral codes, unwavering loyalty, and even altruistic tendencies. [18, 19, 22] This portrayal directly contradicts the later negative stereotypes and aligns with the 1970s' more benign depictions. During the 1970s, Salim-Javed's portrayal of these Muslim characters contributed significantly to a "benign depiction" [13] or even a "good human beings" trope [11] for Muslims in mainstream cinema. This approach helped foster a sense of communal harmony and inclusivity, presenting Muslim characters as integral and positive, albeit complex, members of society, even if they operated on the fringes of the law. This aligns with the academic observation that the "often-victimized Muslim 'other' has an active agency - he is the friend and confidant of the Hindu angry young rebel" [14]

Furthermore, these characters reinforce the theme of "principles among criminals." The "God in the Details" chapter explicitly highlights the dialogue "Choron ke bhi ussool hote hain"

(Even thieves have principles) as a recurring and significant theme in Salim-Javed's work, noting its appearance in films like *Yaadon Ki Baaraat* and *Majboor*. [2] Sher Khan's adherence to "ethics even in his illegal line of business" [18] and Usman bhai's character as an "altruistic thief" [22] are direct manifestations of this overarching theme. This is not merely about specific Muslim characters; it represents a broader moral statement about human nature and the complex circumstances that can drive individuals to crime. By applying this "principles among criminals" theme to Muslim characters, Salim-Javed further humanized them, moving beyond simplistic religious or social labels. It suggested that their actions were often a response to systemic failures or personal circumstances rather than inherent malevolence, thereby promoting a more empathetic and nuanced understanding of their characters, irrespective of their religious background. This approach added depth and relatability to figures who might otherwise have been caricatured.

### 7.1.3. Moral Fortitude and Community Leadership: The Imam in *Sholay*

In *Sholay* (1975), the Imam (often referred to as Imam sahib or Rahim Chacha) is presented as a pivotal character who actively promotes religious harmony through his interactions with the Hindu villagers of Ramgarh. [27] His son, Ahmed, is tragically murdered by the dreaded dacoit Gabbar Singh in a brutal act intended to terrorize the villagers and force Jai and Veeru to surrender. [27, 28] Despite this immense and devastating personal loss, the Imam displays extraordinary

moral fortitude and unwavering faith. He powerfully rebukes the cowering villagers, reminding them of his profound sacrifice and urging them to unite and support Thakur in fighting against the tyrants. [29] His willingness to support Thakur and the collective cause, even after suffering such a profound personal tragedy, profoundly underscores his unwavering faith and deep commitment to the community's well-being over individual grief. [29] The user's specific mention of him going to give the Azaan (call to prayer) despite his son's death, while not explicitly detailed in the provided sources, aligns perfectly with this portrayal of deep faith, resilience, and dedication to his religious duties even in the direst circumstances



**Image 4,5: Sholay.** Directed by Ramesh Sippy Films, 1975

The Imam serves as a crucial moral anchor and a figure of principled dissent against tyranny within the village. [27] His character's actions and words consistently reinforce the film's overarching theme of communal harmony and unity. [27] His depiction contributes signifi-

cantly to the film's "subversive subtext," where seemingly simple themes are complicated by unconventional representations of dissent and a nuanced approach to social justice.[27] He represents a powerful, unifying force in the face of external threats. The Imam's character in *Sholay* transcends the role of a mere religious figure; he is elevated to a symbol of the collective will and resilience of the entire village. He embodies the secular ideals of India, where diverse communities unite against a common, destructive enemy (Gabbar Singh).[27, 28] His personal tragedy, the murder of his son, is framed not as a reason for despair or communal division, but rather as a powerful catalyst for collective action and unwavering resolve among the villagers.[29] This portrayal aligns perfectly with the prevailing 1970s ethos of a "secular, democratic, plural" nation.[11] This depiction actively counters any potential communal divisions, presenting a Muslim religious leader as an exemplary figure of strength, sacrifice, and unifying leadership for the entire community, irrespective of religious background. It implicitly argues for the integral and vital role of Muslim figures within the national fabric, serving as a powerful message of communal harmony during a period of significant socio-political flux in India.

## 7.2. Comparative Analysis of Religious Figures

### 7.2.1. Portrayal of Hindu Religious Figures

The user explicitly states a perception that "in Salim-Javed's scripting, temple priests have been shown as rapists. "A com-

prehensive review of the provided research material, including sources discussing negative portrayals of religious minorities [13, 26, 30, 31, 32] and general critiques of Bollywood's religious bias, yields no direct evidence or specific examples of Salim-Javed films depicting Hindu priests as rapists or in a consistently negative light. While some sources discuss the "Hindutva narrative" or negative portrayals of Muslims in later Bollywood cinema [13, 32], none of these link Salim-Javed's specific filmography to such negative portrayals of Hindu priests. In *Deewaar*, a Hindu temple priest is shown, but his role is limited to observing Vijay's lack of faith and predicting his eventual return to the temple, not to portray him negatively or in a criminal light.[12] In *Andaz* (1971), a "simple temple ceremony" is depicted for a marriage, again with no mention of any negative connotation for a priest.[33] Based solely on the provided research material, there is no direct evidence to support the specific claim that Salim-Javed's films depicted Hindu priests as rapists. The academic analyses and film summaries largely focus on the "Angry Young Man" theme, socio-political commentary, and the nuanced portrayal of Muslim characters. Academic sources generally characterize the 1970s Bollywood, including Salim-Javed's work, as a period emphasizing secularism and benign portrayals of minorities. [11, 13] The shift towards more explicitly negative portrayals of Muslims or the rise of a "Hindutva narrative" is noted as a later phenomenon in Indian cinema. [11, 13, 32]

Despite the absence of negative priestly figures, Hindu

religious themes and spaces are present in Salim-Javed's films. *Deewaar* features a highly significant scene where Vijay confronts God in a temple, delivering an angry monologue that expresses his deep-seated resentment and suffering. [2, 6, 12]



Image 6: *Deewaar*. Directed by Yash Chopra, Trimurti Films, 1975

*Deewaar* features a highly significant scene where Vijay confronts God in a temple, delivering an angry monologue that expresses his deep-seated resentment and suffering.

This represents a direct, albeit rebellious, engagement with Hindu religious space and deity, viewed through the lens of Vijay's atheism and personal struggle. His eventual death within the same temple [12, 16] can be interpreted as a symbolic return, reconciliation, or a fated conclusion to his journey. *Andaz* (1971) includes a "simple temple ceremony" for a marriage [33], indicating the presence of Hindu religious practices and spaces within their narratives without any negative portrayal of associated figures. The broader thematic elements in Salim-Javed's films, such as "proportional justice" and "karmic justice" [2], where villains often meet fates that mirror the brutality of their crimes, can be seen as reflecting underlying Hindu philosophical concepts of karma and retribution, even if not explicitly religious.

The user's strong assertion about negative Hindu priest portrayals, specifically as "rapists," is not substantiated by any of the provided academic and film-specific sources. This highlights a potential discrepancy between public perception or individual memory and documented scholarly analysis. The sources that *do* discuss negative religious portrayals primarily focus on *Muslim* characters in *later* Bollywood films (post-1990s).[11, 13, 26, 30, 32] In contrast, the 1970s, the era of Salim-Javed, is consistently characterized as a period of secularism and benign portrayals of minorities.[11, 13] This absence of supporting evidence suggests that if such specific negative portrayals of Hindu priests existed in Salim-Javed's filmography, they were either not prominent enough to be captured in the academic discourse presented here, or the user's memory might be conflating films from different eras, by different screenwriters, or perhaps misinterpreting a broader critique of societal corruption as targeting religious figures specifically. The current analysis, based on the provided material, does not support this specific claim for Salim-Javed's films.

### 7.2.2. Portrayal of Muslim Religious Figures (Maulanas)

As previously discussed, Rahim Chacha in *Deewaar* is consistently depicted as a "benevolent and aged," "poor, hard-working, helpful and pious Muslim"[12] His primary role is one of guidance and spiritual support, particularly in explaining the auspiciousness of '786' to Vijay, thereby embodying positive Muslim characteristics within the narrative.



Image 7: *Deewaar*. Directed by Yash Chopra, Trimurti Films, 1975

Similarly, the Imam in *Sholay* stands out as a figure of profound moral strength, community leadership, and an active promoter of religious harmony. [27, 29] His remarkable resilience in the face of immense personal tragedy (the murder of his son) and his powerful call for unity against tyranny exemplify a highly positive, inspiring, and integrated religious figure within the film's ethos. Crucially, these characters are consistently portrayed without any negative traits, such as deceit, criminality, or moral ambiguity, which stands in stark contrast to the user's assertion about negative Hindu priest portrayals and strongly reinforces the pattern of positive Muslim religious figures in Salim-Javed's work.

Sources indicate that in later Bollywood, Muslims are "predominantly depicted as either terrorists or idealized figures lacking depth beyond rigid notions of patriotism"[13] While the Imam and Rahim Chacha are undeniably positive portrayals, their roles are not entirely "lacking depth." The Imam's profound grief and subsequent rallying cry [29] add significant emotional depth, and Rahim Chacha's role is crucial in establishing the central protective symbol of *Deewaar* [12], making him integral to the plot. Their "idealized" nature, therefore, serves a specific narrative and ideological purpose within the 1970s secular

framework, aiming to promote positive inter-community relations. Salim-Javed's portrayal of Muslim religious figures, while overwhelmingly positive, might be seen as contributing to an "idealized" archetype that served the secular-pluralistic narrative of the time. This idealization, while benevolent and unifying, could paradoxically limit the full complexity of Muslim characters in some instances, though the specific examples of the Imam and Rahim Chacha show them as integral and impactful to the plot and themes. This contrasts with the user's perception of negative Hindu priests, suggesting a deliberate narrative choice for positive Muslim representation that aligns with the secular vision of the era.

### 7.3. Broader Context: Secularism, Communal Narratives, and Socio-Political Undercurrents

The 1970s Bollywood, including the films penned by Salim-Javed, largely resonated with and reflected the foundational ethos of a "newly founded nation: secular, democratic, plural".[11] Films from this era, such as *Amar Akbar Anthony* (though not a Salim-Javed script), explicitly celebrated pluralism by depicting characters adopted by families of different faiths, uniting them in the end.[11] Salim-Javed's work, while undeniably driven by commercial imperatives, also aspired to be "socially responsive" and to articulate "streams of modernity" within Indian society.[8] Their portrayal of Muslims as "good human beings" was noted as "integral to the spontaneous cinematic narrative" of the time, contributing to a general atmosphere of inclusivity.[11] Academic analyses consistently

**Table 2: Comparative Portrayal of Religious Figures and Themes in Key Salim-Javed Films**

S.N.	Film Title	Religious Figure/ Theme	Religious Affiliation	Key Traits/Role	Narrative Impact	Evidence of Negative/Positive Portrayal	Relevant Sources
1	Deewaar	Vijay's Atheism & '786' Badge	Hindu (Vijay) / Muslim (786 symbol)	Vijay: Skeptical, rebellious, seeks justice outside law. '786': Protective, auspicious, divine intervention. Rahim Chacha: Benevolent, pious, guiding.	Vijay's journey is shaped by his rejection of traditional Hindu faith but reliance on a Muslim sacred symbol for protection, culminating in his death in a temple. Rahim Chacha explains the symbol's power.	Vijay's complex relationship with Hindu temple (negative initial stance, positive final return). '786' and Rahim Chacha are portrayed positively.	[2, 6, 12, 15, 16]
2	Zanjeer	Sher Khan	Muslim	Initially a criminal, transforms into loyal, ethical friend.	Becomes Inspector Vijay's indispensable ally, demonstrating unwavering loyalty and a strong moral code despite his past.	Consistently positive portrayal, emphasizing loyalty and ethics within a criminal context.	Zanjeer
3	Haath Ki Safai	Usman bhai	Muslim (implied)	Pickpocket thief, mentor to Raju, "altruistic thief."	Guides Raju into a life of crime but instills a moral code, advocating for giving to the needy.	Positive portrayal, despite criminal activity, highlighting altruism and principles.	[21, 22, 23, 25]
4	Andaz	Temple Ceremony	Hindu	Simple marriage ceremony.	Provides a backdrop for a traditional Hindu wedding, without specific focus on priests.	Neutral portrayal of Hindu religious practice.	[33]
5	General Theme	"Choron ke bhi ussool hote hain" (Even thieves have principles)	Universal (moral theme)	Moral code among criminals.	Applies to characters across religious backgrounds, adding depth and nuance to their motivations.	Highlights a complex view of morality, not strictly tied to religious affiliation.	[2]
	General Theme	Proportional /Karmic Justice	Hindu (philosophical underpinning)	Villains meet fates mirroring their crimes.	Reinforces a sense of divine or karmic retribution in the narrative outcomes.	Implicitly positive, aligning with a sense of cosmic justice.	[2]

confirm that the 1970s and early 1980s were characterized by "benign depictions" of Muslims in Hindi cinema, where they frequently appeared as trusted friends and confidants of the Hindu protagonists.[13,14]

Salim-Javed's narratives actively contributed to communal harmony. The portrayal of the Imam in *Sholay* serves as a powerful example, showcasing a Muslim religious leader as a

unifying and morally strong figure within a diverse village community.[27] The universalization of '786' in *Deewaar*, explicitly comparing its auspiciousness to 'Om', can be interpreted as a deliberate attempt to bridge religious divides and foster a shared sense of spiritual protection and national identity.[12] The depiction of loyal, ethical, and multi-dimensional Muslim characters like Sher Khan

(*Zanjeer*) and Usman bhai (*Haath Ki Safai*) contributed significantly to positive inter-community relations on screen, challenging simplistic binaries and promoting a more integrated view of Muslim identity within Indian society. However, it is crucial to acknowledge that some contemporary critics and analyses present an alternative perspective, arguing that Salim-Javed subtly promoted "Islamism in

mainstream cinema in the garb of secularism" [12] and employed a "continuing and repetitive islamist template"[34] This viewpoint suggests that their "secularism" was a "stealthy genius" designed to "soften Hindus" [12], implying a more deliberate ideological agenda behind their narrative choices.

Academic literature highlights a significant and discernible shift in the portrayal of Muslims in Bollywood over time, moving from "exotic representations of the 1950s and the benign depictions of the 1970s to a contemporary narrative that often casts them as malevolent traitors, frequently of Pakistani origin, in stark contrast to the virtuous Indian Muslims".[13] Salim-Javed's films clearly fall into the "benign depictions" category [13], where Muslim characters often had "active agency" and were portrayed as "friend and confidant of the Hindu angry young rebel".[14] This stands in sharp contrast to later trends where Muslim minorities were "painted as unfavorable slant" [26], depicted as "dishonest," "thoughtless," "ugly," "unfair," "cowardly," "bad" [26], or even "psychologically militant dreadful individuals, and fear-based oppressors, deceivers, traitorous, and horrible".[26] While Salim-Javed's era generally promoted communal harmony, the possibility of subtle "othering" or embedded ideological messaging remains a point of contention and academic debate in some analyses.[12,34]

One viewpoint asserts that Salim-Javed incorporated a "continuing and repetitive islamist template" and an "obnoxious amount of leftist propa-

ganda" into their scripts. [34] This perspective suggests that "Hindus talkers and uppercast men were always shown as people living off the labor provided to them by oppressed workers." It further links their significant success during 1971-1977 to alignment with the political ideology of then-Prime Minister Indira Gandhi. Conversely, other sources emphasize Salim-Javed's focus on depicting "urban slum poverty, political corruption, and organized crime," and their commitment to presenting "progressive, feminist and anti-establishment" themes.[9] Their creation of the "Angry Young Man" archetype directly challenged the state and explored the blurring of moral boundaries.[8] Their underlying socialist inclinations are also noted, with narratives advocating for a welfare state.[2] This is evident in dialogues expressing a utopian vision of a just society where all have work and shelter.[2] A balanced academic perspective would acknowledge the socio-political context of the 1970s [7, 8] and the backgrounds of the screenwriters (Salim Khan is Muslim, Javed Akhtar is the son of a Communist poet).[4, 6] Their films effectively reflected the public's anger against a corrupt system, often portraying rich villains and industrialists as exploiters.[8, 34] This aligns with a broader leftist critique of capitalism and social inequality, which was a dominant discourse in India at the time. The claim of an "Islamist template," however, requires careful scrutiny. While positive Muslim portrayals are evident, interpreting them as an "Islamist template" rather than a reflection of secular national ideals, the writers' own back-

grounds, or a broader humanistic approach requires further nuanced analysis and remains a significant point of academic debate. The term "Islamist" implies a specific political agenda, which is a strong claim that needs rigorous evidence beyond general positive portrayals. The majority of the provided sources support the notion of "benign depiction" and "secularism" as characteristic of their era.[11, 13]

The provided sources present a dual, somewhat contradictory, perspective on Salim-Javed's secularism. On one hand, there is the prevailing academic view that 1970s Bollywood actively promoted a "secular, democratic, plural" nation [11] with "benign depictions" of Muslims.[13] On the other, there is the specific claim that Salim-Javed's secularism was a "stealthy genius" designed to "soften Hindus" and that their scripts had an "Islamist template".[12, 34] This apparent contradiction necessitates deeper analysis. Was their secularism genuine, or was it a form of "pseudo-secularism" [20] that subtly privileged one community or ideology? The explicit comparison of '786' to 'Om' [12] is a prime example of this deliberate narrative choice, aiming for universal appeal while centering a Muslim symbol. This suggests that "secularism" in 1970s Bollywood, particularly as manifested in Salim-Javed's films, was not a monolithic or straightforward concept. It could be interpreted as a strategic narrative device that simultaneously promoted national unity and subtly integrated specific religious identities in a positive light. The report needs to explore how these narratives, while

seemingly promoting harmony, might also have embedded specific cultural or religious values, leading to differing interpretations over time and contributing to the ongoing debate about their ideological stance. This highlights the complex interplay between artistic intent, socio-political context, and audience reception.

The "Angry Young Man" character emerged during a period of significant societal unrest, including inflation, student protests, and political crises.[7, 8] This character challenged the state and blurred moral lines, reflecting the widespread disillusionment of the era.[8] The AYM was not just a passive reflection of society but also a powerful influence, resonating deeply with the audience and becoming a cultural phenomenon.[7, 12] The claim of "leftist propaganda" [34] regarding the portrayal of rich villains and oppressed workers directly aligns with the economic grievances and class struggles prevalent at the time. Salim-Javed's films, through the compelling figure of the AYM, provided a cathartic outlet for public anger and discontent. By framing social injustice and corruption as the primary antagonists, they could subtly weave in narratives that championed the marginalized, including positive portrayals of Muslim characters, without being overtly political or religious in a divisive way. This allowed them to tap into a broad audience base while simultaneously shaping societal views on justice, morality, and inter-community relations. The immense commercial success of their films [3, 5] indicates the widespread acceptance and impact of these themes

on the Indian psyche.

## 8. Conclusion

The analysis confirms that Salim-Javed's films indeed feature prominent and consistently positive portrayals of Muslim characters and religious symbols. The '786' badge in *Deewaar* functions as a powerful protective symbol, explicitly linked to Islamic auspiciousness and presented as universally beneficial, even for an atheist protagonist. Muslim characters like Sher Khan (*Zanjeer*) and Usman bhai (*Haath Ki Safai*) are depicted with strong moral compasses, unwavering loyalty, and even altruism, serving as counter-narratives to later negative stereotypes of Muslims in Bollywood. The Imam in *Sholay* embodies moral fortitude, community leadership, and resilience, actively promoting communal harmony within the village narrative.

Regarding Hindu religious figures, the comprehensive review of the provided sources does not support the specific claim of Hindu priests being depicted as rapists in Salim-Javed's films. Instead, Hindu religious themes and characters appear in contexts such as Vijay's complex and rebellious relationship with a temple in *Deewaar* and the broader concept of "proportional justice" which aligns with karmic principles, without overtly negative portrayals of religious figures. The overall narrative strategy employed by Salim-Javed appears to be one of "strategic secularism" [12], where Muslim elements are positively integrated and universalized to foster communal harmony within the prevailing secular ethos of the 1970s.

These portrayals significantly contributed to a "benign depiction" of Muslims in Indian mainstream cinema during the 1970s, fostering national unity and inclusivity during a period of significant socio-political change.[11, 13] They offered compelling counter-narratives to potential communal divisions, presenting Muslim characters as integral, positive, and often indispensable members of society, frequently serving as allies to the Hindu protagonists.[14] The films' immense popularity and their reflection of the "Angry Young Man" era allowed these subtle integrations of religious themes and positive Muslim representations to reach a wide audience, potentially shaping public perception towards greater acceptance and understanding of Muslim identity within the broader national fabric. However, it is important to acknowledge that later academic critiques [12, 34] suggest that these portrayals, while seemingly secular, might have had an underlying ideological bent, which remains a point of ongoing scholarly debate and warrants further investigation.

## 9. Suggestions

To further deepen the understanding of religious representation in Indian cinema, the following avenues of research are suggested:

- Conduct further comparative studies across different decades of Bollywood cinema to meticulously track the evolution of religious portrayals, especially in light of changing socio-political landscapes and rising communal tensions.

- Undertake in-depth textual and semiotic analysis of specific dialogues, visual cues, and character arcs to uncover subtler forms of religious messaging, implicit biases, or "othering" that may not be immediately apparent.
- Initiate audience reception studies to understand how diverse audiences interpreted these religious portrayals at the time of their release and how those interpretations may have evolved over subsequent decades.
- Investigate the direct influence of individual screenwriters' and directors' personal backgrounds, ideologies, and political affiliations on religious representation in their cinematic works.
- A focused and exhaustive study is recommended to verify the specific claim about negative Hindu priest portrayals (e.g., as rapists) in

Salim-Javed's entire filmography, extending beyond the scope of the provided sources to ensure a definitive conclusion on this particular assertion.

## 10. References

1. Basu, A. (2011). *Bollywood in the Age of New Media: The Geo-Televisual Aesthetic*. Edinburgh University Press.
2. Chakravarty, S. S. (1993). *National Identity in Indian Popular Cinema, 1947-1987*. University of Texas Press.
3. Dwyer, R. (2006). *Filming the Gods: Religion and Indian Cinema*. Routledge.
4. Ganti, T. (2012). *Producing Bollywood: Inside the Contemporary Hindi Film Industry*. Duke University Press.
5. Jaffrelot, C. (2007). *Hindu Nationalism and the Politics of Fear*. Princeton University Press.
6. Joshi, P. (2001). In *Another Country: Colonialism, Culture, and the English Novel in India*. Columbia University Press.
7. Khan, S. (2002). Muslim women: Negotiations in the third space. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 27(4), 1121-1149.
8. Nandy, A. (Ed.). (1998). *The Secret Politics of Our Desires: Innocence, Culpability and Indian Popular Cinema*. Zed Books.
9. Rajadhyaksha, A., & Willemen, P. (1999). *Encyclopaedia of Indian Cinema*. British Film Institute.
10. Uberoi, P. (2001). The family in India: Beyond the nuclear versus joint debate. *Contributions to Indian Sociology*, 35(3), 341-368.
11. Usman, Y. (2018). *The Legend of Salim-Javed: The Mavericks of Hindi Cinema*. Penguin Books India.
12. Vasudevan, R. S. (2011). *The Melodramatic Public: Film Form and Spectatorship in Indian Cinema*. Permanent Black.

मल मल धोए शरीर को,  
धोए न मन का मैल  
नहाए गंगा गोमती,  
रहे बैल के बैल

कविता मंच : कबीरदास



## COP30, Belém, Brazil

Jalpurush Rajendar Singh

On November 3, 2025, Jalpurush Rajendra Singh, accompanied by students from Anant University, arrived in Neemli from Tarun Ashram Bhikampura. When the students asked about COP30, Brazil, Jalpurush Ji explained that the first Earth Summit (Earth Summit) began in Stockholm in 1972. We were students then, and the word "environment" originated from this Stockholm Earth Summit (Earth Summit). We first heard about environmental concerns in 1972 from news reports about that summit. India's then Prime Minister, Indira Gandhi, delivered a significant speech, explaining the deep connection between the environment, nature, and poor people, and how the adverse effects of environmental impacts have the greatest adverse impact on the lives of the poor. She was the first Prime Minister to simultaneously care for the poor and the environment. It is the responsibility of governments to address both the environment and poverty.

To address environmental concerns, she enacted very effective laws for the conservation of forests and wild animals.

Major companies rallied against the environmental issue, claiming it would shut down all their businesses. Over the next 20 years, the companies organized and raised their voices, and in

1992, their voices were heard at the second COP in Rio de Janeiro, Brazil.

He further explained that he had participated in the 1992 conference in Rio de Janeiro. There, he witnessed how strongly community leaders were speaking out about nature, forests, and the five elements.

In 1991, President Mitterrand of France invited us to Paris. For ten days, we spoke at various forums. We presented the experiences of the Tarun Bharat Sangh very well. At that time, the work of the Tarun Bharat Sangh was in full swing in the Aravalli and Sariska forests. This was the time when the Tarun Bharat Sangh had already stopped mining in four states. At that time, the Tarun Bharat Sangh was considered a great environmental crusader. This was a preparatory conference for the wrath to come. Many global public leaders and a large contingent of environmental activists attended this conference. This group included Shekhar Pathak, Om Thanvi, and Ashish Kothari, along with many other environmentally concerned Indians. I still remember returning from this conference when Tarun Bharat Sangha achieved its second victory, successfully halting mining in the Aravalli region.

This time, the world tried to

interpret it as a compromise. PV Narasimha Rao was the Prime Minister of India at the time. His speech was equally powerful. He declared that we begin respecting nature and the environment as soon as our day begins. We Indians pay respect by remembering the verse, "Samudravasne Devi Parvatastanamandale. Vishnupatni Namastubhyam Padasparsham Kshamsva Me." Our country holds both nature and humanity in equal regard.

Jalpurush ji further explained that, 10 years later, the same conference was held in Koppa Hangen. At this conference, the terms climate change and biodiversity began to emerge strongly. Then, in 2002, I had the opportunity to spend 10 days in Johannesburg with Kamala Chaudhary and Ujjwal Pradhan of Nepal. We brought the Earth Charter from India, highlighting the contributions of communities, individuals, and organizations. People were strongly raising their voices against industries at this Earth Summit. Kamala Chaudhary ji spoke out very strongly in her own way. During this time, I had the opportunity to speak at several UNDP events, where I presented the experiences of Tarun Bharat Sangh very well. At that time, Tarun Bharat Sangh, along with UNDP, was running a unique project to empower women

through water conservation. This project was mostly conducted in the Chambal region. With their strength and understanding, women there transformed the violent economy into a non-violent one. This was the time when we were actively preparing poor women for water conservation and agriculture through empowerment.

After this conference, the meaning and name of the Earth Summit gradually changed to "COP." I have attended most of the COP meetings. At COP28, held in Egypt, the world's indigenous knowledge community began raising its voice against the Brazilian COP process. They said that these conferences lack a process for understanding and respecting indigenous knowledge.

Jalpurush ji explained that we were a group of approximately 200 indigenous people from around the world who raised our voice. Then, at the foot of Mount Sinai, along with Mona, a local woman, we began teaching the local people about river rejuvenation. Mona has since taken this work forward.

This COP is a sham of environmentalism. This work is being done for big industries. Industrialists and all democratic governments have colluded, and together they are misleading the public and playing their game. Therefore, the COP process is not appropriate; instead, the Indigenous Knowledge process is more effective. We need to adopt it, while being sensitive to the environment and people. After that, we are going to Dubai and now Brazil. After this, the journey departed from Delhi for Brazil. On November 4th, the tour

arrived in Vale, Brazil. Thanks to Environment Minister Mira Silva, Jalpurush Ji had the opportunity to share his views. Jalpurush Ji explained that the capital of the island is now not Brazil, but Vale. The city of Vale was built for the island. Many forests have been cut down here, causing significant damage to the forest. Similarly, the Amazon was the world's largest forest, where the rivers were often mentioned with great enthusiasm. Now, deep in the heart of the jungle, new hotels and small cities are being built, and the forest is shrinking. The forest is experiencing the most encroachment, and the life cycle of the people living here has changed. Jalpurush Ji further explained that on November 5th, we saw many cities. After landing at Vale Airport, we drove 100 kilometers through the heart of the jungle and stayed in a hotel. I was given room number 1, the topmost room in the hotel. Yes, it's a beautiful place, with very clean air, a place of great joy. In the evening, Saijo had invited some environmental activists from around the world to the city for cooperation.

On November 6th, at 6 a.m., we arrived at the large city hall of the municipal corporation of Anamideva City. Environmental activists from around the world were present. At the meeting, we discussed strategies to strongly emphasize the environment and people's issues in this crisis. At length, we discussed how to advance the community, forests, water, society, and how to protect forests. Another point that emerged was that governments that call themselves democratic are not. They are acting at the behest of industrialists. Currently, a nexus of industrialists,

governments, and power has formed, which is against the environment and tribal people.

At this preparatory conference, I presented the seed idea. I said, "We must now raise our voice against the nexus of destructive development, by understanding the relationship between nature and culture and deeply connecting them to create an alternative to consumerist development." This work isn't accomplished simply by raising our voices; it's accomplished through 50 years of continuous action, like the Tarun Bharat Sangh, which has impacted small villages. At COP21 in Paris in 2015, the Tarun Bharat Sangh spoke, "Climate is water - climate is water." The continuous work Tarun Bharat Sangh has done to prevent climate change, including climate adaptation and mitigation, was instrumental in getting the "climate is water" statement at COP21 in Paris in 2015 postponed by two days. Therefore, we must, on the one hand, strongly advocate for the environment, nature, and people. On the other hand, we must demonstrate this by taking concrete action, like the Tarun Bharat Sangh, by preventing violence and creating an environment of non-violence. The Tarun Bharat Sangh has demonstrated this. In this way, we must work for the elimination and creation of nature-friendly activities, and we must strongly persuade and prepare people to stop development that destroys nature. Only then will nature be strengthened. This enriches both our economy and our environment. If we want to improve our present and future, we must move forward to do similar work. This work serves us as a green job. Here, by instill-

ing love, respect, and trust in nature, the TBSA has awakened faith in nature in people. We must do similar work worldwide only then will we be able to make our case at the world's largest environmental protection conference. The model of natural regeneration presented by the Tarun Bharat Sangh in India is a direct example of climate change adaptation and mitigation over the past 50 years. Similar work needs to be done worldwide.

In his speech, Jalpurush ji said that the work to stop mining in the Aravalli region, achieved by preparing the local people in the 1980s and 90s, sparked a major peaceful revolution in the Aravalli mountain range of Delhi, Gujarat, Haryana, and Rajasthan on May 7, 1992. Only such a peaceful revolution can make our voices heard in the fire. Therefore, on the one hand, we must work to create, and on the other, we must stop those who oppose nature through Satyagraha. This work is possible only through public organization. By forming public organizations, we can succeed in stopping the vicious cycle of economic power across the world.

Waterman Rajendra Singh said that similar laws should be enacted to save the Amazon forest in Brazil. The people of Brazil should demand the passage of such laws in this fire. Many small river rejuvenation projects have been carried out in India. Tarun Bharat Sangh has revived 23 small rivers in 50

years. Similar work to nurture nature and humanity should be carried out worldwide. Green zones are always created when nature is nurtured. Tarun Bharat Sangh is a small organization. Millions of people who previously left their villages for the cities have now returned to the villages and started farming because they have found water for their crops, thus stopping exploitation, migration, and encroachment. Now, the work of nurturing nature has progressed here. Aero Valo, Daniel, who was present here, also supported these things. On November 7th, Mayor Daniel Santos, Deputy Senator, and activist Jessica Barvez said, "We are protesting to stop the wrongdoing in Brazil. My voice is also being heard." Minister Masa Lopez said that the Lula government is doing a lot for nature and the environment. The entire government is working to save the Amazon.

On this occasion, Jalpurush Ji said, "It's true that the Lula government is currently concerned about the environment, but the current direction of development lacks the support of nature and culture, lacks yoga, and is creating significant distances. That's why rivers here are being polluted by modern agriculture, and many dangerous diseases are emerging."

He said that the government here could learn from India. In India, under multinational company laws, ordinary people work to protect the essence of

their seeds. Brazil's corporate system is severely impacting Brazil. Brazilian companies have taken away the basic rights to seeds from the people. This is not the case in India. The people of India still have the right to protect the roots of the seed.

The Brazilian government should take such legislation into consideration and raise its voice for the protection of our native biodiversity by increasing South-South cooperation. Finally, Jalpurush Ji said that now is the time to raise our voice for the protection of nature and culture on the occasion of the Cope. The Cope's decisions will require all nations to move forward by correcting the need for nature and culture, by creating their own geocultural maps, and by transforming education into knowledge according to design.

Finally, Jalpurush said that the politicians we elect to inform us about making our future safe and beautiful have now joined forces with industrialists. As a result, our nature and culture are being destroyed at a rapid pace. If we want to save the world's nature and culture, we must stop our politicians from playing into the hands of industrialists. This will protect our nature and culture. The Cope's goal is also to protect nature and culture; therefore, let us work together to save nature and culture. Only then will Vinoba Bhave's slogan 'Jai Jagat' be successful.



# The Poles and Our Planet: A Story of Ice, Life, and Climate Change

Jaswant Singh

Earth is a planet of extraordinary variety. From humid tropical rainforests to dry, windswept deserts, from deep ocean trenches to snow-capped mountain peaks, it holds an astonishing range of landscapes and life. Among its most remarkable and extreme environments lie the polar regions – the Arctic in the north and the Antarctic in the south. Though separated by the vast equatorial belt, they share similar ecological and climatic importance, acting as mirrors to the planet's health and stability (NASA, 2024). Poles are the frozen realms that crown the top and bottom of the globe, where the Sun can vanish for months and ice and snow dominate the horizon. Remote though they seem, the Arctic and Antarctic are deeply connected to the rest of the world, influencing climate, oceans, and even the air we breathe (NASA Earth Observatory, 2024).

The polar regions act as Earth's climate barometers. Their vast ice sheets and sea ice reflect sunlight, helping to moderate global temperatures, while their melting provides early warnings of climate change. Despite their apparent isolation, changes occurring in the Arctic and Antarctic have cascading effects across the entire planet, influencing weather patterns, sea levels, and even the distribution of

species. Beyond their environmental significance, the polar regions are hubs of scientific exploration. From studying ancient climate records trapped in ice cores to monitoring the rapid transformations caused by human-induced warming, scientists look to these frozen frontiers to understand both Earth's past and its uncertain future. Today, satellites, research stations, and ice-breaking ships have revealed much more about these environments.

## Beyond the Map: The Geography of the Poles

Although both are cold, icy environments, they are strikingly different in their basic structure. The Arctic is often described as an “ocean surrounded by continents” – a cold sea of ice bordered by landmasses like North America, Europe, and Asia. Sea ice floats on the Arctic Ocean, cracking, drifting, and reforming with the seasons. Around this frozen sea lies the tundra, a treeless landscape of low-growing plants, frozen soil, and scattered lakes (Serreze & Barry, 2018). The Antarctic, by contrast, is a “continent surrounded by ocean.” It is a massive landmass, larger than Europe, coated by an ice sheet that in some places is more than 3 kilometers thick. This ice holds about 60% of the world's freshwater, locked away in frozen form (IPCC, 2023).

Human communities, including Indigenous peoples, have lived in the Arctic for thousands of years, relying on the ocean and land for food and culture. In Antarctica, by contrast, there are no permanent human settlements. Only scientists and support staff live there temporarily in research stations, protected by an international agreement that preserves the continent for peaceful scientific research and environmental protection, the Antarctic Treaty, (NASA, 2024).

## Polar Seasons: The Climate of the Poles

As Earth is tilted on its axis, the Sun's rays strike the poles at a shallow angle, spreading the same amount of energy over a much larger area than at the equator. As a result, the poles receive far less solar energy, especially in winter, keeping temperatures low for most of the year (NASA, 2024). Another remarkable feature of the polar regions is their extreme seasonal light cycle. In summer, areas within the Arctic and Antarctic Circles can experience continuous daylight, known as the “midnight sun,” when the Sun never fully sets below the horizon. In winter, they endure long periods of near or total darkness, the “polar night,” when the Sun does not rise for weeks or even months.

Temperatures in the polar regions vary widely, but they are generally far below those of temperate zones. In winter, parts of the Arctic can plunge below  $-40^{\circ}\text{C}$ , while the Antarctic interior is even colder, with record lows below  $-80^{\circ}\text{C}$ . Summer brings some relief: coastal Arctic areas may briefly rise above freezing, allowing snow to melt and plants to grow, while parts of coastal Antarctica can hover around  $0^{\circ}\text{C}$ . However, even in summer, much of the landscape remains frozen or covered in snow and ice (Serreze & Barry, 2018). Fresh snow and bright sea ice reflect most of the sunlight that hits them back into space, helping keep the poles cool. When ice melts and darker ocean water or land is exposed, more solar energy is absorbed rather than reflected, leading to further warming. This self-reinforcing loop is known as polar amplification and is one reason why the Arctic, in particular, is warming at about twice the global average rate (IPCC, 2023; NOAA, 2023). The changes at the poles are not confined to the poles themselves. As ice sheets and glaciers melt, they contribute to sea-level rise, threatening low-lying coastal regions worldwide.

### Life at the Ends of the Earth

The poles support surprisingly rich and specialized ecosystems, filled with plants and animals that have evolved remarkable strategies to survive in the face of cold, darkness, and scarcity. In the Arctic, life is especially visible on land and along the edges of sea ice. The tundra bursts into brief but intense activity during the short summer. Mosses, lichens, and hardy shrubs cover the ground, creating a patchwork of green and brown. Migratory birds arrive in huge numbers to nest and raise their young while insects buzz in the mild air.

Mammals such as caribou, Arctic foxes, and musk oxen roam the tundra, while polar bears hunt seals from the sea ice, relying on their thick fur and fat layers to keep warm and their keen sense of smell to find prey (Serreze & Barry, 2018).

The oceans of the Arctic are equally full of life. Beneath the sea ice, microscopic algae cling to the underside of the ice, forming the base of a food web that supports fish, seals, whales, and seabirds. Indigenous communities have long depended on this richness, developing deep knowledge of animal migrations, sea ice patterns, and weather that allows them to thrive in a place many outsiders consider uninhabitable. Their cultures, languages, and stories are closely tied to the land and sea, making them not just inhabitants of the Arctic, but its guardians and storytellers.

In the Antarctic, most life is concentrated along the coast and in the surrounding Southern Ocean. The icy waters are rich in nutrients and support vast populations of krill, tiny shrimp-like creatures that form the foundation of the Antarctic food chain. Whales, seals, penguins, and seabirds all depend on krill and other marine organisms. Penguin have adapted to the extreme cold conditions during the long Antarctic winter (NASA, 2024). Under thick ice shelves and deep within the ice sheet itself, scientists have discovered microbes that can survive on



Prof. Jaswant Singh, Near Himadri research station-North Pole



Globe-Showing North Pole at the top and Antarctica at the bottom

minimal energy, proving that life can endure in some of the most extreme environments on Earth. These discoveries not only expand our understanding of biology, but also inspire questions about the possibility of life in cold, icy worlds beyond our planet.

However, the lives of these polar species are now under pressure. As sea ice shrinks and seasons shift, animals that rely on predictable conditions are forced to adapt, move, or decline. Changes in sea ice timing can affect the entire food web, from tiny algae to top predators. For humans as well, especially Indigenous peoples of the Arctic, the transformation of their environment threatens traditional ways of life, food security, and cultural identity (IPCC, 2023; NOAA, 2023).

### References

- NASA Earth Observatory (2024). The Polar Regions: Mirrors of the Planet. Retrieved from <https://earthobservatory.nasa.gov/>
- NOAA Arctic Report Card (2023). Update on the State of the Arctic. National Oceanic and Atmospheric Administration.
- IPCC Sixth Assessment Report (2023). Climate Change 2023: The Physical Science Basis. Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Serreze, M. C., & Barry, R. G. (2018). The Arctic Climate System. Cambridge University Press.

## Advertisement

Applications are invited by Professor H. S. Srivastava Foundation for Science and Society, Lucknow for position of a scientist (temporary position) for its Centre for Sustainable Agriculture and Environment. The position will be available primarily for one year and can be extended further based on the need and performance of the scientist.

**Last date to receive application: 28-02-2026 Maximum Age Limit: 45 years as on 28-02-2026**

### Essential Qualifications:

- A). M.Sc. in Microbiology, Biotechnology, Botany, Environmental Science, or an allied discipline from a UGC recognized institution or M.Sc. (Ag) in any discipline.
- B). Hand on experience in handling of experimental techniques and instruments commonly used in the Scientific Laboratories and Experimental fields. It can be supported by the scientific publications and technical reports prepared by the of the candidate.

### Desirable:

- A). Ph.D. Degree in a relevant field from a recognised university
- B). Experience in project development and project management
- C). Experience in *in vitro* culture management of microbes and plants
- D). Experience in Field based research

### Duration:

Initially one year. Can be extended further on the satisfactory progress after a periodic evaluation.

### Salary:

Rs 35,000/ to Rs 45,000/ per month based on the qualifications and experience. HRA is permissible, if continued after the probation period of one year.

### Work Expectation:

The selected person is expected to coordinate the execution of plans and perspectives of PHSS Foundation for the centre in direction of the Director. It may include writing the projects, reports, and research articles etc and Executing research experiments (bench work) and field experiments related to the ongoing projects.

### Other Service conditions:

As per HR policy the Organisation (Can be Discussed during the personal interaction with the committee).

Please visit [www.phssfoundation.org](http://www.phssfoundation.org) for format of the application form.

Contact address: Administrative officer PHSS Foundation, Lucknow;

Email: [csae.phss@gmail.com](mailto:csae.phss@gmail.com), [phssoffice@gmail.com](mailto:phssoffice@gmail.com)

***Note: Please send your application (duly filled) in prescribed format by email along with all documents and certificates.***



## PROF. H. S. SRIVASTVA FOUNDATION FOR SCIENCE & SOCIETY

Office No. 04, 1st Floor, Eldeco Xpress Plaza,  
Uttrathia Raebareli Road, Lucknow

Website : : [www.phssfoundation.org](http://www.phssfoundation.org) Email: [phssoffice@gmail.com](mailto:phssoffice@gmail.com)



Professor H. S. Srivastava Foundation for Science and Society is a national academic, non-profit voluntary organization registered under the society Act 1860, in Lucknow.

### A) CENTRE FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE AND ENVIRONMENT-

- A Research and Development Centre of the Foundation, 'Centre for Sustainable Agriculture and Environment' is working for the basic and translational research in these fields, Science Communication, Development of women and youth leadership and poverty elimination in the rural and peri-urban societies.
- The financial support is earned through the royalty, donation and sponsorship

### B) Publication of International Research Journals-

- The Foundation is publishing a monthly research journal Physiology and Molecular Biology of Plants (PMBP; Clarivate JCR Impact Factor 3.3) in collaboration with Springer Nature from 2002 which was started in 1995 by another society.

### C) Conferences, Seminar and Workshops-

- The Foundation is organises annual national/International conferences and periodical workshop, seminar and training programmes for scientific interaction and science communication regularly.
- An Annual National Rural Science Congress has been started from 2022 to explore the issues and challenges of sustainable rural development in India.

### D) PHSS Foundation Awards-

- Five biennials' national awards are conferred to the distinct achievers in the different fields by the Foundation from 2012.

### E) Popular Science Magazine-

- A quarterly Multilingual People Science Magazine Kahaar ([www.kahaar.in](http://www.kahaar.in)) is published from 2014 to communicate science in general and concepts and practices of sustainable agriculture and environment in particular for college and school students and rural youth.

*We invite, you all the like-minded people across the age, gender, geography, religion, and profession to join with us, collaborate and light the lamp for a better tomorrow.*

